रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-221 REGISTERED NO. D.-221



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2— अनुभाग 1क PART II — Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 4 No. 4 नई दिल्ली, गुरुवार, 10 नवम्बर, 2016/19 कार्तिक, 1938 (शक) NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2016/KARTIKA 19, 1938 (SAKA) खंड LII VOL. LII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2016/19 कार्तिक, 1938 (शक)

दि इंश्योरेंश लाज़ (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2015; (2) दि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज (सेलरिज एंड कंडिशन्स आफ सर्विस) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2016; (3) दि रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 2016; (4) दि एप्रोप्रिएशन ऐक्ट्स (रिपील) ऐक्ट, 2016; (5) दि रिपीलिंग एंड अमेंडिंग ऐक्ट, 2016; (6) दि मांइस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2016; (7) दि इंडियन ट्रस्ट्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016; (8) दि लोकपाल एंड लोकायुक्ताज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016; (9) दि इंडियन मेडिकल काउंसिल (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016; (10) दि इन्स्टीट्यूट्स आफ टेक्नालाजी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016; (11) दि नेशनल इंस्टीट्यूट्स आफ टेक्नालाजी, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016; (12) दि सेंट्रल एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016 और (13) दि टैक्सेशन लाज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016 के निम्नलिखत हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाट समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, November 10, 2016/Kartika 19, 1938 (Saka)

The translation in Hindi of the following, namely:—The Insurance Laws (Amendment) Act, 2015; (2) The High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2016; (3) The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016; (4) The Appropriation Acts (Repeal) Act 2016; (5) The Repealing and Amending Act, 2016; (6) The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2016; (7) The Indian Trusts (Amendment) Act, 2016; (8) The Lokpal and Lokayuktas (Amendment) Act, 2016; (9) The Indian Medical Council (Amendment) Act, 2016; (10) The Institutes of Technology (Amendment) Act, 2016; (11) The National Institutes of Technology, Science Education and Research (Amendment) Act, 2016; (12) The Central Agricultural University (Amendment) Act, 2016; and (13) The Taxation Laws (Amendment) Act, 2016 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

	पृष्ठ
बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 5)	249
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 13)	293
भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 16) The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016	299
विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 22)	337
निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 23)	361
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 25) The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2016	375
भारतीय न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 34)	377
लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 37) The Lokpal and Lokayuktas (Amendment) Act, 2016	379
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 39) The Indian Medical Council (Amendment) Act, 2016	381
प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 41)	383
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 42)	387
केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 27) The Central Agricultural University (Amendment) Act, 2016	389
कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 47)	391

बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 5)

[20 मार्च, 2015]

बीमा अधिनियम, 1938 और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात्:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 26 दिसंबर, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अध्याय 2

बीमा अधिनियम, 1938 का संशोधन

कितपय पदों के प्रतिनिर्देशों के स्थान पर कितपय अन्य पदों का प्रतिस्थापन। 2. बीमा अधिनियम, 1938 में (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् बीमा अधिनियम कहा गया है), पूरे 1938 का 4 अधिनियम में—

(क) ''इंडियन कंपनीज ऐक्ट, 1913'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, 1913 का 7 ''कंपनी अधिनियम, 2013'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) ''कंपनी अधिनियम, 1956'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, ''कंपनी 1956 का 1 अधिनियम, 2013'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 2 का संशोधन।

- 3. बीमा अधिनियम की धारा 2 में.-
 - (i) खंड (1) और खंड (1क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थातु:—
 - '(1) ''बीमांकक'' से बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा 2 की उपधारा (1) के 2006 का 35 खंड (क) में यथापरिभाषित कोई बीमांकक अभिप्रेत है;
 - (1क) ''प्राधिकरण'' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की 1999 का 41 धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है:':
 - (ii) खंड (5क) का लोप किया जाएगा;
 - (iii) खंड (6ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 - '(6ग) ''स्वास्थ्य बीमा कारबार'' से उन संविदाओं को प्रभावी करना अभिप्रेत है, जो रुग्णता फायदे या चिकित्सा, शल्यचिकित्सा या अस्पताल खर्चे संबंधी, चाहे आंतरिक रोगी या बाह्य रोगी, फायदे, यात्रा रक्षावरण और व्यक्तिगत दुर्घटनावरण उपलब्ध कराते हैं; ';
 - (iv) खंड (7क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
 - '(7क) ''भारतीय बीमा कंपनी'' से कोई बीमाकर्ता अभिप्रेत है, जो ऐसी कंपनी है, जो शेयरों द्वारा सीमित है. और.—
 - (क) जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन किसी पब्लिक कंपनी के रूप में बनाया 2013 का 18 और रजिस्ट्रीकृत किया गया है या बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ के एक वर्ष के भीतर ऐसी कंपनी में संपरिवर्तित किया गया है:
 - (ख) जिसमें विदेशी विनिधानकर्ताओं द्वारा, जिनके अन्तर्गत पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता भी हैं, साधारण शेयरों की कुल धृतियां ऐसी भारतीय बीमा कंपनी की, ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, भारतीय के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन है, समादत्त साधारण पूंजी के उनचास प्रतिशत से अधिक नहीं है।

स्पष्टीकरण — इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए ''नियंत्रण'' पद के अन्तर्गत अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने अथवा प्रबंधन या नीति विषयक विनिश्चयों, जिसके अंतर्गत उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारकों के करार या मत देने के करार भी हैं, को नियंत्रित करने का अधिकार भी हैं;

- (ग) जिसका एकमात्र प्रयोजन जीवन बीमा कारबार या साधारण बीमा कारबार या पुनर्बीमा कारबार या स्वास्थ्य बीमा कारबार करना है;';
- (v) खंड (8) का लोप किया जाएगा;
- (vi) खंड (8क) में,—
 - (I) उपखंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थातु:—

- ''(ख) जीवन बीमा कारबार, साधारण बीमा कारबार या स्वास्थ्य बीमा कारबार की दशा में जिनके पास एक सौ करोड़ रुपए की न्यूनतम समादत्त पूंजी है;'',
- (II) उपखंड (घ) में, ''साधारण बीमा कारबार'' शब्दों के पश्चात् ''या स्वास्थ्य बीमा कारबार'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (vii) खंड (9) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातु:-
 - '(9) ''बीमाकर्ता'' से.—
 - (क) कोई भारतीय बीमा कंपनी, या
 - (ख) बीमा कारबार करने के लिए संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित कोई कानुनी निकाय, या
 - (ग) कोई बीमा सहकारी सोसाइटी, या
 - (घ) भारत में स्थापित शाखा के माध्यम से पुनर्बीमा कारबार में लगी कोई विदेशी कंपनी,

अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, ''विदेशी कंपनी'' पद से भारत के बाहर किसी देश की विधि के अधीन स्थापित या निगमित कोई कंपनी या निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत लॉयड अधिनियम, 1871 (यूनाइटेड किंगडम) के अधीन स्थापित लॉयड सोसाइटी और उसका कोई सदस्य भी है;';

- (viii) खंड (10) में, ''धारा 42 के अधीन अनुज्ञप्त'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;
- (ix) खंड (11) के उपखंड (ग) में, ''वार्षिकियां प्रदान करना, जो ऐसी किसी निधि में से देय है'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे फायदे प्रदान करना, जो ऐसी किसी निधि में से देय है'',शब्द रखे जाएंगे;
 - (x) खंड (12), खंड (13) और खंड (15) का लोप किया जाएगा;

1913 का 7 2013 का 18

- (xi) खंड (16) में, ''इंडियन कंपनीज़ ऐक्ट, 1913 की धारा 2 के खंड (13) और खंड (13क)'' शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर ''कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (68) और खंड (72)'' शब्द, अंक, और कोष्ठक रखे जाएंगे;
 - (xii) खंड (16) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

1999 का 41

1992 का 15

- '(16क) ''विनियम'' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विरचित विनियम अभिप्रेत हैं;
- (16ख) पुनर्बीमा से एक बीमाकर्ता के जोखिम के भाग का दूसरे बीमाकर्ता द्वारा, जो पारस्परिक रूप से स्वीकार्य प्रीमियम के लिए जोखिम स्वीकार करता है, बीमा अभिप्रेत है:
- (16ग) ''प्रतिभूति अपील अधिकरण'' से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15ट के अधीन स्थापित प्रतिभूति अपील अधिकरण अभिप्रेत है;';

नई धारा 2गख का अंत:स्थापन।

- (xiii) खंड (17) का लोप किया जाएगा।
- 4. बीमा अधिनियम की धारा २गक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

भारत में संपत्तियों का प्राधिकरण की अनुज्ञा के सिवाय विदेशी बीमाकर्ताओं द्वारा बीमाकृत न किया जाना।

धारा 2ङ का लोप।

धारा 3 का संशोधन। "2गख. (1) कोई व्यक्ति, प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, भारत में किसी संपत्ति या भारत में रिजस्ट्रीकृत किसी पोत या अन्य जलयान या वायुयान के संबंध में ऐसे किसी बीमाकर्ता से बीमे की कोई पालिसी नहीं लेगा या उसका नवीकरण नहीं करेगा, जिसके कारबार का मुख्य स्थान भारत के बाहर है।

- (2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंध का उल्लंघन करेगा तो वह शास्ति का, जो पांच करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।''।
- 5. बीमा अधिनियम की धारा 2ङ का लोप किया जाएगा।
- 6. बीमा अधिनियम की धारा 3 में,-
 - (i) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
 - ''(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी रीति में किया जाएगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज लगे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।'';
- (ii) उपधारा (2क) के खंड (घ) में, ''5, 31क और 32'' अंकों, अक्षर और शब्द के स्थान पर, ''5 और 31क'' अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;
 - (iii) उपधारा (2ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
 - ''(2ग) रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने के प्राधिकरण के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको विनिश्चय की एक प्रति उसके द्वारा प्राप्त की जाती है, तीस दिन के भीतर प्रतिभृति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।'';
 - (iv) उपधारा (2घ) का लोप किया जाएगा;
- (v) उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (5क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—
 - ''(3) किसी ऐसे बीमाकर्ता, जिसका ऐसे व्यक्ति के साथ संयुक्त उद्यम है जिसके कारबार का मुख्य स्थान भारत के बाहर अधिवसित है या धारा 2 के खंड (9) के उपखंड (घ) में यथा परिभाषित किसी बीमाकर्ता की दशा में, प्राधिकरण पहले से किए गए रिजस्ट्रीकरण को, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस देश में, जिसमें ऐसे व्यक्ति को बीमा कारबार करने से उस देश की विधि या प्रथा द्वारा विवर्जित किया गया है, विधारित कर सकेगा।
 - (4) प्राधिकरण, किसी बीमाकर्ता के रिजस्ट्रीकरण को, यथास्थिति, या तो पूर्णतया या जहां तक इसका संबंध बीमा कारबार के किसी विशिष्ट वर्ग से है, निलंबित या रद्द कर सकेगा.—
 - (क) यदि बीमाकर्ता किसी समय, अपनी आस्तियों के मूल्य के उसके दायित्वों की रकम से आधिक्य के संबंध में धारा 64फक के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल उड़ता है। या
 - (ख) यदि बीमाकर्ता परिसमापनाधीन है या उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है: या
 - (ग) यदि बीमाकर्ता का कारबार या कारबार का कोई वर्ग प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना किसी व्यक्ति को अंतरित हो गया है या किसी अन्य बीमाकर्ता के कारबार में अंतरित या उसमें समामेलित हो गया है; या
 - (घ) यदि बीमाकर्ता इस अधिनियम या किसी नियम या किसी विनियम की किसी अपेक्षा अथवा उसके अधीन किए गए आदेश या जारी किए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करता है या उसके उल्लंघन में कार्य करता है; या
 - (ङ) यदि प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने का कारण है कि बीमाकर्ता पर बीमे की किसी पालिसी के अधीन भारत में उद्भूत कोई दावा नियमित न्यायालय में अंतिम निर्णय के पश्चात् तीन मास तक असंदत्त रहता है; या

(च) यदि बीमाकर्ता बीमा कारबार या किसी विहित कारबार से भिन्न कोई कारबार करता है; या

- (छ) यदि बीमाकर्ता बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन प्राधिकरण द्वारा, यथास्थिति, जारी किए गए किसी निदेश या किए गए आदेश का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करता है; या
- (ज) यदि बीमाकर्ता, कंपनी अधिनियम, 2013 या साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करता है या उसके उल्लंघन में कार्य करता है; या
- (झ) यदि बीमाकर्ता धारा 3क के अधीन अपेक्षित वार्षिक फीस का संदाय करने में असफल रहता है; या
- (ञ) यदि बीमाकर्ता को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है: या
- (ट) यदि बीमाकर्ता, जो, यथास्थिति, सुसंगत राज्य विधियों या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन गठित सहकारी सोसाइटी है, बीमाकर्ता को लागू होने वाली विधि के उपबंधों का उल्लंघन करता है।
- (5) जब प्राधिकरण उपधारा (4) के खंड (क), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ) या खंड (झ) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर देता है, तब वह बीमाकर्ता को अपने विनिश्चय की लिखित में सूचना देगा और विनिश्चय उस तारीख को, जिसे वह उस निमित्त सूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रभावी होगा; ऐसी तारीख उस तारीख से जिसको पारेषण के सामान्य अनुक्रम में सुचना की प्राप्ति होती है, एक मास से कम या दो मास से अधिक की नहीं होगी।
- (5क) जब प्राधिकरण उपधारा (4) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (ञ) या खंड (ट) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर देता है तब, यथास्थिति, निलंबन या रहकरण, उस तारीख को प्रभावी होगा जिसको निलंबन या रहकरण के आदेश की सचना की बीमाकर्ता को तामील की जाती है।''।
- (vi) उपधारा (5ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
- ''(5ग) जहां उपधारा (4) के खंड (क), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ) या खंड (झ) के अधीन कोई रिजस्ट्रीकरण निलंबित या रद्द कर दिया जाता है, वहां प्राधिकरण, स्वविवेकानुसार रजिस्ट्रीकरण को पुन: प्रवर्तित कर सकेगा, यदि बीमाकर्ता उस तारीख से, जिसको निलंबन या रद्दकरण प्रभावी होता है, छह मास के भीतर अपनी आस्तियों के मूल्य के अपने दायित्वों की रकम से आधिक्य के संबंध में धारा 64फक के उपबंधों का अनुपालन कर देता है या वह धारा 3क की उपधारा (4) के अधीन किया गया आवेदन स्वीकार करा लेता है या वह प्राधिकरण का यह समाधान कर देता है कि उस पर कोई ऐसा दावा, जो उपधारा (4) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट है, असंदत्त नहीं रहा है या यह कि उसने इस अधिनियम या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी विनियम की किसी अपेक्षा या किए गए किसी आदेश अथवा उन अधिनियमों के अधीन जारी किए गए किसी निदेश का अनुपालन कर दिया है या यह कि उसने, यथास्थिति, बीमा कारबार या किसी विहित कारबार से भिन्न कोई कारबार करना बंद कर दिया है और वह ऐसे किन्हीं निदेशों का, जो प्राधिकरण द्वारा उसे दिए जाएं, अनुपालन करता है।''।
- 7. बीमा अधिनियम की धारा 3क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 3क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। बीमाकर्ता द्वारा वार्षिक फीस का संदाय।

- ''3क. (1) ऐसा कोई बीमाकर्ता, जिसे धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, प्राधिकरण को ऐसी वार्षिक फीस का, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय करेगा।
- (2) वार्षिक फीस जमा करने में कोई असफलता रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द किए जाने के लिए दायी बनाएगी।''।

1999 का 41

2013 का 18 1972 का 57 1999 का 42

2003 का 15

2002 का 39

धारा ४ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। जीवन बीमा पालिसियों द्वारा प्रतिभूत वार्षिकयों और अन्य प्रसुविधाओं के लिए न्यूनतम सीमाएं। धारा 5 का संशोधन।

धारा 6 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। पूंजी के संबंध में अपेक्षा।

- 8. बीमा अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:--
- "4. बीमाकर्ता, जारी की गई किसी जीवन बीमा पालिसी या किसी समूह पालिसी पर ऐसी न्यूनतम वार्षिकी और अन्य फायदों का संदाय करेगा या संदाय करने का वचन देगा, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, जिसके अंतर्गत कोई लाभ या बोनस नहीं है, परंतु यह किसी बीमाकर्ता को, किसी पालिसी को किसी मूल्य की समादत्त पालिसी में संपरिवर्तित करने से या किसी रकम के अभ्यर्पण मूल्य का संदाय निवारित नहीं करेगी।"।
- 9. बीमा अधिनियम की धारा 5 में.—
 - (i) उपधारा (2) में, दोनों परंतुकों का लोप किया जाएगा;
 - (ii) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।
- 10. बीमा अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
- ''6. (1) ऐसा कोई बीमाकर्ता, जो धारा 2 के खण्ड (9) के उपखण्ड (घ) में यथापरिभाषित कोई बीमाकर्ता नहीं है, जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् भारत में जीवन बीमा, साधारण बीमा, स्वास्थ्य बीमा या पुन: बीमा का कारबार कर रहा है तब तक रिजस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास—

1999 का 41

- (i) जीवन बीमा या साधारण बीमा का कारबार करने वाले किसी व्यक्ति की दशा में, एक अरब रुपए की समादत्त साधारण पूंजी नहीं है; या
- (ii) अनन्य रूप से स्वास्थ्य बीमा का कारबार करने वाले किसी व्यक्ति की दशा में, एक अरब रुपए की समादत्त साधारण पूंजी नहीं है; या
- (iii) किसी पुनर्बीमाकर्ता के रूप में अनन्य रूप से कारबार करने वाले किसी व्यक्ति की दशा में, दो अरब रुपए की समादत्त साधारण पूंजी नहीं है:

परंतु बीमाकर्ता, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और उनके अधीन जारी किए गए नियमों, विनियमों या निदेशों और तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य विधियों के उपबंधों के अनुसार इस धारा में यथा उपबंधित समादत्त साधारण पूंजी को बढ़ा सकेगा:

2013 का 18 1992 का 15

परंतु यह और कि समादत्त साधारण पूंजी का अवधारण करने में, किसी बीमाकर्ता की विरचना और उसके रजिस्ट्रीकरण में उपगत ऐसे किन्हीं प्रारंभिक व्ययों को, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, अपवर्जित किया जाएगा।

- (2) धारा 2 के खंड (9) के उपखंड (घ) में यथापरिभाषित कोई बीमाकर्ता तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास पांच हजार करोड़ रुपए से अन्यून की अपनी शुद्ध निधि न हो।''।
- 11. बीमा अधिनियम की धारा 6क में,—
 - (i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
 - ''(1) शेयरों द्वारा परिसीमित कोई भी पब्लिक कंपनी, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय भारत में है, तब तक जीवन बीमा कारबार या साधारण बीमा कारबार या स्वास्थ्य बीमा कारबार या पुनर्बीमा कारबार नहीं करेगी जब तक कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करती है, अर्थात्:—
 - (i) कंपनी की पूंजी ऐसे साधारण शेयरों के रूप में हो, जिनमें से प्रत्येक का एकल अंकित मूल्य है और ऐसी अन्य प्रकार की पूंजी के रूप में होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;
 - (ii) शेयरधारकों के मतदान अधिकार साधारण शेयरों तक निर्बंधित हों:
 - (iii) अधिक से अधिक एक वर्ष की ऐसी अवधि के दौरान के सिवाय, जो शेयरों पर मांगों के संदाय के लिए कंपनी द्वारा अनुज्ञात है, सभी शेयरों की, चाहे वे विद्यमान हों या न हों. समादत्त रकम एक समान है:

धारा 6क का संशोधन। 1950 का 47

परंतु ऐसी किसी पब्लिक कंपनी के संबंध में, जिसने बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1950 के प्रारंभ के पूर्व मामूली शेयरों से भिन्न कोई ऐसे शेयर निर्गमित किए हैं जिनमें से प्रत्येक का एकल अंकित मूल्य है या जिसने ऐसे शेयर निर्गमित किए हैं जिनकी समादत्त रकम उन सब के लिए समान नहीं है, इस उपधारा में विनिर्दिष्ट शर्तें ऐसे प्रारंभ से तीन वर्ष की अविध तक लागू नहीं होंगी।":

- (ii) उपधारा (2) में, ''शेयरों की समादत्त रकम'' शब्दों से पूर्व ''साधारण'' शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा:
 - (iii) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
 - '(4) पूर्वोक्त जैसी कोई पब्लिक कंपनी जो जीवन बीमा कारबार, साधारण और स्वास्थ्य बीमा कारबार तथा पुनर्बीमा कारबार कर रही है—
 - (क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रखे जाने वाले सदस्यों के रिजस्टर के अतिरिक्त शेयरों का एक ऐसा रिजस्टर रखेगी, जिसमें प्रत्येक शेयर के हिताधिकारी स्वामी का नाम, उपजीविका और पता, जिसके अंतर्गत हिताधिकारी स्वामी के संबंध में ऐसी कोई तब्दीली भी है जिसकी घोषणा उसे की गई है, ऐसी घोषणा की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर दर्ज किया जाएगा;
 - (ख) अपने शेयरों का कोई अंतरण तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगी—
 - (i) जब तक कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 56 के उपबंधों का अनुपालन करने के अतिरिक्त, अंतरिती विहित प्ररूप में इस बाबत घोषणा नहीं कर देता है कि वह शेयरों को अपने ही फायदे के लिए या दूसरों की ओर से, चाहे संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से, नामनिर्देशिती के रूप में धारण करने की प्रस्थापना करता है और पश्चात्वर्ती दशा में हिताधिकारी स्वामी या स्वामियों के नाम, उपजीविका और पते नहीं दे देता है और प्रत्येक के फायदाप्रद हित की सीमा व्यक्त नहीं कर देता है;
 - (ii) जहां अंतरण के पश्चात् कंपनी के शेयरों में अंतरिती की कुल समादत्त धृति उसकी समादत्त पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है, वहां जब तक कि ऐसे अंतरण के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त नहीं कर लिया गया है;
 - (iii) जहां किसी व्यष्टि, फर्म, समूह, समूह के संघटकों या उसी प्रबंध के अधीन निगमित निकाय द्वारा संयुक्त रूप से अथवा पृथक् रूप से अंतरित किए जाने के लिए आशयित शेयरों का अभिहित मूल्य बीमाकर्ता की समादत्त साधारण पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक हो जाता है, वहां जब तक कि ऐसे अंतरण के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त नहीं कर लिया गया है।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए ''समूह'' और ''उसी प्रबंध'' पदों के वही अर्थ होंगे, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में क्रमश: उनके हैं।';

- (iv) उपधारा (3), उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (8), उपधारा (9) और उपधारा (10) का लोप किया जाएगा;
 - (v) उपधारा (11) में,—
 - (क) आरंभिक भाग में, ''उपधारा (7), (8) और (9) के उपबंधों को छोड़कर'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा;
 - (ख) खंड (i) में, ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा;
 - (ग) खंड (ii) का लोप किया जाएगा;
 - (घ) स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उपखंड (ग) में, ''प्रबंध अभिकर्ता'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
- 12. बीमा अधिनियम की धारा 6कक का लोप किया जाएगा।
- 13. बीमा अधिनियम की धारा 6ख में.—

2013 का 18

2013 का 18

2003 का 12

धारा 6कक का लोप। धारा 6ख का संशोधन।

- (i) उपधारा (1) में,—
- (क) ''जीवन बीमा'' शब्दों के स्थान पर ''जीवन या साधारण या स्वास्थ्य बीमा या पुनर्बीमा'' शब्द रखे जाएंगे; और
 - (ख) ''केन्द्रीय सरकार'' शब्दों के स्थान पर ''प्राधिकरण'' शब्द रखा जाएगा;
- (ii) उपधारा (2) और उपधारा (3) में, ''उच्च न्यायालय'' शब्दों के स्थान पर, क्रमशः ''प्रतिभृति अपील अधिकरण'' शब्द रखे जाएंगे;
 - (iii) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा।

धारा ६ग, धारा ७, धारा ८ और धारा ९ का लोप। धारा 10 का संशोधन।

- 14. बीमा अधिनियम की धारा 6ग, धारा 7, धारा 8 और धारा 9 का लोप किया जाएगा।
- 15. बीमा अधिनियम की धारा 10 में,-
- (i) उपधारा (1) में ''इस निमित्त विहित किए जाएं'' शब्दों के स्थान पर ''विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं '' शब्द रखे जाएंगे;
 - (ii) उपधारा (2) में,—

(क) ''बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1946 के प्रारंभ से छह मास की समाप्ति के पश्चात्'' 1946 का 6 शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा;

- (ख) ''बीमाकर्ता के देश की विधि के अधीन'' शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (iii) उपधारा (2क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:--
 - ''(2कक) जहां कोई बीमाकर्ता बीमा का कारबार करता है वहां ऐसे बीमा कारबार के प्रत्येक उपवर्ग के संबंध में देय सभी प्राप्तियां एक पृथक् निधि में जमा की जाएंगी या उससे निकाली जाएंगी, उसकी आस्तियां बीमाकर्ता की अन्य आस्तियों से पृथक् और सुभिन्न रखी जाएंगी तथा प्रत्येक बीमाकर्ता प्राधिकरण को ऐसी निधियों के आवश्यक ब्यौरे, जिनकी प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेगा और ऐसी निधियों का इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन जैसा अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञात है, उसके सिवाय प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपयोजन नहीं किया जाएगा।''।
- 16. बीमा अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
- ''11. (1) प्रत्येक बीमाकर्ता बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम 2015 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उसके द्वारा किए गए बीमा कारबार के संबंध में और उसके शेयरधारकों की निधियों के संबंध में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उस वर्ष के संबंध में एक तलनपत्र, लाभ और हानि लेखा, पथक प्राप्तियां और संदाय लेखा आमदनी लेखा, उन विनियमों के अनुसार तैयार करेगा, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (2) प्रत्येक बीमाकर्ता शेयरधारकों और पालिसीधारियों की निधियों से संबंधित पृथक् खाता रखेगा।
- (3) यदि बीमाकर्ता, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथापरिभाषित कोई कंपनी नहीं है तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखे और विवरण बीमाकर्ता द्वारा या किसी कंपनी की दशा में अध्यक्ष, यदि कोई हो और कंपनी के दो निदेशकों तथा प्रधान अधिकारी द्वारा या किसी बीमा सहकारी सोसाइटी की दशा में सोसाइटी के भारसाधक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे तथा उसके साथ उस अविध के दौरान,जिससे ऐसे लेखे और विवरण संबंधित हैं, कारबार के प्रबंध से संबद्ध भारसाधक व्यक्तियों के नाम, वर्णन और उनकी उपजीविका तथा उनके द्वारा धारित निदेशक पद अंतर्विष्ट करते हुए ऐसा विवरण संलग्न होगा तथा उस अवधि के दौरान के कामकाज की एक रिपोर्ट भी होगी।''।

धारा 11 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। लेखा और तुलन- पत्र।

17. बीमा अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 12 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

लेखापरीक्षा।

2013 का 18

''12. ऐसे प्रत्येक बीमाकर्ता की दशा में, उसके द्वारा किए गए सभी बीमा कारबार के संबंध में तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा, आमदनी लेखा तथा लाभ और हानि विनियोग लेखा की लेखा परीक्षा उस दशा को छोड़कर जब उनकी लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन की जाती है, लेखापरीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी और लेखापरीक्षक को सभी ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा करते समय वही शिक्तयां प्राप्त होंगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 147 द्वारा कंपनी लेखापरीक्षकों को प्राप्त हैं और वह उनमें निहित कृत्यों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा उन पर अधिरोपित दायित्व और शास्तियों के अध्यधीन होगा।''।

18. बीमा अधिनियम की धारा 13 में.—

धारा 13 का संशोधन।

- (i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:-
- "(1) जीवन बीमा कारबार करने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार उसके द्वारा किए गए जीवन बीमा कारबार की वित्तीय स्थिति का जिसके अंतर्गत उससे संबंधित उसके दायित्वों का मूल्यांकन भी है किसी बीमांकक द्वारा अन्वेषण कराएगा, तथा ऐसे बीमांकक की रिपोर्ट का सार विनियमों के अनुसार तैयार कराएगा:

परंतु प्राधिकरण किसी विशिष्ट बीमाकर्ता की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे उस तारीख से जिसको पूर्ववर्ती अन्वेषण किया गया था, दो वर्ष के अपश्चात् की तारीख को अन्वेषण कराने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा:

परंतु यह और कि प्रत्येक बीमाकर्ता, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में तैयार की जाने वाली बीमांकक की रिपोर्ट का सार तैयार कराएगा।'':

- (ii) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थातु:—
- ''(4) प्रत्येक ऐसे सार के साथ ऐसे प्ररूप और रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तैयार किया गया एक विवरण उपाबद्ध किया जाएगा:

परंतु यदि उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट अन्वेषण किसी बीमाकर्ता द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है तो विवरण प्रत्येक वर्ष उपाबद्ध करना आवश्यक नहीं होगा, किंतु प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार उसे उपाबद्ध किया जाएगा।'';

- (iii) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी अर्थात्, —
- '(6) जीवन बीमा कारबार से संबंधित इस धारा के उपबंध बीमा कारबार के किसी ऐसे उपवर्ग को भी लागू होंगे जिसे ''प्रकीर्ण बीमा'' वर्ग में सिम्मिलत किया गया है, और प्राधिकरण विनियमों में ऐसे उपांतरणों और परिवर्तनों को, जो बीमा कारबार के किसी उपवर्ग को उनके लागू करने को सुकर बनाने के लिए आवश्यक हों, प्राधिकृत कर सकेगा:

परंतु यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि बीमा कारबार के किसी ऐसे उपवर्ग में किसी बीमाकर्ता द्वारा किए गए संव्यवहारों की संख्या और रकम इतनी कम है कि उसका कालिक अन्वेषण और मूल्यांकन अनावश्यक है तो वह उस बीमाकर्ता को बीमा कारबार के उस उपवर्ग के संबंध मे इस उपधारा के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।'।

19. बीमा अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 14 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

''14. (1) प्रत्येक बीमाकर्ता, उसके द्वारा किए गए सभी संव्यवहारों के संबंध में,—

(क) ऐसी पालिसियों का एक अभिलेख रखेगा, जिसमें बीमाकर्ता द्वारा निर्गमित प्रत्येक पालिसी के संबंध में पालिसीधारी का नाम और पता,पालिसी कराने की तारीख पालिसियों और दावों का अभिलेख।

और ऐसे किसी अंतरण, समनुदेशन या नामनिर्देशन का अभिलेख रखेगा, जिसकी बीमाकर्ता को सूचना है;

- (ख) दावों का एक अभिलेख, जिसमें किए प्रत्येक दावे के साथ दावे की तारीख, दावाकर्ता का नाम और पता तथा वह तारीख जिसको दावा उन्मोचित किया गया था या किसी खारिज किए गए दावे की दशा में खारिज करने की तारीख और उसके आधार रखेगा; और
- (ग) खंड (क) और खंड (ख) के अनुसार पालिसियों और दावों का एक अभिलेख इलैक्ट्रानिक पद्धति सिहत किसी ऐसे प्ररूप में, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, रखेगा ।
- (2) प्रत्येक बीमाकर्ता, उसके द्वारा किए गए सभी कारबार के संबंध में बीमांकित राशि और प्रीमियम के निबंधनानुसार किसी विनिर्दिष्ट अवसीमा से अधिक की पालिसियां इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति और प्ररूप में इलैक्ट्रानिक रूप में जारी करने का प्रयास करेगा।''।

धारा 15 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। विवरणियों का दिया जाना।

- 20. बीमा अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
- "15. (1) धारा 11 या धारा 13 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षित लेखे और विवरण तथा धारा 13 में निर्दिष्ट सार और विवरण मुद्रित किए जाएंगे और उनकी चार प्रतियां प्राधिकरण को उस अविध की समाप्ति से जिससे वे संबंधित हैं, छह मास के भीतर विवरणी के रूप में दी जाएंगी।
- (2) इस प्रकार दी गई चार प्रतियों में से एक प्रति किसी कंपनी की दशा में अध्यक्ष द्वारा और कंपनी के दो निदेशकों और प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और यदि कंपनी का कोई प्रबंध निदेशक है तो उस प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और एक प्रति, यथास्थिति, उस लेखापरीक्षक द्वारा जिसने लेखापरीक्षा की थी, या बीमांकक द्वारा, जिसने मूल्यांकन किया था, हस्ताक्षरित की जाएगी।''।

धारा 16 का लोप।

21. बीमा अधिनियम की धारा 16 का लोप किया जाएगा।

धारा 17 और धारा 17क का लोप। 22. बीमा अधिनियम की धारा 17 और धारा 17क का लोप किया जाएगा।

धारा 20 का संशोधन।

- 23. बीमा अधिनियम की धारा 20 में,-
 - (i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्: —
 - ''(1) प्राधिकरण को दी गई प्रत्येक विवरणी या उसकी अधिप्रमाणित प्रति प्राधिकरण द्वारा रखी जाएगी और निरीक्षण के लिए खुली रहेगी; और कोई व्यक्ति किसी ऐसी विवरणी या उसके किसी भाग की प्रति ऐसी फीस के संदाय पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्राप्त कर सकेगा।'':
 - (ii) उपधारा (2) में, "या धारा 16" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;
- (iii) उपधारा (3) में, ''एक रुपए की'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसी फीस की, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 21 का संशोधन।

- 24. बीमा अधिनियम की धारा 21 में,—
 - (i) उपधारा (1) के खण्ड (घ) में, "या धारा 16" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;
 - (ii) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(2) प्रतिभूति अपील अधिकरण, किसी बीमाकर्ता के आवेदन पर और प्राधिकरण को सुनने के पश्चात्, उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश को रद्द कर सकेगा, या ऐसी विवरणी को प्रतिगृहीत करने का निदेश दे सकेगा, जिसको प्राधिकरण ने प्रतिगृहीत करने से इंकार कर दिया है, यदि बीमाकर्ता अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि परिस्थितियों में प्राधिकरण की कार्रवाई अयुक्तियुक्त थी:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक वह उस तारीख से, जब प्राधिकरण ने आदेश किया है या विवरणी को प्रतिगृहीत करने से इंकार किया है, चार मास की समाप्ति के पूर्व न किया गया हो।''।

25. बीमा अधिनियम की धारा 22 में, —

धारा 22 का संशोधन।

- (i) उपधारा (1) में, ''या धारा 16 की उपधारा (2) में खंड (ग) के अधीन दी गई मूल्यांकन रिपोर्ट की संक्षिप्ति से'' शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर का लोप किया जाएगा;
- (ii) उपधारा (2) में, ''तथा, यथास्थिति, धारा 15 की उपधारा (1) और (2) या धारा 16 की उपधारा (2) के'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर ''तथा धारा 15 की उपधारा (1) और (2) के'' शब्द, अंक और कोष्ठक शब्द रखे जाएंगे।
- 26. बीमा अधिनियम की धारा 27, धारा 27क, धारा 27ख, धारा 27ग और धारा 27घ के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 27, धारा 27क, धारा 27ख, धारा 27ग और धारा 27घ के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

'27. (1) प्रत्येक बीमाकर्ता —

आस्तियों का विनिधान।

- (क)परिपक्व दावों की बाबत भारत में जीवन बीमा पालिसियों के धारकों के प्रति अपने दायित्वों की रकम के: और
- (ख) भारत में अदायगी के लिए परिपक्व हो रही जीवन बीमा की पालिसियों के अधीन दायित्वों को चुकाने के लिए अपेक्षित रकम के,

योग से अन्यून राशि के बराबर आस्तियां उनमें से निम्नलिखित घटाकर—

- (i) उन प्रीमियमों की रकम, जो ऐसी पालिसियों के संबंध में बीमाकर्ता को शोध्य हो चुके हैं किन्तु जिनका संदाय नहीं किया गया है और जिनके संदाय के अनुग्रह दिवस समाप्त नहीं हुए हैं, और
- (ii) उन उधारों के लिए बीमाकर्ता को शोध्य कोई रकम, जो भारत में भुगतान के लिए परिपक्व होने वाली उन जीवन बीमा पालिसियों के अभ्यर्पण मूल्य पर और उसके भीतर अनुदत्त किए गए हैं जो उसके द्वारा या ऐसे बीमाकर्ता द्वारा निर्गमित हैं, जिसका कारबार उसने अर्जित कर लिया है और जिसके संबंध में, उसने दायित्व ग्रहण कर लिया है, निम्नलिखित रीति में विनिहित करेगा और सदैव विनिहित रखेगा, अर्थात:—
 - (क) उक्त राशि का पच्चीस प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में, उक्त राशि के पच्चीस प्रतिशत से अन्यून रकम के बराबर अतिरिक्त राशि सरकारी प्रतिभूतियों में या अन्य अनुमोदित प्रतिभृतियों में; और
 - (ख) अतिशेष किन्हीं अनुमोदित विनिधानों में से किसी में,

जो उसमें विनिर्दिष्ट परिसीमाओं, शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) साधारण बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता की दशा में, आस्तियों का बीस प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में, आस्तियों के दस प्रतिशत से अन्यून के बराबर अतिरिक्त राशि सरकारी प्रतिभूतियों में या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में तथा अतिशेष किसी अन्य ऐसे विनिधान में जो प्राधिकरण के विनियमों के अनुसरण में और ऐसी सीमाओं, शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो इस बाबत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

स्पष्टीकरण — इस धारा में, ''आस्तियों'' पद से उनकी चालू कीमत पर बीमाकर्ता की सभी आस्तियां अभिप्रेत हैं, किन्तु इनमें ऐसी किसी निधि या उसके भाग जिसकी बाबत प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि, यथास्थिति, ऐसी निधि या उसका भाग भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा विनियमित होता है या प्रकीर्ण व्यय जिसकी बाबत प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि इस धारा के उपबंधों को लागू करना बीमाकर्ता के हित में नहीं होगा, के प्रति विनिर्दिष्ट रूप से धारित कोई आस्ति सम्मिलत नहीं है।

- (3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, कोई विनिर्दिष्ट आस्तियां, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अनुमोदित विनिधानों में विनिहित आस्तियां या विनिहित रखी गईं आस्तियां समझी जाएंगी।
- (4) उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट आस्तियों की संगणना करने में, भारतीय रुपए से भिन्न किसी करेंसी के प्रति निर्देश से किए गए किसी विनिधान को, जो उस करेंसी के प्रति निर्देश से भारत में बीमाकर्ताओं के दायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षित रूप से अधिक है, ऐसे आधिक्य की सीमा तक हिसाब में नहीं लिया जाएगा:

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात उपधारा (2) के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी:

परन्तु यह और कि प्राधिकरण या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट मामले में यह निदेश दे सकेगा कि कोई विनिधान ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए,जो अधिरोपित की जाएं, ऐसी रीति से हिसाब में लिया जाएगा जो उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट आस्तियों की संगणना में विनिर्दिष्ट की जाएं और जहां कोई निदेश इस परन्तुक के अधीन जारी किया गया है वहां उसकी प्रतियां उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएंगी।

- (5) जहां किसी बीमाकर्ता ने किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा निर्गमित और भारत में अदायगी के लिए परिपक्व होने वाली किन्हीं जीवन बीमा पॉलिसियों की बाबत पुनर्बीमा प्रतिगृहीत किया है या उसने स्वयं के द्वारा निर्गमित किन्हीं ऐसी पालिसियों के संबंध में अन्य बीमाकर्ता को पुनर्बीमा अभ्यर्पित किया है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि में ऐसे प्रतिग्रहण में अंतर्विलत दायित्व की रकम जोड़ दी जाएगी और ऐसे अभ्यर्पण में अंतर्विलत दायित्व की रकम उसमें से घटा दी जाएगी।
- (6) वे सरकारी प्रतिभूतियां और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, जिनमें उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आस्तियां विनिहित की जानी हैं और विनिहित रखी जानी हैं, बीमाकर्ता द्वारा किसी विल्लंगम, प्रभार, आडमान या धारणाधिकार से मुक्त रूप में धारित की जाएंगी।
- (7) वे आस्तियां जिनकी बाबत इस धारा के अनुसार यह अपेक्षित है कि वे भारत के बाहर निगमित या अधिवसित बीमाकर्ता द्वारा विनिहित रखी जाएं उनके उस भाग तक की सीमा के सिवाय, जो भारत के बाहर विदेशी आस्तियों के रूप में धृत हैं, भारत में धृत रखी जाएंगी और सभी ऐसी आस्तियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति के दायित्वों के उन्मोचन के लिए न्यास के रूप में धृत रखी जाएंगी और भारत में निवासी तथा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित न्यासियों में विनिहित होंगी, और इस उपधारा के अधीन न्यास लिखत प्राधिकरण के अनुमोदन से बीमाकर्ता द्वारा निष्पादित की जाएगी और उसमें उस रीति का उल्लेख किया जाएगा जिससे केवल न्यास की विषय-वस्तु बरती जाएगी।

स्पष्टीकरण — यह उपधारा भारत में निगमित ऐसे किसी बीमाकर्ता को लागू होगी जिसकी एक-तिहाई शेयर पूंजी के स्वामी या जिसके शासी निकाय के एक-तिहाई सदस्य भारत से अन्यत्र अधिवसित हैं।

27क. (1) जीवन बीमा कारबार करने वाला कोई बीमाकर्ता उसके द्वारा नियंत्रित निधि के किसी भाग को और साधारण कारबार करने वाला कोई बीमाकर्ता अपनी आस्तियों को ऐसे अनुमोदित विनिधानों से भिन्न किसी विनिधान में, न तो विनिहित करेगा और न ही विनिहित रखेगा, जो

विनिधानों के संबंध में अतिरिक्त उपबंध। उसमें ऐसी परिसीमाओं, शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

- (2) धारा 27 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, कोई बीमाकर्ता, ठीक आगामी उपधाराओं के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा नियंत्रित निधि या आस्तियों के किसी भाग को, किसी अनुमोदित विनिधान से भिन्न विनिधानों में विनिहित कर सकेगा या विनिहित रख सकेगा, यदि
 - (i) ऐसे विनिधान के पश्चात् बीमाकर्ता के ऐसे सभी विनिधानों की कुल रकम, यथास्थिति, धारा 27 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि के पन्द्रह प्रतिशत या उसकी उपधारा (2) में निर्दिष्ट आस्तियों के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं है;
 - (ii) वह विनिधान उन सब निदेशकों की सहमित से किया गया है या पहले से किए गए किसी विनिधान की दशा में वह विनिधान अधिवेशन में उपस्थित और मतदान के लिए पात्र सभी निदेशकों की सहमित से चालू रखा गया है जिसकी विशेष सूचना भारत में उस समय विद्यमान सब निदेशकों को दी गई हो और सभी ऐसे विनिधानों सिहत, जिनसे कोई निदेशक हितबद्ध हो ऐसे सभी विनिधानों की रिपोर्ट ऐसे सब विनिधानों के सम्पूर्ण ब्यौरों सिहत और किसी ऐसे विनिधान में निदेशक के हित की सीमा तक प्राधिकरण को अविलंब दे दी गई हो।
- (3) कोई भी बीमाकर्ता धारा 27 में यथा निर्दिष्ट अपनी नियंत्रित निधि या आस्तियों में से, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिशतता से अधिक कोई रकम—
 - (क) किसी एक बैंककारी कंपनी के शेयरों में विनिहित नहीं करेगा, या
 - (ख) किसी एक कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों में विनिहित नहीं करेगा।
- (4) कोई बीमाकर्ता धारा 27 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट उसके द्वारा नियंत्रित निधि या आस्तियों में से किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों में न तो कोई रकम विनिहित करेगा और न ही विनिहित रखेगा।
- (5) धारा 27 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट नियंत्रित निधि या आस्तियों के भागरूप वे सभी आस्तियां, जो सरकारी प्रतिभूतियां या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां नहीं हैं जिनमें आस्तियां इस धारा के अनुसार विनिहित की जानी हैं या विनिहित रखी जानी हैं [उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट नियंत्रित निधि या आस्तियों के मूल्य के एक-बटा दस से अनिधक भाग के सिवाय, जो ऐसी शर्तों और निबंधनों के रहते हुए, जो विहित किए जाएं, किसी विनिधान के प्रयोजनों के लिए, लिए गए किसी ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में दिया जा सकता है। किसी विल्लंगम, भार, आडमान या धारणाधिकार से मुक्त धारण की जाएंगी।
- (6) यदि किसी समय, प्राधिकरण बीमाकर्ता के किसी एक या एक से अधिक विनिधानों को अनुपयुक्त या अवांछित समझता है, तो प्राधिकरण, बीमाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे विनिधान या विनिधानों की रकम वसूल करने का निदेश दे सकेगा और वह बीमाकर्ता ऐसे समय के भीतर, जो प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे निदेशों का पालन करेगा।
- (7) इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसी किसी रीति पर प्रभाव डालती है जिससे किसी कर्मचारी की भविष्य निधि या किसी कर्मचारी से ली गई किसी प्रतिभूति से संबंधित धनराशियां या उसी प्रकृति की कोई अन्य धनराशियां किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य विधान–मंडल के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन धारित की जानी अपेक्षित हैं।

स्पष्टीकरण — इस धारा में ''नियंत्रित निधि'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

- (क) जीवन बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता की दशा में,—
 - (i) उसकी सभी निधियां, यदि वह किसी अन्य वर्ग का बीमा कारबार नहीं करता है:
- (ii) उसके जीवन बीमा कारबार से संबंधित भारत में की सभी निधियां, यदि वह किसी अन्य वर्ग का बीमा कारबार भी करता है।

स्पष्टीकरण — उपखंड (i) और उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, निधि के अंतर्गत ऐसी कोई निधि या उसका भाग नहीं है, जिसकी बाबत प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि, यथास्थिति, ऐसी निधि या उसके भाग को भारत के बाहर किसी देश की प्रवृत्त विधि द्वारा विनियमित किया जाता है या इस धारा के उपबंधों को लागू करना बीमाकर्ता के हित में नहीं होगा।'':

- (ख) जीवन बीमा कारबार करने वाले किसी अन्य बीमाकर्ता की दशा में,—
- (i) भारत में उसकी सभी निधियां, यदि वह किसी अन्य वर्ग का बीमा कारबार नहीं करता है:
- (ii) उसके जीवन बीमा कारबार से संबंधित भारत में सभी निधियां, यदि वह किसी अन्य वर्ग के बीमा कारबार भी करता है;

किंतु इसमें कोई निधि या उसका भाग सिम्मिलित नहीं है जिसके संबंध में प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है, कि, यथास्थिति, ऐसी निधि या उसका भाग भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा विनियमित किया जाता है या जिसके संबंध में प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि इस धारा के उपबंधों को लागू करना बीमाकर्ता के हित में नहीं होगा।

- 27ख. (1) साधारण बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता की सभी आस्तियों को, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, धारा 27 में विनिर्दिष्ट अनुमोदित विनिधानों में विनिहित की गई या विनिहित रखी गई आस्तियां समझा जाएगा।
- (2) सभी आस्तियां (उनमें से उनके उस भाग के सिवाय जो मूल्यों में कुल आस्तियों के एक-बटा दस से अधिक नहीं है और जो ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, किसी विनिधान या दावों के चुकाने के प्रयोजन के लिए दिए गए किसी उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्थापित किया गया है या जो पालिसियों के प्रतिग्रहण के लिए बैंकों के पास प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखा जाए) किसी भी विल्लंगम, भार, आडमान या धारणाधिकार से मुक्त धारण की जाएंगी।
- (3) धारा 27क की उपधारा (5) द्वारा प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह बीमाकर्ता से यह अपेक्षा करती है कि वह बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1968 के प्रारंभ के पश्चात् धारा 27 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुरूप किए गए किसी विनिधान की वसूली करे, जो ऐसा विनिधान किए जाने के पश्चात् इस धारा के अर्थांतर्गत कोई अनुमोदित विनिधान नहीं रह गया है।

1968 का 62

कतिपय मामलों में बीमाकर्ता द्वारा विनिधान।

साधारण बीमा

कारबार करने वाले

बीमाकर्ता की

आस्तियों के विनिधानों के

संबंध में उपबंध।

विनिधान की रीति और शर्तें। 27ग. कोई बीमाकर्ता, धारा 27 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट अपनी नियंत्रित निधि या आस्तियों के कुल पांच प्रतिशत से अनिधक, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं, संप्रवर्तकों की कंपनियों में विनिहित कर सकेगा।

27घ. (1) इस धारा की किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण, पालिसीधारकों के हित में, विनियमों द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी बीमाकर्ता द्वारा धारण की जाने वाली आस्तियों के विनिधान का समय. रीति और अन्य शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

1999 का 41

- (2) प्राधिकरण, ऐसे समय, रीति और अन्य शर्तों के संबंध में विनिर्दिष्ट निदेश दे सकेगा, जिनके अधीन रहते हुए, पालिसीधारियों की निधियां, ऐसे अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं विनिहित की जाएंगी और ऐसे विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात्, भारत में जीवन बीमा, साधारण बीमा, या स्वास्थ्य बीमा अथवा पुनर्बीमा कारबार करने वाले सभी बीमाकर्ताओं को एक समान रूप से लागू होंगे।
- (3) प्राधिकरण, कारबार की प्रकृति को ध्यान में रखने के पश्चात् और पालिसीधारियों के हितों के संरक्षण के लिए किसी बीमाकर्ता को उसके द्वारा धारित की जाने वाली आस्तियों के विनिधान के समय, रीति और अन्य शर्तों के संबंध में निदेश जारी कर सकेगा:

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित बीमाकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

27ड. कोई बीमाकर्ता, पालिसीधारियों की निधियों को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर विनिहित नहीं करेगा।''।

27. बीमा अधिनियम की धारा 28, धारा 28क और धारा 28ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"28. प्रत्येक बीमाकर्ता, प्राधिकरण को, किए गए विनिधानों की विवरणी उनका विवरण देते हुए ऐसे प्ररूप, समय और ऐसी रीति में जिसके अन्तर्गत उसका अधिप्रमाणन भी है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए. देगा।"।

28. बीमा अधिनियम की धारा 29 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थातु:—

"29.(1) कोई भी बीमाकर्ता, अपने द्वारा निर्गमित जीवन बीमा पालिसियों पर उनके अभ्यर्पण मूल्य की सीमा तक उधार देने के सिवाय संपत्ति के आडमान पर या वैयक्तिक प्रतिभूति पर या अन्यथा, कोई उधार या अस्थायी अग्रिम उस दशा में, यदि वह बीमाकर्ता कोई कंपनी है, उसके किसी निदेशक, प्रबंधक, बीमांकक, लेखा परीक्षक या अधिकारी को या किसी अन्य कंपनी या फर्म को, जिसमें कोई ऐसा निदेशक, प्रबंधक, बीमांकक वा अधिकारी किसी निदेशक, प्रबंधक, बीमांकक आधिकारी या भागीदार की हैसियत में है, नहीं देगा:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी बीमाकर्ता द्वारा किसी बैंककारी कंपनी को दिए गए ऐसे उधारों को, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात किसी कंपनी की किसी समनुषंगी कंपनी या किसी अन्य कंपनी को, जिसकी उधार या अग्रिम देने वाली कंपनी समनुषंगी कंपनी है, ऐसे उधार या अग्रिम देने से प्रतिषिद्ध नहीं करेगी, यदि ऐसे उधार या अग्रिम के लिए प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन ले लिया गया है।

- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के उपबंध ऐसे किसी बीमाकर्ता के, जो कंपनी है, निदेशक को दिए गए उधार की दशा में लागू नहीं होंगे, यदि ऐसा उधार उस पालिसी की प्रतिभूति पर दिया गया है जिस पर जोखिम बीमाकर्ता वहन करता है और पालिसी निदेशक को उसके स्वयं के जीवन के लिए निर्गमित की गई है और वह उधार उस पालिसी के अभ्यर्पण मूल्य की सीमा के भीतर है।
 - (3) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसा कोई बीमाकर्ता—
 - (क) ऐसे उधार के सिवाय जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट है, जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता के पूर्णकालिक कर्मचारियों को उसके निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित स्कीम के

भारत के बाहर निधियों के विनिधान के लिए प्रतिषेध।

धारा 28, धारा 28क और धारा 28ख के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन। आस्तियों के विनिधान का विवरण और विवरणों।

धारा 29 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

उधारों का प्रतिषेध।

अनुसार उनके वेतन पैकेज के भागरूप मंजूर किए गए उधार भी हैं, कोई उधार या अग्रिम, संपत्ति के आडमान या वैयक्तिक प्रतिभृति पर या अन्यथा नहीं देगा;

- (ख) किसी बीमा अभिकर्ता को अस्थायी अग्रिम उस रूप में उसके कृत्यों को सुकर बनाने के लिए उन दशाओं में देने के सिवाय नहीं देगा, जहां ऐसे अग्रिम कुल मिलाकर उसके द्वारा ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उपार्जित नवीकरण कमीशन से अधिक नहीं है।
- (4) जहां ऐसी कोई घटना घटित होती है जिससे ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसकी विद्यमानता से उधार या अग्रिम दिए जाने के समय ऐसे अनुदान को इस धारा का उल्लंघन होता है वहां ऐसे उधार या अग्रिम का किसी प्रतिकूल संविदा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी घटना के घटित होने से तीन मास के भीतर प्रतिसंदाय किया जाएगा।
- (5) उपधारा (4) के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम की दशा में, संपृक्त निदेशक, प्रबंधक, लेखा परीक्षक, बीमांकक, अधिकारी या बीमा अभिकर्ता, ऐसी किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो वह उपगत कर ले तीन मास की समाप्ति पर उधार देने वाले बीमाकर्ता के अधीन उस पद पर नहीं रह जाएगा या उसके लिए कार्य करने से प्रविरत हो जाएगा।"।
- 29. बीमा अधिनियम की धारा 30 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात:—
- "30. यदि बीमाकर्ता को या पालिसीधारियों को धारा 27, धारा 27क, धारा 27ख, धारा 27 ग, धारा 27घ या धारा 29 के उपबंधों में से किसी उपबंध के उल्लंघन के कारण कोई हानि उठानी पड़ती हैं तो ऐसा प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक या अधिकारी, जिसने जानबूझकर ऐसे उल्लंघन में भाग लिया है, ऐसी किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन दायी हो सकता है, ऐसी हानि की रकम की प्रतिपूर्ति करने के लिए संयुक्तत: और पृथक्त: दायी होगा।"।
- **30**. बीमा अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात:—
 - ''(1) किसी बीमाकर्ता की भारत में की आस्तियों में से कोई भी आस्ति, वहां तक के सिवाय जहां तक कि ऐसी आस्तियां धारा 27 की उपधारा (7) के अधीन न्यासियों में निहित की जानी अपेक्षित हैं, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित लोक अधिकारी के नाम में या उपक्रम के निगमित नाम में यदि, वह, यथास्थिति, कंपनी या बीमा सहकारी सोसाइटी है, रखे जाने से अन्यथा नहीं रखी जाएगी।''।
 - 31. बीमा अधिनियम की धारा 31क में,—
 - (क) उपधारा (1) के खंड (ग) में.—
 - (I) परन्तुक के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
 - ''(i) किसी बीमा अभिकर्ता को उस जीवन बीमा कारबार विषयक कमीशन की अदायगी, जो उसके द्वारा या उसके माध्यम से उपाप्त किया गया है;'';
 - (II) परन्तुक के खंड (iii) का लोप किया जाएगा;
 - (ख) उपधारा (3) में, ''या इंडियन कंपनीज ऐक्ट, 1913 की धारा 86बी में ''शब्दों, अंकों और 1913 का 7 अक्षर के स्थान पर, ''या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में'' शब्द रखे जाएंगे।
 - 32. बीमा अधिनियम की धारा 31ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
 - "31 ख. कोई बीमाकर्ता उसके द्वारा किए गए बीमा कारबार के संबंध में किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक के रूप में ऐसी रकम से अधिक रकम, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, कमीशन के रूप में या अन्यथा नहीं देगा।"।

धारा 30 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। धारा 27, धारा 27क, धारा 27ख, धारा 27ग, धारा 27घ या धारा 29 के उल्लंघनों के कारण हुई हानि के लिए निदेशकों, आदि का दायित्व। धारा 31 का संशोधन।

धारा 31क का संशोधन।

धारा 31 ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। अत्यधिक पारिश्रमिक के दिए जाने को निर्बंधित करने की शक्ति। 33. बीमा अधिनियम की धारा 32 का लोप किया जाएगा।

धारा 32 का लोप।

34. बीमा अधिनियम की धारा 32क में.—

धारा 32क का संशोधन।

- (i) उपधारा (1) में, ''धारा 2 के खंड (9) के उपखंड (ख) में विनिर्दिष्ट है तथा'' शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर का लोप किया जाएगा;
 - (ii) उपधारा (2) और उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।
- 35. बीमा अधिनियम की धारा 32ख में, ''ग्रामीण या सामाजिक सेक्टर में'' शब्दों के स्थान पर, ''ग्रामीण और सामाजिक सेक्टरों में'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 32ख का संशोधन।

36. बीमा अधिनियम की धारा 32ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:—

नई धारा 32घ का अन्तःस्थापन।

''32घ. साधारण बीमा कारबार करने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता, बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ के पश्चात् मोटरयान के अन्य पक्षकार जोखिम से संबंधित बीमा कारबार की उतनी न्यूनतम प्रतिशतता का हामीदार होगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए: मोटरयान के अन्य पक्षकार जोखिम में बीमा कारबार के संबंध में बीमाकर्ता की बाध्यता।

परन्तु प्राधिकरण, विनियमों द्वारा, ऐसे किसी बीमाकर्ता को, जो मुख्यतया स्वास्थ्य, पुनर्बीमा, कृषि, निर्यात प्रत्याय प्रत्याभूति के कारबार में लगा हुआ है, इस धारा के लागू होने से छूट प्रदान कर सकेगा।''।

37. बीमा अधिनियम की धारा 33 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 33 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। प्राधिकरण द्वारा अन्वेषण और निरीक्षण की

शक्ति ।

'33. (1) प्राधिकरण किसी भी समय, यदि वह ऐसा करना समीचीन समझता है, लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो (जिसे ''अन्वेषक अधिकारी'' कहा गया है), यथास्थिति, किसी बीमाकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती के क्रियाकलापों का अन्वेषण करने तथा ऐसे अन्वेषक अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे किसी अन्वेषण की रिपोर्ट प्राधिकरण को देने का निदेश दे सकेगा:

परन्तु अन्वेषक अधिकारी, जहां–कहीं आवश्यक हो, इस धारा के अधीन किसी अन्वेषण में उसकी सहायता करने के प्रयोजन के लिए किसी लेखापरीक्षक या बीमांकक या दोनों को नियोजित कर सकेगा।

- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210 में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, अन्वेषक अधिकारी, यथास्थिति, किसी बीमाकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती का तथा उसकी बहियों और लेखाओं का अपने एक या अधिक अधिकारियों द्वारा किसी भी समय निरीक्षण करा सकेगा तथा प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए निदेश दिए जाने पर ऐसा कराएगा और अन्वेषक अधिकारी ऐसे निरीक्षण पर रिपोर्ट की एक प्रति, यथास्थिति, बीमाकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती को देगा।
- (3) बीमार्कर्ता के प्रत्येक प्रबंधक, प्रबंध निदेशक या अन्य अधिकारी का, जिसके अंतर्गत किसी बीमार्कर्ता का सेवा प्रदाता या ठेकेदार भी है, यह कर्तव्य होगा कि वह जहां, यथास्थिति, बीमार्कर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती द्वारा उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण करने अथवा उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण करने के लिए निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष सेवाएं बाह्य स्रोत से प्राप्त की जाती हैं वहां ऐसी सब लेखा बहियां, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजें, जो उसकी अभिरक्षा और शक्ति में हैं, पेश करे तथा, यथास्थिति, किसी बीमार्कर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती के कार्यकलापों से संबंधित ऐसे विवरण और जानकारी, जिनकी उक्त अन्वेषक अधिकारी द्वारा उससे अपेक्षा की जाए, उतने समय के भीतर उसे दे, जितना उक्त अन्वेषक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (4) उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण करने के लिए अथवा उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण करने के लिए निर्दिष्ट कोई अन्वेषक अधिकारी बीमाकर्ता के कारबार के संबंध में, यथास्थिति, बीमाकर्ता

के किसी प्रबंधक, प्रबंध निदेशक या अन्य अधिकारी की, जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता का सेवा प्रदाता या ठेकेदार भी है, जहां कि, यथास्थिति, बीमाकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती द्वारा बाह्य सेवा प्राप्त की जाती है, शपथ पर परीक्षा कर सकेगा।

- (5) अन्वेषक अधिकारी, ऐसे निरीक्षण के संबंध में प्राधिकरण को रिपोर्ट उस दशा में देगा यदि उसे प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण किए जाने का निदेश दिया गया हो।
- (6) उपधारा (1) या उपधारा (5) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर प्राधिकरण, यथास्थिति, बीमाकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती को रिपोर्ट के संबंध में अभ्यावेदन करने का ऐसा अवसर दिए जाने के पश्चात्,जो प्राधिकरण की राय में युक्तियुक्त प्रतीत हो, लिखित आंदेश द्वारा,—
 - (क) बीमाकर्ता से यह अपेक्षा कर सकेगा कि रिपोर्ट से उद्भूत किसी विषय के बारे में वह ऐसी कार्रवाई करे, जो प्राधिकरण ठीक समझे; या
 - (ख) यथास्थिति, बीमाकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती का रिजस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा: या
 - (ग) किसी व्यक्ति को निदेश दे सकेगा कि वह, यथास्थिति, बीमाकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती, यदि वह कंपनी है, के परिसमापन के लिए न्यायालय में आवेदन करे, भले ही, यथास्थिति, बीमाकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती का रिजस्ट्रीकरण खंड (ख) के अधीन रद्द किया गया हो या नहीं।
- (7) प्राधिकरण, उसके द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा वह न्यूनतम जानकारी, जो, यथास्थिति, बीमाकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती द्वारा अपनी बहियों में रखी जानी हैं वह रीति, जिसमें ऐसी जानकारी रखी जाएगी, वे जांच-पड़तालें तथा अन्य सत्यापन, जो, यथास्थिति, बीमाकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती द्वारा इस संबंध में किए जाने हैं तथा उनसे आनुषंगिक सब अन्य ऐसी बातें जो उसकी राय में अन्वेषक अधिकारी को इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का समाधानप्रद रूप में निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं, विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''बीमाकर्ता'' पद के अन्तर्गत भारत में निगमित बीमाकर्ता की दशा में,—

- (क) उसकी वे सब समनुषंगी आती हैं, जो अनन्यत: भारत के बाहर बीमा कारबार के प्रयोजन से बनाई गई हैं; और
 - (ख) उसकी सब शाखाएं आती हैं, भले ही वे भारत में या भारत के बाहर स्थित हों।
- (8) इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई बीमाकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।
- (9) इस धारा के अधीन किए गए किसी अन्वेषण के और उससे आनुषंगिक सब व्यय, यथास्थिति, बीमाकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती द्वारा चुकाए जाएंगे तथा बीमाकर्ता से शोध्य अन्य ऋणों पर अग्रता रखेंगे तथा भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होंगे।'।

धारा 34ख का संशोधन।

- 38. बीमा अधिनियम की धारा 34ख की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
 - "(4) यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी बाबत प्राधिकरण ने उपधारा (1) के अधीन अथवा उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन कोई आदेश किया है, इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह हर ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, एक लाख रुपए अथवा एक करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, की शास्ति का दायी होगा।"।

39.बीमा अधिनियम की धारा 34ग की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) यदि प्राधिकरण की यह राय है कि लोकहित में अथवा बीमाकर्ता या उसके पालिसीधारियों के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह समय-समय पर लिखित आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, एक या अधिक व्यक्तियों को, उस तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, बीमाकर्ता के अपर निदेशकों के रूप में पद धारण करने के लिए नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु इस प्रकार नियुक्त किए गए अपर निदेशकों की संख्या किसी भी समय पांच से या बीमाकर्ता के संगम–ज्ञापनों द्वारा बोर्ड के लिए नियत अधिकतम संख्या के एक–तिहाई से, इनमें से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी।''।

40. बीमा अधिनियम की धारा 34छ का लोप किया जाएगा।

धारा 34छ का लोप।

धारा ३४ग का संशोधन।

41. बीमा अधिनियम की धारा 34ज में, --

धारा 34ज का संशोधन।

- (i) उपधारा (1) में ''प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी'' शब्दों के स्थान पर ''उप निदेशक या कोई समतुल्य अधिकारी'' शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) उपधारा (7) और उपधारा (8) में, ''केन्द्रीय सरकार'' शब्दों के स्थान पर ''प्रतिभूति अपील अधिकरण'' शब्द रखे जाएंगे।
- 42. बीमा अधिनियम की धारा 35 में,—

धारा 35 का संशोधन।

- (i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थातु:-
- ''(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, बीमाकर्ता का कोई भी बीमा कारबार इस धारा के अधीन तैयार की गई और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की गई स्कीम के अनुसार ही किसी अन्य बीमाकर्ता के बीमा कारबार को अन्तरित या उसमें समामेलित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।'';
- (ii) उपधारा (3) के खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात:—
 - ''(ख) ऐसे समामेलन या अन्तरण से संबंध रखने वाले बीमाकर्ताओं में से हर एक के बीमा कारबार की बाबत तुलन-पत्र ऐसे प्ररूपों में तैयार किया जाएगा जो विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं;
 - (ग) इस प्रकार संबंध रखने वाले बीमाकर्ताओं में से हर एक के जीवन बीमा कारबार की बाबत बीमांकक रिपोर्ट और संक्षिप्तियां इस संबंध में विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुरूप तैयार की जाएंगी।''।
- 43. बीमा अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 36 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। प्राधिकरण द्वारा समामेलन और

अन्तरण

मंजूरी ।

"36. यदि धारा 35 की उपधारा (3) के अधीन कोई आवेदन प्राधिकरण को किया जाता है तो प्राधिकरण संपृक्त बीमाकर्ता की किसी भी प्रकार की पालिसी के धारकों को आवेदन की सूचना, उस प्रकृति के विवरण सिहत दिलाएगा, और, यथास्थिति, उस समामेलन या अन्तरण के निबन्धनों को ऐसी रीति में और ऐसी अविध के लिए, जो वह निर्दिष्ट करे, प्रकाशित कराएगा तथा निदेशकों की सुनवाई करने के पश्चात् और पालिसीधारियों के तथा ऐसी किन्हीं अन्य व्यक्तियों के जिनकी बाबत वह यह समझे कि वे सुनवाई के हकदार हैं, आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात् उस ठहराव का अनुमोदन कर सकेगा और उस ठहराव को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे पारिणामिक आदेश कर सकेगा, जो आवश्यक हों।"।

धारा 37क का संशोधन। 44. बीमा अधिनियम की धारा 37क की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(4) तत्पश्चात् स्कीम मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखी जाएगी तथा केन्द्रीय सरकार स्कीम को किसी उपान्तरण के बिना या ऐसे उपान्तरणों सिहत, जो वह आवश्यक समझे, मंजूर कर सकेगी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई स्कीम उस तारीख को प्रवृत्त होगी जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित करे:

परन्तु स्कीम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।

(4क) प्रत्येक बीमाकर्ता का प्रत्येक पालिसीधारी या शेयरधारक या सदस्य समामेलन के पूर्व, उस समामेलन के परिणामस्वरूप बीमाकर्ता में वही हित या उसके विरुद्ध वही अधिकार रखेगा जो उसका उस कंपनी में होता जिसका वह मूल रूप से पालिसीधारी या शेयर धारक या सदस्य था:

परन्तु जहां किसी शेयरधारक या सदस्य के हित या अधिकार मूल बीमाकर्ता में के हित या उसके विरुद्ध के अधिकारों से कम है वहां वह ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निर्धारित किया जाए।

- (4ख) बीमा कंपनी द्वारा ऐसे समामेलन के परिणामस्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया गया प्रतिकर शेयरधारक या सदस्य को संदत्त किया जाएगा।
- (4ग) उपधारा (4क) के अधीन प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रतिकर के निर्धारण से व्यथित कोई सदस्य या शेयरधारक ऐसे निर्धारण के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।''।
- 45. बीमा अधिनियम की धारा 38, धारा 39 और धारा 40 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 38, धारा 39 और धारा 40 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

बीमा पालिसियों का समनुदेशन और अन्तरण।

- '38. (1) बीमा पालिसी का पूर्णत: या भागत: अन्तरण या समनुदेशन, भले ही वह प्रतिफल सहित हो या प्रतिफल रहित, केवल पालिसी पर ही ऐसे पृष्ठांकन द्वारा या ऐसी पृथक् लिखत द्वारा, जो दोनों ही दशाओं में अन्तरक द्वारा या समनुदेशक द्वारा या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित हो, अन्तरण या समनुदेशन का तथ्य और उसके लिए कारण, समनुदेशिती का पूर्ववृत्त और वे निबंधन, जिन पर समनुदेशन किया गया है, विनिर्दिष्टत: उसमें उपवर्णित करके किया जा सकेगा।
- (2) कोई बीमाकर्ता, अन्तरण या समनुदेशन को स्वीकार कर सकेगा या उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी पृष्ठांकन पर कार्रवाई करने से इंकार कर सकेगा, जहां उसके पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ऐसा अन्तरण या समनुदेशन सदभावी नहीं है या पालिसीधारी के हित में अथवा लोकहित में नहीं है या बीमा पालिसी का लेन-देन करने के प्रयोजन के लिए है।
- (3) बीमाकर्ता, पृष्ठांकन पर कार्रवाई करने से इंकार करने से पूर्व, ऐसे इंकार के कारणों को लेखबद्ध करेगा और उनकी संसूचना ऐसे अन्तरण या समनुदेशन की सूचना पालिसीधारी को दिए जाने की तारीख से तीस दिन के अपश्चात् पालिसीधारी को देगा।
- (4) कोई व्यक्ति जो, बीमाकर्ता के ऐसे अन्तरण या समनुदेशन के प्रति कार्रवाई करने से इंकार करने के विनिश्चय से व्यथित है, बीमाकर्ता से ऐसे इंकार किए जाने के कारणों की संसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अविध के भीतर प्राधिकरण को दावा प्रस्तुत कर सकेगा।
- (5) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तरण या समनुदेशन सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित ऐसे पृष्ठांकन या लिखत के निष्पादन पर पूर्ण और प्रभावी हो जाएगा, किंतु जहां वह

अन्तरण या समनुदेशन बीमाकर्ता के पक्ष में है, वहां के सिवाय वह बीमाकर्ता के विरुद्ध प्रवृत्त नहीं होगा और यह अन्तरिती या समनुदेशिती या उसके विधिक प्रतिनिधि को ऐसी पालिसी की रकम के लिए या उसके द्वारा प्रतिभूत धनराशि के लिए वाद लाने का कोई अधिकार तब तक प्रदत्त नहीं करेगा जब तक उस अन्तरण या समनुदेशन की लिखित सूचना और स्वयं पृष्ठांकन या लिखत अथवा उसकी ऐसी प्रति, जिसको अन्तरक और अन्तरिती दोनों ने या उनके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ताओं ने उसकी शुद्ध प्रति होना प्रमाणित कर दिया हो, बीमाकर्ता को न दे दी गई हो:

परन्तु जहां भारत में बीमाकर्ता के एक या अधिक कारबार के स्थान हैं, वहां ऐसी सूचना केवल उस स्थान पर परिदत्त की जाएगी, जहां पालिसी की तामील की जा रही है।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट सूचना जिस तारीख को बीमाकर्ता को परिदत्त की गई हो, वह तारीख उन व्यक्तियों के बीच, जो पालिसी से हितबद्ध हैं, उन सभी दावों की अग्रता विनियमित करेगी जो अन्तरण या समनुदेशन के अधीन हों; और जहां अन्तरण या समनुदेशन की एक से अधिक लिखत हों, वहां ऐसी लिखतों के अधीन दावों की अग्रता उस क्रम से होगी जिसमें उपधारा (5) में निर्दिष्ट सूचनाएं परिदत्त की गई हों:

परन्तु यदि संदाय की अग्रता के सबंध में कोई विवाद समनुदेशितियों के बीच में उत्पन्न होता है तो विवाद प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

- (7) उपधारा (5) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर, बीमाकर्ता ऐसे अंतरण या समनुदेशन का तथ्य, उसकी तारीख और अन्तरिती या समनुदेशिती के नाम सिंहत अभिलिखित करेगा तथा उस व्यक्ति के, जिसने सूचना दी थी या अंतरिती या समनुदेशिती के अनुरोध पर ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी सूचना की प्राप्ति की लिखित अभिस्वीकृति देगा; तथा ऐसी अभिस्वीकृति बीमाकर्ता के विरुद्ध इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि उसे वह सूचना, जिससे ऐसी अभिस्वीकृति संबंधित है, सम्यक् रूप से प्राप्त हो गई है।
- (8) अन्तरण या समनुदेशन के निबन्धनों ओर शर्तों के अधीन रहते हुए, बीमाकर्ता उपधारा (5) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति की तारीख से, उस अन्तरिती या समनुदेशिती को, जिसका नाम सूचना में दिया गया है, ऐसा एकमात्र अंतरिती या समनुदेशिती मानेगा, जो उस पालिसी के अधीन फायदे का हकदार है तथा ऐसा व्यक्ति उन सब दायित्वों और साम्याओं के अधीन होगा, जिनके अधीन वह अंतरक या समनुदेशक उस अन्तरण या समनुदेशन की तारीख पर था तथा अंतरक या समनुदेशक की सहमित प्राप्त किए बिना या उसे ऐसी कार्यवाहियों का पक्षकार बनाए बिना उस पालिसी के संबंध में कोई भी कार्यवाहियां संस्थित कर सकेगा, पालिसी के अधीन ऋण प्राप्त कर सकेगा या पालिसी अभ्यर्पित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—उस दशा के सिवाय जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट पृष्ठांकन में अभिव्यक्त रूप से यह उपदर्शित है कि समनुदेशन या अन्तरण इसके अधीन उपधारा (10) के निबन्धनों के अनुसार सशर्त है, प्रत्येक समनुदेशन या अन्तरण संपूर्ण समनुदेशन या अन्तरण समझा जाएगा और, यथास्थिति, समनुदेशिती या अन्तरिती क्रमश: पूर्ण समनुदेशिती या अन्तरिती समझा जाएगा।

- (9) बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ के पूर्व किए गए समनुदेशन या अन्तरण के अधीन जीवन बीमा पालिसी के किसी समनुदेशिती या अन्तरिती के किन्हीं अधिकारों या उपचारों पर इस धारा के उपबन्धों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (10) किसी विधि या विधि का बल रखने वाली किसी रूढ़ि में उसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति के पक्ष में इस शर्त के साथ किया गया समनुदेशन विधिमान्य होगा कि —
 - (क) पालिसी के अधीन आगम, पालिसीधारी को या समनुदेशिती या अन्तरिती की बीमाकृत व्यक्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को संदेय हो जाएंगे ;

(ख) बीमाकृत व्यक्ति के पालिसी की अवधि तक जीवित रहने पर:

परन्तु सशर्त समनुदेशिती किसी पालिसी पर कोई उधार लेने या पालिसी का अभ्यर्पण करने का हकदार नहीं होगा।

(11) उपधारा (1)के अधीन बीमा की पालिसी के आंशिक समनुदेशन या अन्तरण की दशा में बीमाकर्ता का दायित्व आंशिक समनुदेशन या अन्तरण द्वारा प्रतिभूत रकम तक सीमित होगा और ऐसा पालिसीधारक उसी पालिसी के अधीन संदेय अवशिष्ट रकम का और समनुदेशन या अन्तरण करने का हकदार नहीं होगा।

पालिसीधारी द्वारा नामनिर्देशन।

39. (1) जीवन बीमा पालिसी का धारक अपने ही जीवन पर पालिसी कराते समय या संदाय के लिए पालिसी के परिपक्व होने से पूर्व किसी भी समय उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे या जिन्हें वह धनराशि, जो पालिसी द्वारा प्रतिभूत है, उसकी मुत्यु की दशा में दी जाएगी:

परन्तु जहां कोई नामनिर्देशिती अवयस्क है, वहां पालिसीधारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह बीमाकर्ता द्वारा अधिकथित रीति में किसी व्यक्ति को इस दृष्टि से नियुक्त कर दे कि वह नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान पालिसीधारी की मृत्यु हो जाने की दशा में वह धनराशि, जो पालिसी द्वारा प्रतिभूत है, प्राप्त करेगा।

- (2) इस दृष्टि से कि कोई ऐसा नामनिर्देशन तब के सिवाय, जबिक वह पालिसी के पाठ में ही समाविष्ट हो, पालिसी पर पृष्ठांकन द्वारा प्रभावी किया जाएगा, जिसकी संसूचना बीमाकर्ता को दे दी गई हो और जिसे उसने पालिसी संबंधी अभिलेखों में दर्ज कर लिया हो, तथा ऐसा नामनिर्देशन संदाय के लिए पालिसी के परिपक्व होने के पूर्व किसी भी समय, यथास्थिति, पृष्ठांकन द्वारा या अतिरिक्त पृष्ठांकन द्वारा या विल द्वारा रद्द या परिवर्तित किया जा सकेगा, किन्तु जब तक कि ऐसे रद्दकरण या परिवर्तन की लिखित सूचना बीमाकर्ता को नहीं दे दी जाती, बीमाकर्ता पालिसी के पाठ में उल्लिखित या बीमाकर्ता के अभिलेखों में दर्ज नामनिर्देशिती को पालिसी पर अपने द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए किसी संदाय के लिए दायी न होगा।
- (3) बीमाकर्ता नामनिर्देशन या उसका रहकरण या परिवर्तन दर्ज कर लेने की लिखित अभिस्वीकृति पालिसीधारी को देगा तथा ऐसा रहकरण या परिवर्तन दर्ज करने के लिए ऐसी फीस प्रभारित कर सकेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (4) धारा 38 के अनुसार किया गया पालिसी का अन्तरण या समनुदेशन स्वत: नामनिर्देशन को रद्द कर देगा:

परन्तु ऐसे बीमाकर्ता को जो समनुदेशन के समय पालिसी पर जोखिम उठाता है, पालिसी के ऐसे समनुदेशन से, जो पालिसी के अभ्यर्पण मूल्य के अंदर उस पालिसी की प्रतिभूति पर उस बीमाकर्ता द्वारा दिए गए उधार के प्रतिफलस्वरूप किया गया है, या उधार को चुका दिए जाने पर उसके पुन: समनुदेशन से नामनिर्देशन रद्द नहीं होगा, बल्कि उससे नामनिर्देशिती के अधिकारों पर केवल उसी विस्तार तक प्रभाव पड़ेगा जहां तक उस पालिसी में बीमाकर्ता का हित है:

परन्तु यह और कि पालिसीधारी को अन्तरिती या समनुदेशिती द्वारा दिए गए उधार के प्रतिफल में पालिसी का अन्तरण या समनुदेशन, चाहे पूर्णत्ः हो या भागतः, नामनिर्देशन को रद्द नहीं करेगा, किन्तु नामनिर्देशिती के अधिकारों को, यथास्थिति, पालिसी में केवल अंतरिती या समनुदेशिती के हित की सीमा तक प्रभावित करेगाः

परन्तु यह भी कि वह नामनिर्देशन, जो अन्तरण या समनुदेशन के परिणामस्वरूप स्वत: रद्द हो गया है वह नामनिर्देशन तब स्वत्: ही पुन:प्रवर्तित हो जाएगा जब बीमाकर्ता को पालिसी की प्रतिभूति पर उधार से भिन्न उधार का प्रतिसंदाय करने पर पालिसीधारी के पक्ष में समनुदेशिती द्वारा पुन: समनुदेशन या अन्तरिती द्वारा पुन: अन्तरण कर दिया गया हो।

- (5) यदि पालिसी उस व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान, जिसके जीवन का बीमा किया गया है, संदाय के लिए परिपक्व हो जाती है या यदि नामनिर्देशिती की अथवा एक से अधिक नामनिर्देशिती होने की दशा में, सभी नामनिर्देशितियों की संदाय के लिए पालिसी के परिपक्व होने के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो पालिसी द्वारा प्रतिभूत रकम, यथास्थिति, पालिसीधारी को या उसके वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों को या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक को संदेय होगी।
- (6) जहां नामनिर्देशिती अथवा यदि एक से अधिक नामनिर्देशिती हों, तो एक या अधिक नामनिर्देशिती, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् जिसके जीवन का बीमा किया गया है, जीवित बचा रहता है या रहते हैं तो उस पालिसी द्वारा प्रतिभृत रकम ऐसे उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को संदेय होगी।
- (7) इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां अपने ही जीवन पर बीमा पालिसी का धारक अपने माता-पिता या अपने पित या अपनी पत्नी या अपने बच्चों या अपने पित या अपनी पत्नी और बच्चों या उनमें से किसी को नामनिर्देशित करता है वहां नामनिर्देशिती बीमाकर्ता द्वारा उपधारा (6) के अधीन उसे या उनको संदेय रकम के फायदा पाने का हकदार होगा या होंगे जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि पालिसी का धारक पालिसी में अपने हक की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए नामनिर्देशिती को ऐसे कोई फायदा पाने का हक प्रदान नहीं कर सकता था।
- (8) पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, जहां नामनिर्देशिती या यदि एक से अधिक नामनिर्देशिती हैं तो कोई नामनिर्देशिती या ऐसे नामनिर्देशिती, जिसको/जिनको उपधारा (7) लागू होती है, उस व्यक्ति के, जिसका जीवन बीमाकृत है, किन्तु पालिसी द्वारा प्रतिभृत रकम का संदाय करने के पूर्व, मृत्यु होती है तो पालिसी द्वारा प्रतिभूत रकम या पालिसी द्वारा प्रतिभूत उतनी रकम जो (यथास्थिति), उस नामनिर्देशिती या उन नामनिर्देशितियों के जिनकी मृत्यु हो जाती है, अंश को दर्शाती है, यथास्थिति, नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों के वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक को संदेय होगी और वे उस रकम का फायदा पाने के हकदार होंगे।
- (9) उपधारा (7) और उपधारा (8) की किसी बात का किसी जीवन बीमा पालिसी के आगमों से संदत्त किए जाने वाले किसी उधार देने वाले के अधिकार को नष्ट करने या उसमें अड़चन डालने का प्रभाव नहीं होगा।
- (10) उपधारा (7) और उपधारा (8) के उपबंध बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ के पश्चात् संदाय के लिए परिपक्व होने वाली सभी जीवन बीमा पालिसियों को लाग् होंगे।
- (11) जहां पालिसीधारी की पालिसी की परिपक्वता के पश्चात् मृत्यु हो जाती है किन्तु उसकी पालिसी के आगम और फायदे उसकी मृत्यु के कारण उसे नहीं दिए गए हैं, वहां उस दशा में उसका नामनिर्देशिती उसकी पालिसी के आगमों और फायदे का हकदार होगा।
- (12) इस धारा के उपबंध किसी ऐसी जीवन बीमा पालिसी को लागू नहीं होंगे जिसको विवाहित

स्त्री संपत्ति अधिनियम, 1874 की धारा 6 लागू होती है या किसी समय लागू रही है:

परन्तु जहां बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् ऐसे व्यक्ति की, जिसने अपने जीवन या अपनी पत्नी के जीवन और सन्तानों या उनमें से किसी के जीवन का स्पष्ट रूप से बीमा कराया है, पत्नी के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन इस धारा के अधीन किया गया अभिव्यक्त होता है, चाहे यह बात पालिसी के मुख्य भाग पर स्पष्ट रूप से अंकित है या नहीं, वहां उक्त धारा 6 के बारे में यह समझा जाएगा कि वह न तो पालिसी को लागू है और न ही लागू रही है।

40. (1) कोई भी व्यक्ति कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या पारितोषिक बीमा अभिकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती के सिवाय किसी व्यक्ति को भारत में बीमा कारबार के लिए याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए, ऐसी किसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, नहीं देगा और न ही देने की संविदा करेगा।

उपाप्त करने के लिए कमीशन के रूप में या अन्यथा

संदाय का प्रतिषेध।

(2) कोई भी बीमा अभिकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती भारत में किसी बीमाकर्ता द्वारा निर्गमित पालिसियों की बाबत किसी रूप में कमीशन या पारिश्रमिक इस संबंध में विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार ही प्राप्त करेगा या प्राप्त करने की संविदा करेगा, अन्यथा नहीं:

परन्तु प्राधिकरण, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन विनियम बनाते समय, पालिसी की प्रकृति और अविध पर और विशिष्टतया संयुक्त अभिकर्ताओं और अन्य मध्यवर्तियों के हित को ध्यान में रखेगा।

- (3) पूर्ववर्ती उपधाराओं या इस संबंध में विरचित विनियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध के किसी बीमाकर्ता द्वारा उल्लंघन की बाबत, धारा 102 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई ऐसा बीमा अभिकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती, जो उक्त उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसी शास्ति का दायी होगा जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी।'।
- 46. बीमा अधिनियम की धारा 40क का लोप किया जाएगा।
- 47. बीमा अधिनियम की धारा 40ख और धारा 40ग के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''40ख. कोई भी बीमाकर्ता, भारत में उसके द्वारा किए गए बीमा कारबार की बाबत, किसी वित्तीय वर्ष में उस रकम से अधिक रकम, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रबंध व्ययों के रूप में खर्च नहीं करेगा।

40ग. भारत में बीमा कारबार करने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता प्राधिकरण को प्रबंध व्ययों का ब्यौरा ऐसी रीति और ऐसे प्ररूप में देगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।"।

- 48. बीमा अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
 - ''(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में व्यतिक्रम करेगा, शास्ति के लिए, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।''।
 - 49. बीमा अधिनियम की धारा 42 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
 - "42. (1) कोई बीमाकर्ता किसी व्यक्ति को अपने लिए बीमा कारबार की याचना करने और उसे उपाप्त करने के प्रयोजन के लिए बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु ऐसा व्यक्ति उपधारा (3) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी से ग्रस्त नहीं होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति एक जीवन बीमाकर्ता, एक साधारण बीमाकर्ता, एक स्वास्थ्य बीमाकर्ता से अधिक बीमाकर्ता तथा अन्य मोनोलाइन बीमाकर्ताओं में से प्रत्येक के एक से अधिक के लिए बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा:

परन्तु प्राधिकरण, विनियम विरचित करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे किसी अभिकर्ता का, उन दो या अधिक बीमाकर्ताओं का, जिनके लिए वह एक अभिकर्ता हो, प्रतिनिधित्व करने में हित में कोई परस्पर विरोध अनुज्ञात न किया जाए।

- (3) उपधारा (1) के परंतुक में निर्दिष्ट निरर्हताएं निम्नलिखित होंगी:—
 - (क) यह कि वह व्यक्ति अवयस्क है:
 - (ख) यह कि सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा उसे विकृत्तचित्त पाया गया है;

धारा 40क का लोप। धारा 40ख और धारा 40ग के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन। जीवन बीमा कारबार में प्रबंध व्ययों की परिसीमा।

बीमा और

पुनर्बीमा कारबार

में प्रबंध व्ययों की परिसीमा।

धारा 41 का संशोधन।

धारा 42 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। बीमा अभिकर्ताओं की नियुक्ति। (ग) यह कि सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा उसे आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यासभंग या छल या कूटरचना का या ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण का या उसे करने के प्रयास का दोषी पाया गया है:

परन्तु जहां किसी ऐसे अपराध की बाबत किसी व्यक्ति पर अधिरोपित दंडादेश की समाप्ति से कम से कम पांच वर्ष व्यतीत हो गए हैं, वहां प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति की बाबत मामूली तौर पर यह घोषणा करेगा कि उसकी दोषसिद्धि इस खंड के अधीन निरर्हता के रूप में प्रवृत्त नहीं रह गई है;

- (घ) यह कि किसी बीमा पालिसी से या किसी बीमाकर्ता के परिसमापन से संबंधित किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान या बीमाकर्ता के कार्यकलापों के अन्वेषण के दौरान यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वह बीमाकर्ता या बीमाकृत के प्रति किसी कपट, बेईमानी या दुर्व्यपदेशन का दोषी रहा है या जानते हुए उसमें भागीदार रहा है या ऐसे अपराध के प्रति मौनानुकृल रहा है;
- (ङ) यह कि किसी व्यष्टि की दशा में, उसके पास विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हताएं या व्यावहारिक प्रशिक्षण नहीं है अथवा उसने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है;
- (च) यह कि आवेदन करने वाली किसी कंपनी या फर्म की दशा में निदेशक या भागीदार या उसके अधिकारियों में से एक या अधिक अधिकारी या उसके द्वारा इस प्रकार अभिहित अन्य कर्मचारियों और किसी अन्य व्यक्ति की दशा में मुख्य कार्यपालक, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो या उसके द्वारा अभिहित उसके एक या अधिक कर्मचारियों के पास अपेक्षित अर्हताएं और व्यावहारिक प्रशिक्षण नहीं है और उन्होंने खंड (ङ) और खंड (छ) के अधीन यथा अपेक्षित कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है;
 - (छ) यह कि उसने ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;
 - (ज) यह कि उसने विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट आचार संहिता का अतिक्रमण किया है।
- (4) कोई व्यक्ति जो बीमा अभिकर्ता के रूप में इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य करता है, वह ऐसी शास्ति के लिए जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा और कोई बीमाकर्ता या बीमाकर्ता की ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, जो ऐसे किसी व्यक्ति को बीमा अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता है, जो उस रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं है या भारत में बीमा कारबार ऐसे किसी व्यक्ति के माध्यम से करेगा, वह ऐसी शास्ति के लिए, जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।
- (5) बीमाकर्ता अपने अभिकर्ताओं के सभी कार्यों और लोपों के लिए, जिनके अंतर्गत उपधारा (3) के खंड (ज) के अधीन विनिर्दिष्ट आचार संहिता का अतिक्रमण भी है, उत्तरदायी होगा और ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी।''।
- **50**. बीमा अधिनियम की धारा 42क, धारा 42ख और धारा 42ग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात:—

धारा 42क, धारा 42ख और धारा 42ग के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

- ''42क. (1) कोई भी बीमाकर्ता, बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किसी प्रधान अभिकर्ता, मुख्य अभिकर्ता और विशेष अभिकर्ता को नियुक्त नहीं करेगा और उनके माध्यम से भारत में कोई बीमा कारबार नहीं करेगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति, बहुस्तरीय विपणन स्कीम के माध्यम से किसी बीमा पालिसी को लेने या उसका नवीकरण कराने या जारी रखने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरणा के रूप में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: अनुज्ञात नहीं करेगा या अनुज्ञात करने की प्रस्थापना नहीं करेगा।

प्रधान अभिकर्ता, विशेष अभिकर्ता के माध्यम से बीमा कारबार और बहुस्तरीय विपणन का प्रतिषेध। (3) प्राधिकरण, इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से बहुस्तरीय विपणन स्कीम में अंतर्विलत इकाई या व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित पुलिस प्राधिकारियों को शिकायत कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, ''बहुस्तरीय विपणन स्कीम'' से उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकृत न किए गए व्यक्तियों के माध्यम से बीमा कारबार की याचना करने और उसे उपाप्त करने के प्रयोजनार्थ ऐसी याचना और उपाप्त के माध्यम से अर्जित कमीशन या पारिश्रमिक के संपूर्ण या भागिक प्रतिफल सिहत या उसके बिना कोई स्कीम या कार्यक्रम या उहराव या योजना (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उक्त प्रयोजन के लिए प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी बहुस्तरीय श्रृंखला में व्यक्तियों का नामांकन भी है।''

धारा ४२घ का संशोधन।

- 51. बीमा अधिनियम की धारा 42घ में-
- (i) ''अनुज्ञप्ति'' और ''जारी की गई अनुज्ञप्ति'' शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमश: ''रजिस्ट्रीकरण'' और ''किए गए रजिस्ट्रीकरण'' शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) उपधारा (1) के परन्तुक के खंड (क) में "उपधारा (4)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "उपधारा (3)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (3) में,—

- (क) ''निदेशकों या भागीदारों'' शब्दों के पश्चात्, ''अथवा उनके द्वारा इस प्रकार पदाभिहित उनके एक या अधिक अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों और किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, मुख्य कार्यपालक, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, या उसके द्वारा पदाभिहित उसके एक या अधिक कर्मचारियों'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (ख) "धारा 42 की उपधारा (4) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 42 की उपधारा (3) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (छ)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (iv) उपधारा (8) और उपधारा (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—
- "(8) ऐसा कोई व्यक्ति, जो मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने के लिए इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत हुए बिना उस रूप में कार्य करता है, ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी और ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसीमध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या किसी व्यक्ति को, जो उस रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकृत नहीं है, नियुक्त करता है या ऐसे किसी व्यक्ति के माध्यम से भारत में कोई बीमा कारबार करता है, वह, ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी।
- (9) जहां उपधारा (8) का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी या फर्म है, वहां ऐसी किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर, जो कंपनी या फर्म के विरुद्ध की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कंपनी का ऐसा प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी और फर्म का ऐसा प्रत्येक भागीदार, जो जानबूझकर ऐसे उल्लंघन का भागी बना है, ऐसी शास्ति का, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।''।
- 52. बीमा अधिनियम की धारा 42ङ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

धारा ४२ ङके स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती के लिए

शर्त ।

''42 ङ. इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा, किसी मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने के लिए पूंजी की अपेक्षाएं, कारबार का रूप और अन्य शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा।''। 53. बीमा अधिनियम की धारा 43 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 43 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। बीमा अभिकर्ताओं का अभिलेख।

- ''43. (1) प्रत्येक बीमाकर्ता और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो बीमाकर्ता की ओर से कार्य करते हुए बीमा अभिकर्ताओं को नियोजित करता है, अभिलेख रखेगा जिसमें उसके द्वारा नियुक्त प्रत्येक बीमा अभिकर्ता का नाम और पता तथा वह तारीख, जिसको उसकी नियुक्ति आरंभ हुई और वह तारीख, यदि कोई हो, जिसको उसकी नियुक्ति समाप्त हुई, दर्शित की जाएगी।
- (2) बीमाकर्ता द्वारा उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया अभिलेख तब तक बनाए रखा जाएगा, जब तक बीमाकर्ता सेवारत है और नियुक्ति की समाप्ति के पश्चात् पांच वर्ष की अविध के लिए बनाए रखा जाएगा।''।
- 54. बीमा अधिनियम की धारा 44 का लोप किया जाएगा।

धारा 44 का लोप।

55. बीमा अधिनियम की धारा 44क और धारा 45 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात:—

धारा ४४क और धारा ४५ के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

''44क. धारा 40, धारा 40ख और धारा 40ग के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण सूचना द्वारा— जानकारी मांगने की शक्ति।

- (क) बीमाकर्ता से ऐसी जानकारी, जिसे वह आवश्यक समझे, मांग सकेगा, जो यदि अपेक्षित हो, तो लेखापरीक्षक या बीमांकक द्वारा प्रमाणित की गई होगी;
- (ख) बीमाकर्ता से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके द्वारा परीक्षा किए जाने के लिए भारत में बीमाकर्ता के कारबार के मुख्य स्थान पर ऐसी लेखा बहियां, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज पेश करे अथवा ऐसा कोई विवरण दे जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए;
- (ग) ऐसी किसी जानकारी, बही, रिजस्टर, दस्तावेज या विवरण के बारे में बीमाकर्ता के किसी अधिकारी की शपथ पर परीक्षा कर सकेगा और बीमाकर्ता, ऐसे समय के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी किसी अपेक्षा का पालन करेगा।
- 45. (1) किसी भी जीवन बीमा पालिसी पर, पालिसी की तारीख से अर्थात् पालिसी के निर्गमित किए जाने की तारीख से या जोखिम के प्रारंभ होने की तारीख से या पालिसी के पुनर्जीवित होने की तारीख से या पालिसी में राइडर जोड़े जाने की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी आधार पर, चाहे जो भी हो, आक्षेप नहीं किया जाएगा।

अशुद्ध कथन के आधार पर किसी पालिसी पर तीन वर्ष के पश्चात् आक्षेप न किया

(2) किसी जीवन बीमा पालिसी पर, पालिसी के निर्गमित किए जाने की तारीख से या जोखिम प्रारंभ होने की तारीख से या पालिसी के पुनर्जीवित होने की तारीख से या पालिसी में राइडर जोड़े जाने की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, कपट के आधार पर तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय आक्षेप किया जा सकेगा:

परन्तु बीमाकर्ता को लिखित में बीमाकृत या बीमाकृत के विधिक प्रतिनिधियों या नामनिर्देशितियों या समनुदेशितियों को, वे आधार और तथ्य, जिन पर ऐसा विनिश्चय आधारित है, संसूचित करने होंगे।

स्पष्टीकरण 1 — इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''कपट'' पद से बीमाकृत द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पालिसी निर्गमित करने के आशय से निम्नलिखित में से किया गया कोई कृत्य अभिप्रेत है:—

- (क) उस आशय के तथ्य के रूप में ऐसा जो सत्य नहीं है और जिसे बीमाकृत सत्य होने का विश्वास नहीं करता है:
- (ख) बीमाकृत द्वारा तथ्य की जानकारी और विश्वास रखते हुए तथ्य का सिक्रय छिपाव;

- (ग) कोई अन्य कृत्य जो धोखा देने के क्षम हो; और
- (घ) ऐसा कोई कृत्य या लोप जिसे विधि विशेष रूप से कपटपूर्ण घोषित करे।

स्पष्टीकरण 2 — ऐसे तथ्यों के बारे में मात्र मौन रहना, जिनसे बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के निर्धारण के प्रभावित होने की संभावना हो तब तक कपट नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियां ऐसी न हों कि यदि उन पर ध्यान दिया जाए तो बीमाकृत या उसके अभिकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह बोलने से मौन रहे या जब तक कि उसका मौन रहना स्वत्: ही बोलने के समतुल्य न हो।

(3) उपधारा (2) में किसी बात होते हुए भी, कोई बीमाकर्ता कपट के आधार पर किसी जीवन बीमा पालिसी को निराकृत नहीं करेगा, यदि बीमाकृत यह साबित कर सकता है कि सारवान् तथ्य का मिथ्या कथन करना या छिपाया जाना उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही था या यह कि उस तथ्य को छिपाए जाने का कोई विमर्शित आशय नहीं था या यह कि सारवान् तथ्य का ऐसा मिथ्या कथन या छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

परंतु कपट की दशा में, यदि पालिसीधारी जीवित नहीं है तो झूठ को नासाबित करने का भार हिताधिकारियों पर होता है।

स्पष्टीकरण — कोई व्यक्ति, जो बीमा की संविदा की याचना करता है या बातचीत करता है, संविदा करने के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का अभिकर्ता समझा जाएगा।

(4) किसी जीवन बीमा पालिसी पर, पालिसी निर्गमित करने की तारीख से या जोखिम के प्रारंभ होने की तारीख से या पालिसी के पुनर्जीवित होने की तारीख से या पालिसी में राइडर जोड़े जाने की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, इस आधार पर कि बीमाकृत के जीवन की प्रत्याशा के बारे में सारवान् तथ्य के किसी कथन को छिपाने का कथन प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेज पर गलत ढंग से किया गया था जिस पर पालिसी जारी की गई थी या पुनर्जीवित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय आक्षेप किया जा सकेगा:

परन्तु बीमाकर्ता को बीमाकृत या बीमाकृत के विधिक प्रतिनिधियों या नामनिर्देशितियों या समनुदेशितियों को वे आधार और सामग्री, जिन पर जीवन बीमा की पालिसी को निराकृत करने का ऐसा विनिश्चय आधारित है, लिखित में संसूचित करनी पड़ेगी:

परन्तु यह और कि मिथ्या कथन या सारवान् तथ्य को छिपाने के आधार पर पालिसी के निराकरण की दशा में, न कि कपट के आधार पर, निराकरण की तारीख तक पालिसी पर संगृहीत प्रीमियम बीमाकृत या विधिक प्रतिनिधियों या नामनिर्देशितियों या समनुदेशितियों को ऐसे निराकरण की तारीख से नब्बे दिन की अविध के भीतर संदत्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण — इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए तथ्य का मिथ्या कथन या छिपाया जाना तब तक सारवान् नहीं समझा जाएगा जब तक बीमाकर्ता द्वारा वचनबद्ध किए गए जोखिम पर उसका सीधा संबंध न हो, बीमाकर्ता पर यह दर्शित करने का भार है कि क्या बीमाकर्ता उक्त तथ्य से अवगत था कि बीमाकृत को कोई जीवन बीमा पालिसी निर्गमित नहीं की गई थी।

- (5) इस धारा की किसी बात से बीमाकर्ता किसी भी समय आयु का सबूत उस दशा में मांगने से निवारित नहीं होगा यदि वह ऐसा करने का हकदार हो और किसी भी पालिसी को केवल इस कारण प्रश्नगत किया गया नहीं समझा जाएगा कि पालिसी के निबन्धन बाद में यह साबित किए जाने पर कि जिस व्यक्ति के जीवन का बीमा किया गया है उसकी आयु प्रस्थापना में गलत बताई गई थी, ठीक कर लिए गए हैं।''।
- 56. बीमा अधिनियम की धारा 47क और धारा 48 का लोप किया जाएगा।
- 57. बीमा अधिनियम की धारा ४८क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 47क और धारा 48 का लोप। धारा 48क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। ''48क. कोई भी बीमा अभिकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती बीमा कंपनी में निदेशक होने के लिए न तो पात्र होगा और न निदेशक रहेगा:

बीमा अभिकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती का बीमा कंपनी में निदेशक न होना।

परन्तु बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ पर पद धारण करने वाला कोई भी निदेशक इस धारा के कारण निदेशक रहने के लिए तब तक अपात्र नहीं होगा जब तक कि उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास समाप्त न हो गए हों:

परन्तु यह और कि प्राधिकरण किसी अभिकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती को, किसी बीमा कंपनी के बोर्ड में, ऐसी शर्ती या निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो वह पालिसीधारियों के हित का संरक्षण करने के लिए या हितों के परस्पर विरोध के निवारण के लिए अधिरोपित करे, रहने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।''।

58. बीमा अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) में,—

धारा ४१ का संशोधन।

- (i) ''धारा 2 के खंड (9) के उपखंड (क) (ii) या उपखंड (ख) में विनिर्दिष्ट कोई भी बीमाकर्ता'' शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;
- (ii) ''की या इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ ऐक्ट, 1912 की धारा 11 के अधीन केन्द्रीय सरकार'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।
- **59.** बीमा अधिनियम की धारा 52 और धारा 52क के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 52 और धारा 52क के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन। विभाजन सिद्धान्त पर कारबार करने

''52. कोई भी बीमाकर्ता विभाजन सिद्धांत पर कोई कारबार आरंभ नहीं करेगा अर्थात् इस सिद्धांत पर कि पालिसी द्वारा प्रतिभूत फायदा नियत न होकर या तो पूर्णत्ः या भागत्ः उन पालिसियों के बीच कुछ धनराशियों के वितरण के परिणाम पर निर्भर करता है जो किसी समय–सीमा के अंदर दावे का रूप ग्रहण कर लेती है या इस सिद्धांत पर कि पालिसीधारी द्वारा देय प्रीमियम पूर्णत्ः या भागत्ः उन पालिसियों की संख्या पर निर्भर करती है, जो कितपय समय–सीमा के अंदर दावे का रूप ग्रहण कर लेती है:

ावभाजन ।सद्धान्त पर कारबार करने का प्रतिषेध।

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि किसी नियतकालिक बीमा मूल्यांकन के परिणामस्वरूप वह या तो बीमाकृत राशियों में प्रतिवर्ती अभिवृद्धि के रूप में या तुरंत नकद बोनसों के रूप में या अन्यथा बोनसों का आबंटन जीवन बीमा पालिसियों के धारकों में करने से बीमाकर्ता को निवारित करती है।

52क. (1) यदि किसी समय प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जीवन बीमा कारबार करने वाला बीमाकर्ता ऐसी रीति से कार्य कर रहा है जिससे जीवन बीमा पालिसी के धारकों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है तो वह बीमाकर्ता को सुनवाई का ऐसा अवसर देने के पश्चात् प्राधिकरण के निदेशन और नियंत्रण के अधीन बीमाकर्ता के कार्यों का प्रबंध करने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकेगा।

बीमा कारबार के प्रबंध के लिए प्रशासक कब नियुक्त किया जा सकेगा।

- (2) प्रशासक को ऐसा पारिश्रमिक मिलेगा जो प्राधिकरण निदेश दे और प्राधिकरण किसी समय नियुक्ति को रद्द कर सकेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगा।''।
- 60. बीमा अधिनियम की धारा 52खख में.-

धारा 52खख का संशोधन।

- (क) उपधारा (2) में, ''केन्द्रीय सरकार को उस तारीख से चौदह दिन के अंदर कर सकेगा जिसको उस आदेश की तामील उस पर की गई हो और केन्द्रीय सरकार'' शब्दों के स्थान पर, ''प्रतिभूति अपील अधिकरण को, उस तारीख से चौदह दिन के भीतर कर सकेगा, जिसको उस आदेश की तामील उस पर की गई हो और प्रतिभृति अपील अधिकरण'' शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) उपधारा (3) में, ''केन्द्रीय सरकार'' शब्दों के स्थान पर, ''प्रतिभूति अपील अधिकरण'' शब्द रखे जाएंगे:
 - (ग) उपधारा (10) के खंड (क) में, ''या केन्द्रीय सरकार'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 52घ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। 61. बीमा अधिनियम की धारा 52घ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

प्रशासक की नियुक्ति का पर्यवसान।

"52घ. यदि किसी समय प्राधिकरण को यह प्रतीत होता है कि प्रशासक की नियुक्ति करने वाले आदेश के प्रयोजन की पूर्ति हो गई है या किसी कारण से यह अवांछनीय हो गया है कि नियुक्ति का आदेश प्रवृत्त बना रहे तो प्राधिकरण उस आदेश को रद्द कर सकेगा और तदुपरांत प्रशासक बीमा कारबार के प्रबंध से निर्निहित हो जाएगा और जब तक प्राधिकरण द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, वह पुन: उस व्यक्ति में, जिसमें वह प्रशासक की नियुक्ति के ठीक पूर्व निहित था या बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति में निहित हो जाएगा।"।

धारा 52ङ का संशोधन। 62. बीमा अधिनियम की धारा 52ङ में ''केन्द्रीय सरकार'' शब्दों के स्थान पर, ''प्राधिकरण'' शब्द रखा जाएगा।

धारा 52च का संशोधन। 63. बीमा अधिनियम की धारा 52च में, ''वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर, ''वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, दस हजार रुपए की या दस लाख रुपए की, इनमें से जो भी कम हो, शास्ति का दायी होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 52छ का संशोधन। **64.** बीमा अधिनियम की धारा 52छ की उपधारा (2) में, ''केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 52ज, धारा 52झ, धारा 52ज, धारा 52ट, धारा 52ठ, धारा 52ड और धारा 52ढ का लोप। **65.** बीमा अधिनियम की धारा 52ज, धारा 52झ, धारा 52ञ, धारा 52ट, धारा 52ट, धारा 52ट और धारा 52ढ का लोप किया जाएगा।

धारा 53 का संशोधन।

- 66. बीमा अधिनियम की धारा 53 में,—
 - (क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, अंत में, अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'स्पष्टीकरण—धारा 53 से धारा 61क के प्रयोजन के लिए, ''अधिकरण'' से ''कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण'' अभिप्रेत है।':

2013 का 18

(ख) उपधारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (i) का लोप किया जाएगा।

धारा 58 का संशोधन। 67. बीमा अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात:—

"(4) इस धारा के अधीन ऐसी किसी स्कीम को पुष्ट करने वाला अधिकरण का कोई आदेश, जिससे कंपनी के उद्देश्यों की बाबत उसके ज्ञापन में परिवर्तन किया गया है, परिवर्तनों की बाबत ऐसे प्रभावी होगा मानो वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन पुष्ट किया गया आदेश हो और उस अधिनियम की धारा 7 और धारा 17 के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।"।

2013 का 18

धारा 59 का लोप।

68. बीमा अधिनियम की धारा 59 का लोप किया जाएगा।

शीर्ष का संशोधन।

69. बीमा अधिनियम के भाग 2क में, ''भारतीय बीमा संगम, संगम की परिषदें और उनकी समितियां'' शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:—

''जीवन बीमा परिषद् और साधारण बीमा परिषद् और उनकी समितियां''।

धारा 64क और धारा 64ख का लोप। 70. बीमा अधिनियम की धारा 64क और धारा 64ख का लोप किया जाएगा।

71. बीमा अधिनियम की धारा 64ग और धारा 64घ के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:— धारा 64ग और धारा 64घ के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन। जीवन बीमा और साधारण बीमा परिषदुं।

- ''64ग. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,—
- (क) विद्यमान जीवन बीमा परिषद्, बीमाकर्ताओं के प्रतिनिधि निकाय को, जो भारत में जीवन बीमा कारबार कर रहा है; और
- (ख) विद्यमान साधारण बीमा परिषद्, बीमाकर्ताओं के प्रतिनिधि निकाय को, जो भारत में साधारण बीमा, स्वास्थ्य बीमा कारबार और पुनर्बीमा कारबार कर रहा है,

इस अधिनियम के अधीन संबंधित परिषदों के रूप में गठित किया गया समझा जाएगा।

64घ. जीवन बीमा परिषद् या साधारण बीमा परिषद् के किसी सदस्य के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह संपृक्त परिषद् की किसी बैठक में ऐसे सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी अधिकारी को प्राधिकृत करे।''। परिषदों में प्रतिनिधित्व करने का प्राधिकार।

72. बीमा अधिनियम की धारा 64च के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 64च के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। जीवन बीमा परिषद् और साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका समितियां।

- ''64च. (1) जीवन बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—
 - (क) जीवन बीमा परिषद् के सदस्यों के चार प्रतिनिधि, जो उक्त सदस्यों द्वारा अपनी व्यध्टिक हैसियत में ऐसी रीति से निर्वाचित किए जाएंगे, जो परिषद् की उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;
 - (ख) प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रख्यात व्यक्ति, जो बीमा कारबार से संबद्ध न हो; और
 - (ग) क्रमशः बीमा अभिकर्ताओं, मध्यवर्तियों और पालिसीधारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए;
 - (घ) स्व-साहाय्य समूहों और बीमा सहकारी सोसाइटियों में से प्रत्येक के एक-एक प्रतिनिधि:

परन्तु खंड (क) में यथावर्णित प्रतिनिधियों में से एक को जीवन बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाएगा।

- (2) साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका सिमिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात:—
 - (क) साधारण बीमा परिषद् के सदस्यों के चार प्रतिनिधि, जो उक्त सदस्यों द्वारा अपनी व्यध्यिक हैसियत में ऐसी रीति से निर्वाचित किए जाएंगे, जो परिषद् की उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए:
 - (ख) प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रख्यात व्यक्ति, जो बीमा कारबार से संबद्ध न हो:
 - (ग) क्रमश: बीमा अभिकर्ताओं, अन्य पक्षकार प्रशासकों, सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों तथा पालिसीधारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार व्यक्ति, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु खंड (क) में वर्णित प्रतिनिधियों में से एक को साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका

समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाएगा।

- (3) यदि उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कोई व्यष्टि निकाय जीवन बीमा परिषद् या साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका समितियों के सदस्यों में से किसी का निर्वाचन करने में असफल रहता है तो प्राधिकरण उस रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति, यथास्थिति, जीवन बीमा परिषद् या साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति का इस प्रकार सदस्य समझा जाएगा मानो उसे उसमें सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया हो।
- (4) उक्त कार्यपालिका सिमितियों में से प्रत्येक उक्त सिमिति, उक्त सिमिति के किसी अधिवेशन में किसी कारबार के संव्यवहार के लिए उपविधियां तैयार कर सकेगी।
- (5) जीवन बीमा परिषद् या साधारण बीमा परिषद् ऐसे व्यक्तियों को मिलकर ऐसी अन्य समितियां बना सकेगी, जो वह ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए ठीक समझे, जो उन्हे प्रत्यायोजित किए जाएं।
- (6) जीवन बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति और साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति के सचिव की नियुक्ति प्रत्येक मामले में संबंधित कार्यपालिका समिति द्वारा की जाएगी:

परन्तु संबंधित कार्यपालिका सिमिति द्वारा नियुक्त प्रत्येक सिचव ऐसी सभी शिक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे सभी कृत्य करेगा, जो संबंधित कार्यपालिका सिमिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाएं।"।

धारा 64छ का संशोधन। 73. बीमा अधिनियम की धारा 64छ की उपधारा (2) में, ''प्राधिकरण द्वारा किए गए नामनिर्देशन से भरी जाएंगी'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसी रीति से भरी जाएंगी, जो संबंधित परिषद् की उपविधियों में अधिकथित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 64झ का लोप।

- 74. बीमा अधिनियम की धारा 64झ का लोप किया जाएगा।
- धारा ६४ञ का संशोधन।
- 75. बीमा अधिनियम की धारा 64ञ की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
 - "(2) जीवन बीमा परिषद् की कार्यपालिका सिमिति, अपने कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में अपने को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए जीवन बीमा का कारबार करने वाले बीमाकर्ताओं से ऐसी फीस संगृहीत कर सकेगी, जो परिषद् द्वारा बनाई गई उपविधियों में अधिकथित की जाए।"

धारा 64ठ का संशोधन।

- **76**. बीमा अधिनियम की धारा 64ठ की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात:—
 - "(2) साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति अपने कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में अपने को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए साधारण बीमा का कारबार करने वाले बीमाकर्ताओं से ऐसी फीस संगृहीत कर सकेगी जो परिषद् द्वारा बनाई गई उपविधियों में अधिकथित की जाए।"।

धारा 64ढ का संशोधन। 77. बीमा अधिनियम की धारा 64ढ में, ''केंद्रीय सरकार वे परिस्थितियां जिनमें, वह रीति जिससे, और वे शर्तें, जिन पर जीवन बीमा परिषद् की कार्यपालिका सिमिति और साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका सिमिति दोनों सिमितियों के सामान्य हित की बात के संबंध में कार्यवाही करने के प्रयोजन से संयुक्त अधिवेशन कर सकेंगी, विहित कर सकेगी'' शब्दों के स्थान पर, ''प्राधिकरण वे परिस्थितियां जिनमें, वह रीति जिससे, और वे शर्तें, जिन पर जीवन बीमा परिषद् की कार्यपालिका सिमिति और साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका सिमिति दोनों सिमितियों के सामान्य हित की बात के संबंध में कार्यवाही करने के प्रयोजन से संयुक्त अधिवेशन कर सकेंगी, विनिर्दिष्ट कर सकेगा,'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 64द का संशोधन। 78. बीमा अधिनियम की धारा 64द की उपधारा (1) में,—

- (क) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
- ''(ग) उन सभी बीमाकर्ताओं की, जो किसी भी परिषद् के सदस्य हैं, सूची की अद्यतन प्रति रख सकेगी और बनाए रख सकेगी।'':
- (ख) खंड (घ) में, आरंभिक भाग में ''प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से'' और अंत में,दीर्घ पंक्ति में, ''विनियम बना सकेगी'' शब्दों के स्थान पर आरंभिक भाग में ''निम्नलिखित के लिए'' और अंत में, दीर्घ पंक्ति में, ''उपविधियां बना सकेगी'' शब्द रखे जाएंगे।
- 79. बीमा अधिनियम की धारा 64ध और धारा 64न का लोप किया जाएगा।

80. बीमा अधिनियम की धारा 64प, धारा 64पक, धारा 64पख, धारा 64पग, धारा 64पघ, धारा 64पइ, धारा 64पच, धारा 64पछ, धारा 64पज, धारा 64पज, धारा 64पज, धारा 64पठ और धारा 64पठ का लोप किया जाएगा।

धारा ६४४ और धारा ६४न का लोप। धारा ६४५, धारा ६४५क, धारा ६४५व, धारा ६४५व और धारा ६४५व

81. बीमा अधिनियम की धारा 64पठ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नई धारा ६४पठ का अंत:स्थापन। संक्रमणकालीन उपबंध।

- "64पठक. (1) इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, जब तक धारा 64पग के अधीन सलाहकार सिमित द्वारा अधिकथित दरों, फायदों और निबंधनों तथा शर्तों को प्राधिकरण द्वारा उस तारीख से, जो प्राधिकरण राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अवधारित करे, अधिसूचना से निकाला नहीं जाता है और दरों, फायदों और निबंधनों तथा शर्तों को संबंधित बीमाकर्ता द्वारा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है, तब तक सलाहकार सिमित द्वारा अधिसूचित दरें, फायदे और निबंधन तथा शर्तें प्रवृत्त बनी रहेंगी और सदैव प्रवृत्त बनी रही समझी जाएंगी तथा कोई भी ऐसी दरें, फायदे और निबंधन तथा शर्तें सभी बीमाकर्ताओं पर बाध्य होंगी।
- (2) प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के परामर्श से, टैरिफ सलाहकार समिति के विघटन पर, उसके विद्यमान कर्मचारियों के लिए, ऐसे कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह आदेश द्वारा अवधारित करे, एक स्कीम तैयार करेगा।''।
- 82. बीमा अधिनियम की धारा 64पड के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थातु:—

धारा 64पड के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। सर्वेक्षक और हानि

निर्धारक।

- "64पड (1) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, कोई भी व्यक्ति बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से एक वर्ष की अविध की समाप्ति के पश्चात् साधारण बीमा कारबार की बाबत तब तक सर्वेक्षक या हानि निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करेगा, जब तक कि वह—
 - (क) ऐसी शैक्षिक अर्हताएं धारण न करता हो, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;
 - (ख) सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के किसी वृत्तिक निकाय का, अर्थात्, भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान का सदस्य न हो:

परंतु किसी फर्म या कंपनी की दशा में, ऐसे सभी भागीदार या निदेशक या अन्य व्यक्ति, जिनसे, यथास्थिति, रिपोर्टित हानि का सर्वेक्षण या निर्धारण करने की अपेक्षा की जाए, खंड (क) और खंड (ख) की अपेक्षाओं को पुरा करेंगे।

(2) प्रत्येक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक अपने उन कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और अन्य वृत्तिक अपेक्षाओं की बाबत, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, आचार संहिता का पालन करेगा।

(3) पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से पूर्व किसी अनुज्ञप्त सर्वेक्षक या हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों का कोई वर्ग या के वर्ग उस अविध के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उस रूप में कार्य करता रहेगा या रहेंगे:

परंतु सर्वेक्षक या हानि निर्धारक उस अवधि के भीतर, जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जाए, उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) की अपेक्षाओं को पूरा करेगा, जिसमें असफल रहने पर सर्वेक्षक या हानि निर्धारक स्वत: ही सर्वेक्षक या हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए निर्राहत हो जाएगा।

(4) किसी भी बीमा पालिसी के संबंध में किसी हानि की बाबत, जो भारत में हुई हो, प्राधिकरण द्वारा विनियमों में विनिर्दिष्ट रकम के बराबर या उससे अधिक के मूल्य का ऐसा दावा, जिसका भारत में संदाय या तय किया जाना अपेक्षित हो और जो बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय उद्भूत हुआ हो या बीमाकर्ता को प्रज्ञापित किया गया हो, यदि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए तो, बीमाकर्ता द्वारा संदाय या तय किए जाने के लिए तभी ग्रहण किया जाएगा जबकि उसने उस हानि की बाबत, जो हुई है, ऐसे व्यक्ति से रिपोर्ट अभिप्राप्त नहीं की है जो सर्वेक्षक या हानि निर्धारक के रूप में (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''अनुमोदित सर्वेक्षक या हानि निर्धारक'' कहा गया है) कार्य करने के लिए इस धारा के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति धारण किए हुए है, अन्यथा ग्रहण नहीं किया जाएगा:

परन्तु इस उपधारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह अनुमोदित सर्वेक्षक या हानि निर्धारक द्वारा निर्धारित रकम से भिन्न किसी रकम पर किसी दावे का संदाय करने या उसे तय करने के बीमाकर्ता के अधिकार को छीनती है या न्यून करती है।

- (5) प्राधिकरण किसी भी समय उपधारा (4) में निर्दिष्ट स्वरूप के किसी दावे की बाबत कोई स्वतंत्र रिपोर्ट अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अनुमोदित सर्वेक्षक या हानि निर्धारक से मांग सकेगा और ऐसा सर्वेक्षक या हानि निर्धारक उतने समय के अन्दर जितना प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या उस दशा में, जबिक कोई समय सीमा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, उचित समय के अन्दर, प्राधिकरण को ऐसी रिपोर्ट देगा और ऐसी रिपोर्ट का खर्चा या उससे संबंधित खर्चा बीमाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
- (6) प्राधिकरण उपधारा (5) में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर दावा तय किए जाने से संबंधित ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे और ऐसे निर्देशों के अन्तर्गत किसी दावे के तय किए जाने से संबद्ध ऐसा निर्देश भी है जो ऐसी रकम से कम या अधिक की बाबत होगा जिस पर उसे तय करने की प्रस्थापना हो या जिस पर वह तय किया गया हो और बीमाकर्ता ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा:

परन्तु जहां प्राधिकरण किसी दावे को उससे कम रकम पर तय करने का निदेश देता है जिस पर वह पहले तय किया गया है, वहां बीमाकर्ता के बारे में यह बात कि उसने निदेश का अनुपालन कर दिया है उस दशा में समझी जाएगी जब वह प्राधिकरण का यह समाधान कर दे कि इस बात का सम्यक् ध्यान रखते हुए उसने सम्यक् शीघ्रता से सभी उचित कदम उठा लिए हैं कि उसमें होने वाला व्यय उस रकम के अननुपात में तो नहीं है जो वसुल की जानी है:

परन्तु यह और कि जहां दावे की रकम पहले ही चुका दी गई है और प्राधिकरण की यह राय है कि जितनी रकम अधिक दी गई है उसकी वसूली से बीमाकृत को असम्यक् कठिनाई होगी वहां कम रकम के संदाय का कोई भी निदेश नहीं दिया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि इस धारा की किसी बात से बीमाकर्ता ऐसे किसी सिविल या आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं होगा जिसके अधीन वह उस दशा में होता जबकि इस उपधारा के उपबंध न होते।

(7) कोई भी बीमाकर्ता बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से एक वर्ष की अविध की समाप्ति के पश्चातु बीमा पालिसी के अधीन हानि के दावे के सर्वेक्षण या सत्यापन के लिए या उसके बारे में रिपोर्ट देने के लिए कोई भी फीस या पारिश्रमिक किसी व्यक्ति को तभी देगा जबकि ऐसा सर्वेक्षण, सत्यापन या रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति अनुमोदित सर्वेक्षक या हानि निर्धारक हो, अन्यथा नहीं।

- (8) जहां किसी बीमा पालिसी पर उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट रकम से कम मूल्य के दावे के मामले में बीमाकर्ता के लिए यह साध्य नहीं है कि वह उस दावे की रकम से अननुपातिक व्यय उपगत किए बिना अनुमोदित सर्वेक्षक या हानि निर्धारक को नियोजित करे वहां बीमाकर्ता किसी अन्य व्यक्ति को (जो सर्वेक्षक या हानि निर्धारक के रूप में नियोजित किए जाने के लिए तत्समय निरिहंत व्यक्ति नहीं है), ऐसी हानि का सर्वेक्षण करने के लिए नियोजित कर सकेगा और ऐसे नियोजित व्यक्ति को उतनी उचित फीस या पारिश्रमिक दे सकेगा जितना वह ठीक समझे।
- (9) प्राधिकरण किसी बीमा पालिसी पर उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट रकम से कम मूल्य के किसी दावे की बाबत, उस दशा में जबिक सर्वेक्षक या हानि निर्धारक ने उसे दावे की बाबत रिपोर्ट नहीं दी है या दिए जाने की प्रस्थापना नहीं की है, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे दावे की रिपोर्ट अनुमोदित सर्वेक्षक या हानि निर्धारक द्वारा दी जाए और जहां प्राधिकरण ऐसा कोई निदेश देता है वहां उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबंध उस दावे की बाबत लागू होंगे।
- (10) जहां किसी वर्ग के दावों के संबंध में प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि सर्वेक्षण या हानि निर्धारण का काम अनुज्ञप्त सर्वेक्षक या हानि निर्धारक से भिन्न किसी व्यक्ति को सौंप दिया जाना रुढ़िगत है या कोई सर्वेक्षण या हानि निर्धारण साध्य नहीं है वहां वह, आदेश द्वारा, ऐसे वर्ग के दावों को इस धारा के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।''।
- 83. बीमा अधिनियम की धारा 64फ और धारा 64फक के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 64फ और धारा 64फक के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

"64फ. (1) धारा 64फक के उपबंधों का अनुपालन अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, आस्तियों का मूल्यांकन ऐसे मूल्य पर किया जाएगा, जो उनके बाजार या वसूलीय मूल्य से अधिक न हो और कितपय आस्तियों को प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में, अपवर्जित किया जा सकेगा जो इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

आस्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन कैसे किया जाए।

- (2) बीमाकर्ता के दायित्व की प्रत्येक मद का ऐसी रीति में समुचित मूल्य लगाया जाएगा जो इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।
- (3) प्रत्येक बीमाकर्ता, यथास्थिति, साधारण बीमा कारबार के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षक द्वारा या जीवन बीमा कारबार के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बीमांकक द्वारा प्रमाणित अपनी आस्तियों और दायित्वों का विवरण, जिनका इस धारा द्वारा अपेक्षित रीति से निर्धारण प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को किया गया है, इस अधिनियम के अधीन फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणियों के साथ ऐसे समय के भीतर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएं, प्राधिकरण को देगा।
- 64फक. (1) प्रत्येक बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता सदैव अपने दायित्वों की रकम के ऊपर अपनी आस्तियों का मूल्य इतना अधिक बनाए रखेगा, जो धारा 6 के अधीन यथाकथित और विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से निकाली गई न्यूनतम पूंजी की रकम के पचास प्रतिशत से कम न हो।

आस्तियों की पर्याप्तता।

- (2) यथास्थिति, किसी ऐसे बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता को, जो उपधारा (1) का अनुपालन नहीं करता, दिवालिया समझा जाएगा और प्राधिकरण द्वारा किए गए आवेदन पर न्यायालय द्वारा परिसमापन किया जा सकेगा।
- (3) प्राधिकरण, इस प्रयोजन के लिए बनाए गए विनियम के रूप में, शोधन क्षमता के नियंत्रण स्तर के नाम से ज्ञात शोधन क्षमता मार्जिन का स्तर विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके भंग होने पर प्राधिकरण किन्हीं अन्य उपचारात्मक उपायों पर, जो वह ठीक समझे, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार कार्य करेगा:

परंतु यदि किसी बीमाकर्ता की बाबत प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि इस उपधारा के उपबंधों का अनुपालन करने से बीमाकर्ता को या तो प्रतिकूल दावा विषयक अनुभव के कारण या नए कारबार की मात्रा में तीव्र वृद्धि के कारण या किसी अन्य कारण से, असम्यक्, कठिनाई होगी तो वह यह निदेश दे सकेगा कि इस उपधारा के उपबंध इतनी अविध के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, उस बीमाकर्ता को ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होंगे:

परंतु यह तब जब कि उपांतरणों के परिणामस्वरूप शोधन क्षमता का नियंत्रण स्तर उससे कम न हो, जो उपधारा (1) के अधीन अनुबंधित है।

- (4) यदि, कोई बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता किसी समय, शोधन क्षमता मार्जिन का अपेक्षित नियंत्रण स्तर बनाए नहीं रखता है, तो वह प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार प्राधिकरण को एक वित्तीय योजना, छह मास से अनिधक की विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, कमी को दूर करने के लिए एक कार्य-योजना उपदर्शित करते हुए, प्रस्तुत करेगा।
- (5) ऐसा कोई बीमाकर्ता, जिसने उपधारा (4) के अधीन यथा अपेक्षित योजना प्राधिकरण को प्रस्तुत की है, योजना में उपांतरणों का यदि प्राधिकरण उसे अपर्याप्त समझे, प्रस्ताव करेगा और ऐसे किसी घटनाक्रम में प्राधिकरण ऐसे निदेश जिनके अंतर्गत किसी नए कारबार को करने या किसी प्रशासक की नियुक्ति या दोनों करने से संबंधित निदेश भी है, दे सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।
- (6) यथास्थिति, ऐसे किसी बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता के बारे में, जो उपधारा (4) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता, यह समझा जाएगा कि उसने इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया है।
- (7) प्राधिकरण, किसी बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता की आस्तियों और दायित्वों का निरीक्षण या सत्यापन करने के लिए या यह सिद्ध करने के लिए कि इस धारा की अपेक्षाओं का किसी विशेष तारीख को अनुपालन कर दिया गया है, आवश्यक विशिष्टियां अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी समय, ऐसे कदम उठाने का हकदार होगा, जो वह आवश्यक समझे और, यथास्थित, बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त की गई किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा तथा यदि वह अध्यपेक्षा की प्राप्ति से दो मास के भीतर ऐसा करने में सफल नहीं होता है तो, यथास्थिति, बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया है।
- (8) उपधारा (1) के उपबंधों को, यथास्थित, ऐसे किसी बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता को लागू करने में, जो किसी समूह का सदस्य है, उस बीमाकर्ता के लिए सुसंगत रकम वह होगी जिसका उस सुसंगत रकम के उस अनुपात के बराबर रकम, से जिसका ऐसे समूह द्वारा, यदि उसे एकल बीमाकर्ता समझा जाता, वही अनुपात होगा जो कि समूह द्वारा निर्गमित प्रत्येक पालिसी पर कुल जोखिम से ऐसे बीमाकर्ता के जोखिम के भाग का है:

परंतु जब बीमाकर्ताओं का कोई समूह, समूह नहीं रह जाता है, तो उस समूह में का प्रत्येक ऐसा बीमाकर्ता, जो भारत में किसी वर्ग का बीमा कारबार करना जारी रखता है, उपधारा (1) की अपेक्षाओं का इस प्रकार अनुपालन करेगा मानो वह किसी समय किसी समूह का बीमाकर्ता न रहा हो:

परंतु यह और कि यह पूर्वगामी परंतुक के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन होगा, यदि बीमाकर्ता अपने दायित्वों की रकम के ऊपर अपनी आस्तियों के मूल्य के अधिक्य को समूह के अस्तित्व में न रहने की तारीख से छह मास के भीतर अपेक्षित रकम तक ले आता है:

परंतु यह भी कि प्राधिकरण पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर, छह मास की उक्त अवधि को ऐसी और अवधियों तक बढ़ा सकेगा, जो वह ठीक समझे, किंतु यह कि इस प्रकार कुल अवधि किसी भी दशा में एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकेगी।

(9) प्रत्येक बीमाकर्ता प्राधिकरण को, शोधन क्षमता मार्जिन के ब्यौरे देने संबंधी विवरणी, ऐसे प्ररूप, समय, ऐसी रीति में, जिसके अन्तर्गत उसका अधिप्रमाणन भी है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करेगा।''।

84. बीमा अधिनियम की धारा 64फग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 64फग के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"64फग. कोई भी बीमाकर्ता, बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1968 के प्रारंभ के पश्चात् न तो भारत में और न भारत के बाहर कारबार का कोई नया स्थान खोलेगा और न बंद करेगा और न भारत में या भारत के बाहर स्थित कारबार के किसी विद्यमान स्थान की अवस्थिति को, विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रीति में के सिवाय, उसी शहर, नगर या ग्राम से अन्यत्र बदलेगा।"।

कारबार का नया स्थान खोलने पर निर्बंधन।

85. बीमा अधिनियम के भाग 3 और भाग 3क का लोप किया जाएगा।

भाग 3 और भाग 3क का लोप।

86. बीमा अधिनियम के भाग 4 का लोप किया जाएगा।

भाग 4 का लोप।

87. बीमा अधिनियम की धारा 102 में, ''ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए पांच लाख रुपए से अधिक की नहीं होगी, दायी होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है, एक लाख रुपए या एक करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 102 का संशोधन।

88. बीमा अधिनियम की धारा 103 और धारा 104 के स्थान पर, निम्निलखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:— धारा 103 और धारा 104 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

''103. यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना, बीमा कारबार करेगा, तो वह ऐसी शास्ति से जो पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक की नहीं होगी, और कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। प्रतिस्थापन। धारा 3 के उल्लंघन में बीमा कारबार करने के लिए शास्ति।

104. यदि कोई व्यक्ति धारा 27, धारा 27क, धारा 27ख, धारा 27घ और धारा 27ङ के उपबंधों का पालन करने में असफल रहेगा, तो वह ऐसी शास्ति का, जो पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक की नहीं होगी, दायी होगा।''।

धारा 27, धारा 27क, धारा 27ख, धारा 27घ और धारा 27ङ के उल्लंघन के लिए शास्ति।

89. बीमा अधिनियम की धारा 105 में, ''ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए दो लाख रुपए से अधिक की नहीं होगी'' शब्दों के स्थान पर, ''एक करोड रुपए से अधिक की नहीं होगी'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 105 का संशोधन।

90. बीमा अधिनियम की धारा 105ख और धारा 105ग के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:— धारा 105ख और धारा 105ग के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

''105ख. यदि कोई बीमाकर्ता धारा 32ख, धारा 32ग और धारा 32घ के उपबंधों का पालन करने में असफल रहेगा तो वह शास्ति का, जो पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक की नहीं होगी, दायी होगा।

धारा 32ख, धारा 32ग और धारा 32घ का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति। न्यायनिर्णयन की

शक्ति।

105ग. (1) प्राधिकरण, धारा 2गख की उपधारा (2), धारा 34ख की उपधारा (4), धारा 40 की उपधारा (3), धारा 41 की उपधारा (2), धारा 42 की उपधारा (4) और उपधारा (5), धारा 42घ की उपधारा (8) और उपधारा (9), धारा 52च और धारा 105ख के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, ऐसे किसी अधिकारी को, जो संयुक्त निदेशक या समतुल्य अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् विहित रीति में जांच करने के लिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा।

(2) प्राधिकरण, इस प्रकार नियुक्त किए गए अधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, पूर्वोक्त धाराओं में उपबंधित कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। (3) न्यायनिर्णायक अधिकारी को, कोई जांच करते समय, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या ऐसा कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच के लिए उपयोगी हो या उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत हो, समन करने और कराने की शिक्त होगी और यदि ऐसी जांच पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट धाराओं में से किसी के उपबंधों का पालन करने में असफल रहा है तो वह ऐसी शास्ति की सिफारिश कर सकेगा, जो उन धाराओं में से किसी के उपबंधों के अनुसार वह ठीक समझे।

न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले कारक।

- 105घ. धारा 105ग के अधीन शास्ति की मात्रा की सिफारिश करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी और ऐसी शास्ति अधिरोपित करते समय, प्राधिकरण निम्नलिखित कारकों को सम्यक् रूप से ध्यान में रखेगा, अर्थात्:—
 - (क) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप किए गए अननुपातिक अभिलाभ या अनुचित फायदे, जहां कहीं अनुमान्य हों, की रकम,
 - (ख) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप पालिसीधारियों को हुई हानि की रकम; और
 - (ग) व्यतिक्रम की पुनरावृत्त प्रकृति।

धारा 106क का संशोधन।

- 91. बीमा अधिनियम की धारा 106क की उपधारा (2) में,—
 - (i) खंड (क), खंड (ख) और खंड (च) का लोप किया जाएगा;
 - (ii) खंड (घ) में, ''या क्षेमदा सोसाइटी'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 107 और धारा 107क का लोप। धारा 109 के स्थान पर नई धारा का 92. बीमा अधिनियम की धारा 107 और धारा 107क का लोप किया जाएगा।

अपराध का संज्ञान।

प्रतिस्थापन ।

93. बीमा अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 110 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील।

- ''109. कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किन्हीं विनियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, प्राधिकरण के किसी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।''।
- 94. बीमा अधिनियम की धारा 110 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थातु:—
 - ''110. (1) कोई व्यक्ति, जो—
 - (क) बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ पर और उसके पश्चात् या इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश से, या
 - (ख) इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन के रूप में प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश से,

व्यथित है, उस मामले पर अधिकारिता रखने वाले प्रतिभृति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको प्राधिकरण द्वारा किए गए आदेश की प्रति उसके द्वारा प्राप्त की जाती है, पैंतालीस दिन की अविध के भीतर फाइल की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप में होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए:

परंतु यदि प्रतिभूति अपील अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अपील को पैंतालीस दिन की अविध के भीतर फाइल न करने के लिए पर्याप्त कारण था तो वह उसे उस अविध की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण कर सकेगा।

- (3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर, प्रतिभूति अपील अधिकरण अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपांतिरत या अपास्त करते हुए, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- (4) प्रतिभृति अपील अधिकरण, उसके द्वारा किए गए आदेश की प्रति, प्राधिकरण और पक्षकारों को उपलब्ध कराएगा।
- (5) उपधारा (1) के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई अपील पर उसके द्वारा यथासंभव शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई की जाएगी और उसके द्वारा अपील की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर अपील का अंतिम रूप से निपटारा किए जाने का प्रयास किया जाएगा।
 - (6) किसी अपील को फाइल करने और निपटारा करने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए।

1992 का 15

- (7) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15प, धारा 15फ, धारा 15ब, धारा 15म और धारा 15य में अंतर्विष्ट उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों से उद्भूत होने वाली अपीलों को ऐसे लागू होंगे, जैसे वे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन की अपीलों को लागू होते हैं।"।
- 95. बीमा अधिनियम की धारा 110ङका लोप किया जाएगा।

96. बीमा अधिनियम की धारा 110छ और धारा 110ज का लोप किया जाएगा।

धारा 110ङ का लोप। धारा 110छ और धारा 110ज का लोप।

97. बीमा अधिनियम की धारा 110ज के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नई धारा 110जक का अंत:स्थापन।

''110जक. प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।''। शास्ति का भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होना।

98. बीमा अधिनियम की धारा 111 में.—

धारा 111 का संशोधन।

- (क) उपधारा (1) में, ''या क्षेमदा सोसाइटी'' शब्दों का, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा;
 - (ख) उपधारा (2) के परन्तुक में, ''या क्षेमदा सोसाइटी'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
- 99. बीमा अधिनियम की धारा 113 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 113 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। पालिसी द्वारा अभ्यर्पण मृल्य का

अर्जन ।

- ''113. (1) जीवन बीमा की कोई पालिसी, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट सिन्नयमों के अनुसार अभ्यर्पण मूल्य अर्जित करेगी।
- (2) जीवन बीमा की प्रत्येक पालिसी में पालिसी के गारंटीशुदा अभ्यर्पण मूल्य की संगणना के लिए प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित सूत्र अंतर्विष्ट होगा।
- (3) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, असंबद्ध योजना के अधीन जीवन बीमा की ऐसी पालिसी, जिसने अभ्यर्पण मूल्य अर्जित कर लिया है, आगे के प्रीमियमों के असंदाय के कारण व्यपगत नहीं होगी, बल्कि उसे प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित और पालिसी में अंतर्विष्ट सूत्र के माध्यम से परिकलित बीमाकृत समादत्त राशि की सीमा तक और उत्तरभोगी बोनस, जो पालिसी से पहले ही संलग्न है, तक प्रवृत्त रखा जाएगा:

परंतु असंबद्ध योजना के अधीन जीवन बीमा की पालिसी को, उस रीति से प्रवृत्त रखा जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

- (4) उपधारा (3) के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,—
- (i) जहां किसी पालिसी द्वारा बीमाकृत समादत्त राशि, संलग्न बोनसों सहित, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रकम से कम है या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रकम से कम रकम की वार्षिकी का रूप ले लेती है: या
- (ii) जब पक्षकार प्रीमियम के संदाय में व्यतिक्रम होने के पश्चात् लिखित में अन्य ठहराव करने के लिए सहमत हो जाते हैं।"।

धारा 114 का संशोधन।

- 100. बीमा अधिनियम की धारा 114 में,—
 - (क) उपधारा (2) में,—
 - (i) खंड (कक) का लोप किया जाएगा;
 - (ii) खंड (कक), जिसका इस प्रकार लोप किया गया है, के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—
 - "(ककक) धारा 2 के खंड (7क) के उपखंड (ख) के अधीन भारतीय बीमा कंपनी के स्वामित्व और नियंत्रण की रीति:":
 - (iii) खंड (ग) और खंड (च) का लोप किया जाएगा;
 - (iv) खंड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—
 - ''(ठक) धारा 105ग की उपधारा (1) के अधीन जांच की रीति;
 - (ठख) वह प्ररूप, जिसमें धारा 110 की उपधारा (2) के अधीन अपील की जा सकेगी और ऐसी अपील की बाबत संदेय फीस और उसकी उपधारा (6) के अधीन किसी अपील को फाइल करने और उसके निपटारे की प्रक्रिया;'';
- (ख) उपधारा (3) में, ''या धारा 64पख की उपधारा (1) के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम तथा धारा 64पख की उपधारा (3) के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम'' शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर ''बनाया गया प्रत्येक नियम'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 114क का संशोधन।

- 101. बीमा अधिनियम की धारा 114क की उपधारा (2) में,—
 - (i) खंड (क) और खंड (कक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
 - "(क) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की रीति और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज;";
 - (ii) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:--
 - ''(घ) धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण की वार्षिक फीस और उसके संदाय की रीति;'';
 - (iii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—
 - ''(घक) ऐसी न्यूनतम वार्षिकी और अन्य फायदे, जो धारा 4 के अधीन बीमाकर्ता द्वारा प्रतिभृत किए जाएंगे;
 - (घकक) ऐसे प्रारंभिक व्ययों का अवधारण, जिन्हें धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन बीमाकर्ताओं के लिए नियत समादत्त साधारण पूंजी की गणना करने के लिए अपवर्जित किया जा सकेगा;
 - (घख) धारा 6क की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित ऐसी साधारण पूंजी और ऐसे रूप की पूंजी जिसके अंतर्गत मिश्र-पूंजी भी है;'';

- (iv) खंड (ङ) का लोप किया जाएगा;
- (v) खंड (ङ) के पश्चात् , निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
- "(ङक) धारा 10 की उपधारा (1) और उपधारा (2कक) के अधीन यथा अपेक्षित बीमा कारबार के प्रत्येक वर्ग और उपवर्गों की बाबत सभी प्राप्तियों और संदायों के खाते का पृथक्करण; और उक्त धारा के अधीन उसका अधित्यजन ":
- (vi) खंड (च) में, ''धारा 11 की उपधारा (1क) के अधीन'' शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर , ''धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन'' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
 - (vii) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - ''(छ) वह रीति, जिसमें बीमांकक की रिपोर्ट का उद्धरण विनिर्दिष्ट किया जाएगा और वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 13 में निर्दिष्ट विवरण संलग्न किया जाएगा;'';
 - (viii) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
 - ''(छक) धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन पालिसियों और दावों के अभिलेखों का बनाए रखा जाना;
 - (छख) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन पालिसियों को इलैक्ट्रानिक रूप में निर्गमित किए जाने की रीति और प्ररूप;'';
 - (ix) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - ''(ज) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी या उसके किसी भाग की प्रति उपाप्त करने के लिए फीस;'';
 - (x) खंड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - ''(झ) आस्तियों का विनिधान और धारा 27, धारा 27क, धारा 27ख, धारा 27ग के अधीन कतिपय मामलों में किसी बीमाकर्ता द्वारा विनिधानों और बीमाकर्ताओं द्वारा विनिधान के संबंध में और उपबंध तथा धारा 27घ के अधीन आस्तियों के विनिधान का समय, उसकी रीति और अन्य शर्तें;'';
- (xi) खंड (झक), खंड (झख), खंड (झग), खंड (झघ) और खंड (झङ) के स्थान पर, निम्निलखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—
 - "(झक) वह प्ररूप जिसमें किए गए विनिधानों, वह समय और रीति, जिसके अंतर्गत धारा 28 के अधीन उसका अधिप्रमाणन भी है, का ब्यौरा देते हुए विवरणी फाइल की जाएगी;
 - (झख) ऋण, जिसके अंतर्गत धारा 29 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन बीमाकर्ता द्वारा पूर्णकालिक कर्मचारियों को मंजूर किए गए ऋण भी हैं;
 - (झग) धारा 31ख के अधीन बीमाकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को संदाय की जाने वाली धनराशि:
 - (झघ) धारा 32ख और धारा 32ग के अधीन ग्रामीण या सामाजिक या असंगठित सेक्टर और पिछडे वर्गों की बाबत बीमाकर्ता का दायित्व;

- (झङ) धारा 32घ के अधीन मोटर यानों के अन्य पक्षकार के जोखिम में बीमा कारबार की न्यूनतम प्रतिशतता;'';
- (xii) खंड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
- ''(ञ) यथास्थिति, बीमाकर्ताओं या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती द्वारा अपनी पुस्तकों में रखी जाने वाली न्यूनतम जानकारी, वह रीति जिसमें ऐसी जानकारी रखी जाएगी, उस संबंध में जांच तथा अन्य सत्यापन और धारा 33 की उपधारा (7) के अधीन उसके आनुषंगिक सभी अन्य विषय;'';
- (xiii) खंड (अ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—
- "(अक) धारा 35 की उपधारा (3) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन वह प्ररूप जिसमें संबंधित प्रत्येक बीमाकर्ता के बीमा कारबार की बाबत तुलनपत्र और वह रीति, जिसमें जीवन बीमा कारबार की बाबत बीमांकिक रिपोर्टें और उद्धरण तैयार किए जाएंगे;
 - (ञख) धारा 37क की उपधारा (4क) के परंतुक के अधीन प्रतिकर के निर्धारण की रीति;
 - (ञग) धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन बीमाकर्ता द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस;
- (ञघ) धारा 40 के अधीन किसी बीमा अभिकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती को कमीशन के रूप में या अन्यथा पारिश्रमिक या इनाम संदत्त करने या प्राप्त करने की रीति और उनकी रकम;
 - (ञङ) धारा 40ख और धारा 40ग के अधीन प्रबंध के व्ययों की रीति और प्ररूप;'';
- (xiv) खंड (ट) और खंड (ठ) का लोप किया जाएगा;
- (xv) खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:--
- ''(ड) धारा 42 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन बीमा अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताएं या व्यावहारिक प्रशिक्षण अथवा उत्तीर्ण की जाने वाली परीक्षा;'';
- (xvi) खंड (ढ) का लोप किया जाएगा;
- (xvii) खंड (ण) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - ''(ण) धारा 42 की उपधारा (3) के खंड (ज) के अधीन आचार संहिता:'':
- (xviii) खंड (त) का लोप किया जाएगा;
- (xix) खंड (फक) का लोप किया जाएगा;
- (xx) खंड (फख) में, ''की उपधारा (2)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा;
- (xxi) खंड (ब) का लोप किया जाएगा;
- (xxii) खंड (भ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-
- ''(भ) धारा 64पड की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और आचार संहिता;
- (भक) वह अवधि जिसके लिए कोई व्यक्ति धारा 64पड की उपधारा (3) के अधीन सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य कर सकेगा;'';
- (xxiii) खंड (म) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

- (म) धारा 64फ की उपधारा (1) के अधीन कितपय आस्तियों के अपवर्जन की रीति, उपधारा (2) के अधीन दायित्वों के मूल्यांकन की रीति और उपधारा (3) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय;'';
- (xxiv) खंड (यक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
- ''(यक) आस्तियों की पर्याप्तता से संबंधित धारा 64फक की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट विषय;'';
- (xxv) खंड (यकक) के पश्चात्,निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—
- ''(यकख) धारा 64फक की उपधारा (9) के अधीन शोधन क्षमता के मार्जिन के ब्यौरे देने वाली विवरणी का प्ररूप, समय, रीति, जिसके अंतर्गत उसका अधिप्रमाणन भी है;'';

(यकग) धारा 64फग के अधीन कारबार के स्थान खोलने और बंद करने की रीति;'';

(xxvi) खंड (यख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(यखक) धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन जीवन बीमा पालिसी के अभ्यर्पण मूल्य के सन्नियम :''।

102. बीमा अधिनियम की पांचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची और आठवीं अनुसूची का लोप किया जाएगा।

पांचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची और आठवीं अनुसूची का लोप।

अध्याय 3

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का संशोधन

1972 का 57

103. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 10क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नई धारा 10ख का अंत:स्थापन।

''10ख. साधारण बीमा निगम और धारा 10क में विनिर्दिष्ट बीमा कंपनियां, शोधन क्षमता मार्जिन और ऐसे अन्य प्रयोजनों को पूरा करने के लिए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित सशक्त करे, ग्रामीण और सामाजिक सेक्टरों में अपने कारबार को बढ़ाने के लिए अपनी पूंजी जुटा सकेंगी:

साधारण बीमा कंपनियों की साधारण पूंजी की वृद्धि।

परंतु केंन्द्रीय सरकार की शेयरधारिता किसी भी समय इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं होगी।''।

1972 का 57

104. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 25 का लोप किया ध जाएगा।

धारा 25 का लोप।

अध्याय ४

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का संशोधन

1999 का 41

105. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 2 की उपधारा (1) धारा 2 का मंं,—

- (i) खंड (ख) में, ''बीमा विनियामक'' शब्दों के स्थान पर, ''भारतीय बीमा विनियामक'' शब्द रखे जाएंगे;
 - (ii) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:--
 - '(च)''मध्यवर्ती''या''बीमा मध्यवर्ती''के अंतर्गत बीमा दलाल, पुनर्बीमा दलाल, बीमा परामर्शी, निगम अभिकर्ता, अन्य पक्षकार प्रशासक, सर्वेक्षक और हानि निर्धारक तथा ऐसी अन्य इकाइयां आती हैं जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं;'।

धारा 3 का संशोधन। "'

106. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) में 1999 का 41 ''बीमा विनियामक'' शब्दों के स्थान पर ''भारतीय बीमा विनियामक'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 16 का संशोधन। 107. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 16 की उपधारा (1) के 1999 का 41 खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति। 108. (1) बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938, 1938 का 4 साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 1972 का 57 अधिनियम, 1999 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई उक्त अधिनियमों के, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित, 1999 का 41 तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 13)

[21मार्च, 2016]

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

- 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और संक्षिप्त नाम और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2016 है।
- (2) धारा 8 के उपबंध 1 अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे और शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

अध्याय 2

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 का संशोधन

धारा २ का संशोधन।

2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उच्च 1954 का 28 न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

- (i) खंड (ख) में, ''भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 222 की उपधारा (2) के अधीन अथवा'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;
- (ii) खंड (घ) में, ''भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 222 की उपधारा (3) के अधीन या'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;
 - (iii) खंड (ङ) का लोप किया जाएगा ;
- (ख) उपधारा (2) में, ''किसी भूतपूर्व भारतीय उच्च न्यायालय के कार्यकारी न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में किसी अविध या अविधयों के लिए की गई पूर्व सेवा'' शब्दों के स्थान पर, ''कार्यकारी न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में किसी अविध या अविधयों के लिए की गई सेवा'' शब्द रखे जाएंगे :
 - (ग) उपधारा (३) और उपधारा (४) का लोप किया जाएगा।

धारा ३ का संशोधन।

- 3. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
 - ''(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी न्यायाधीश को किसी कलेण्डर वर्ष में इतने दिनों की और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, आकस्मिक छुट्टी अनुज्ञेय हो सकेगी।''।

धारा 4क का संशोधन। 4. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 4क में, ''अपने खाते में उपार्जित छुट्टी की अविध की बाबत'' शब्दों के स्थान पर, ''पूरे भत्तों के आधार पर संगणित अपने खाते में जमा छुट्टी की अविध की बाबत,'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 9 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

5. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

छुट्टी भत्ते।

''9. किसी न्यायाधीश को, संदेय छुट्टी वेतन की मासिक दर धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार होगी।''

धारा 10 का लोप।

6. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 10 का लोप किया जाएगा।

धारा 14 का संशोधन।

- 7. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 14 के परंतुक में,—
 - (i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
 - ''(ख) उसने बासठ वर्ष की आयु न प्राप्त कर ली हो ; या'';
 - (ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
 - "स्पष्टीकरण—इस धारा में 'न्यायाधीश' से ऐसा न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसने संघ या किसी राज्य के अधीन कोई अन्य पेंशन योग्य पद धारण न किया हो और इसके अंतर्गत ऐसा न्यायाधीश भी है, जिसने संघ या राज्य के अधीन कोई अन्य पेंशन योग्य पद धारण कर लेने पर, प्रथम अनुसूची के भाग 1 के अधीन संदेय पेंशन लेने का चयन किया है।''।

8. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्निलखित धारा अंत:स्थापित की नई धारा 14क का जाएगी, अर्थात्:--

अंत:स्थापन।

''14क. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन किसी ऐसे न्यायाधीश, जो संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (2) के उपखंड (ख) के अधीन ऐसे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, की सेवा में पेंशन के प्रयोजनों के लिए दस वर्ष की अवधि जोड़ी जाएगी और उसे 1 अप्रैल, 2004 से जोड़ा हुआ समझा जाएगा।"।

सेवा के जोड़े गए वर्षों का फायदा।

9. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 15 में,—

धारा 15 का संशोधन।

- (क) उपधारा (1) में,—
 - (i) खंड (क) का लोप किया जाएगा;
- (ii) खंड (ख) में, ''जो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य नहीं है किन्तु'' शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (iii) परंतुक में, '',यथास्थिति'' तथा ''भाग 2 या'' शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा;
- (ख) उपधारा (2) में, '', यथास्थिति, भाग 2 या'' शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा।
- 10. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 16 के परंतुक में, ''भाग 2 या'' शब्दों और अंक का धारा 16 का संशोधन। लोप किया जाएगा।
 - 11. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 17क में,—

धारा 17क का

संशोधन।

- (क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में, "भाग 2 और" शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा:
 - (ख) उपधारा (2) में, ''भाग 2 या'' शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा।
- 12. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 18 का लोप किया जाएगा।

धारा 18 का लोप।

13. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 20 में. —

धारा 20 का संशोधन।

- (i) पहले परंतुक में, ''जो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य है या'' शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ii) दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा।
- 14. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 23ख का लोप किया जाएगा।

धारा 23ख का

लोप।

15. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

धारा 24 का संशोधन।

- ''(कक) आकस्मिक छुट्टियों की संख्या और वे शर्तें, जिनके अध्यधीन इन्हें धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा;"।
- 16. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 25 का लोप किया जाएगा।

धारा 25 का लोप।

17. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

पहली अनुसूची का संशोधन।

- (क) भाग 1 में,—
 - (i) पैरा 1 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—
 - ''1. इस भाग के उपबंध ऐसे न्यायाधीश को, जो संघ या किसी राज्य के अधीन किसी अन्य पेंशन योग्य पद पर नहीं रहा है या ऐसे न्यायाधीश को, जिसने संघ या राज्य के

अधीन किसी अन्य पेंशन योग्य पद पर रहते हुए इस भाग के अधीन संदेय पेंशन लेने का चयन किया है, लागू होंगे।'';

- (ii) पैरा 2 में, ''और जिसने पेंशन के लिए सेवा के कम से कम सात वर्ष पूरे कर लिए हैं,'' शब्दों का लोप किया जाएगा:
 - (iii) पैरा 8 और पैरा 9 का लोप किया जाएगा;
- (ख) भाग 2 का लोप किया जाएगा।

अध्याय 3

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का संशोधन

धारा २ का संशोधन।

18. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (छ) में, ''या तो फेडरल न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में या ऐसे किसी न्यायालय '' शब्दों के स्थान पर, ''उच्चतम न्यायालय में '' शब्द रखे जाएंगे।

1958 का 41

धारा ३ का संशोधन।

- 19. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
 - ''(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी न्यायाधीश को किसी कलेण्डर वर्ष में इतने दिनों की और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, आकस्मिक छुट्टी अनुज्ञेय हो सकेगी।''।

धारा ४क का संशोधन। 20. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 4क में, ''अपने खाते में उपार्जित छुट्टी की अविध की बाबत'' शब्दों के स्थान पर, ''पूरे भत्तों के आधार पर संगणित अपने खाते में जमा छुट्टी की अविध की बाबत,'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 9 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। 21. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

छुट्टी भत्ते।

"9. किसी न्यायाधीश को संदेय छुट्टी वेतन की मासिक दर धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार होगी।"।

धारा 13 का संशोधन। 22. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 13 के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण — इस धारा में 'न्यायाधीश' से ऐसा न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसने संघ या किसी राज्य के अधीन कोई अन्य पेंशन योग्य पद धारण न किया हो और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो 20 मई, 1954 को न्यायाधीश के रूप में सेवा में था और इसके अंतर्गत ऐसा न्यायाधीश भी है, जिसने संघ या राज्य के अधीन कोई अन्य पेंशन योग्य पद धारण कर लेने पर, अनुसूची के भाग 1 के अधीन संदेय पेंशन लेने का चयन किया है।''।

धारा 14 का संशोधन।

- 23. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 14 में,—
 - (क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थातु:—
 - ''(1) ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश को, जिसने संघ या किसी राज्य के अधीन कोई अन्य पेंशन योग्य पद धारण किया है, उसकी निवृत्ति पर अनुसूची के भाग 3 के उपबंधों के अनुसार पेंशन संदत्त होगी:

परंतु ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश, यथास्थिति, या तो अनुसूची के भाग 1 या अनुसूची के भाग 3 के अधीन उसको संदेय पेंशन प्राप्त करने का चयन करेगा और उसको संदेय पेंशन तद्नुसार संगणित की जाएगी।'';

(ख) उपधारा (2) में, ''यथास्थिति, भाग 2 या'' शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा।

24. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 16क के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में, ''भाग 2 धारा 16क का और'' शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा।

संशोधन।

25. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 18 का लोप किया जाएगा।

धारा 18 का लोप।

26. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 20 के परंतुक में, ''जो भारतीय सिविल सेवा का धारा 20 का सदस्य है या'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

संशोधन।

27. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

धारा 24 का संशोधन।

''(कक) आकस्मिक छुट्टियों की संख्या और वे शर्तें, जिनके अध्यधीन इन्हें धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा।"।

28. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की अनुसूची में,—

अनुसूची का संशोधन।

(क) भाग 1 में, पैरा 1 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

''1. इस भाग के उपबंध ऐसे न्यायाधीश को, जो संघ या किसी राज्य के अधीन किसी अन्य पेंशन योग्य पद पर नहीं रहा है, लागू होंगे और ऐसे व्यक्ति को भी, जो 20 मई, 1954 को न्यायाधीश के रूप में सेवा में था और ऐसे न्यायाधीश को, जिसने संघ या राज्य के अधीन किसी अन्य पेंशन योग्य पद पर रहते हुए इस भाग के अधीन संदेय पेंशन लेने का चयन किया है, लागू होंगे।";

(ख) भाग 2 का लोप किया जाएगा।

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 16)

[25 मार्च, 2016]

भू-संपदा सेक्टर के विनियमन और संवर्धन के लिए भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने तथा यथास्थिति, भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन का विक्रय या भू-संपदा परियोजना का विक्रय दक्षतापूर्ण और पारदर्शी रीति में सुनिश्चित करने तथा भू-संपदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हित की संरक्षा करने और विवाद के शीघ्र समाधान के लिए एक न्यायनिर्णायक तंत्र की स्थापना और भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण तथा न्यायनिर्णायक अधिकारी के विनिश्चयों, निदेशों अथवा आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए भी एक अपील अधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध

करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

परिभाषाएं।

- 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---
- (क) ''न्यायनिर्णायक अधिकारी'' से धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ख) ''विज्ञापन'' से किसी भी माध्यम के माध्यम से विज्ञापन के रूप में वर्णित या जारी किया गया कोई दस्तावेज अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी कोई सूचना, परिपत्र या अन्य दस्तावेज या किसी भी रूप में प्रचार, भू–संपदा परियोजना के बारे में व्यक्तियों को सूचित करना या किसी भू–खंड, भवन या अपार्टमेंट का विक्रय करने की प्रस्थापना करना या ऐसे भू–खंड, भवन या अपार्टमेंट को किसी भी रीति में क्रय करने या ऐसे प्रयोजनों के लिए अग्रिम या निक्षेप करने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करना भी है;
 - (ग) ''विक्रय करार'' से संप्रवर्तक और आबंटिती के बीच किया गया करार अभिप्रेत है:
- (घ) किसी भू-संपदा परियोजना के संबंध में ''आबंटिती'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे संप्रवर्तक द्वारा, यथास्थिति, कोई भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन (चाहे निर्बाधधृति के रूप में या पट्टाधृति के रूप में) आबंटित, विक्रीत या अन्यथा अंतरित किया गया है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो बाद में उक्त आबंटन को विक्रय, अंतरण के माध्यम से या अन्यथा अर्जित करता है परन्तु इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे, यथास्थिति, ऐसा भूखंड, अपार्टमेंट या भवन किराए पर दिया गया है;
- (ङ) ''अपार्टमेंट'' से, चाहे उसे ब्लाक, चेम्बर, निवास एकक, फ्लैट, कार्यालय, शोरूम, दुकान, गोदाम, परिसर, सूट, वासगृह, एकक कहा जाए या किसी अन्य नाम से जाना जाए, किसी भवन में या किसी भू-खंड पर एक या अधिक तलों पर या उसके किसी भाग पर अवस्थित किसी स्थावर संपत्ति का एक पृथक् और स्वत:पूर्ण भाग, जिनके अंतर्गत एक या अधिक कमरे या संलग्नक स्थल भी हैं, अभिप्रेत है, जिसका किसी निवासीय या वाणिज्यिक उपयोग जैसे कि निवास, कार्यालय, दुकान, शोरूम या गोदाम के लिए अथवा कोई कारबार, उपजीविका, वृत्ति या व्यापार करने के लिए या विनिर्दिष्ट प्रयोजन के आनुषंगिक किसी अन्य प्रकार के उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है;
 - (च) ''अपील अधिकरण'' से धारा 43 के अधीन स्थापित भू-संपदा अपील अधिकरण अभिप्रेत है;
 - (छ) ''समुचित सरकार'' से,—
 - (i) विधान-मंडल रहित संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित मामलों की बाबत, केंद्रीय सरकार;
 - (ii) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित मामलों की बाबत, संघ राज्यक्षेत्र सरकार;
 - (iii) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित मामलों की बाबत, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय:
 - (iv) राज्य से संबंधित मामलों की बाबत, राज्य सरकार,

अभिप्रेत है:

(ज) ''वास्तुविद्'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन वास्तुविद् के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो;

1972 का 20

- (झ) ''प्राधिकरण'' से धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है:
- (ञ) ''भवन'' के अंतर्गत कोई संरचना या परिनिर्माण या किसी ऐसी संरचना या परिनिर्माण का भाग भी है, जिसका उपयोग आवासिक, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अथवा किसी कारबार, उपजीविका, वृत्ति या व्यापार के प्रयोजन के लिए या किन्हीं अन्य संबंधित प्रयोजनों के लिए किया जाना आशयित है;
- (ट) ''फर्श क्षेत्र'' से किसी अपार्टमेंट का, बाह्य दीवारों द्वारा आवेष्टित क्षेत्र, सर्विस शाफ्टों के अधीन के क्षेत्रों, अनन्य बालकोनी या बरामदे के क्षेत्रों और अनन्य खुले टेरेस क्षेत्र को छोड़कर, वास्तविक प्रयोक्तव्य फर्श क्षेत्र अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत अपार्टमेंट की आंतरिक विभाजक दीवारों द्वारा आवेष्टित क्षेत्र आता है।

- स्पर्धिकरण इस खंड के प्रयोजन के लिए ''अनन्य बालकोनी या बरामदा क्षेत्र'' पद से, यथास्थिति, बालकोनी या बरामदे का ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो अपार्टमेंट के वास्तिवक प्रयोक्तव्य फर्श क्षेत्र से अनुलग्न है और जो आबंटिती के अनन्य उपयोग के लिए है और ''अनन्य खुले टेरेस क्षेत्र'' से खुले टेरेस का ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो अपार्टमेंट के वास्तिवक प्रयोक्तव्य फर्श क्षेत्र से अनुलग्न है, आबंटिती के अनन्य उपयोग के लिए है;
 - (ठ) ''अध्यक्ष'' से धारा 21 के अधीन नियुक्त भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है:
 - (ड) ''कार्य प्रारंभ करने संबंधी प्रमाणपत्र'' से संप्रवर्तक को स्थावर संपत्ति पर विकास कार्य मंजूर रेखांक के अनुसार, आरंभ करने के लिए अनुज्ञात या अनुज्ञप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कार्य प्रारंभ करने संबंधी प्रमाणपत्र या निर्माण अनुज्ञापत्र या सिन्नर्माण अनुज्ञापत्र, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है;
 - (ढ) ''सामान्य क्षेत्र'' से अभिप्रेत है,—
 - (i) भू–संपदा परियोजना के लिए संपूर्ण भूमि या जहां परियोजना को अवस्थान क्रमों में विकसित किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा किसी अवस्थान–क्रम के लिए की जाती है वहां उस अवस्थान–क्रम के लिए संपूर्ण भूमि;
 - (ii) सीढ़ियां, लिफ्टें, सीढ़ी और लिफ्ट लाबी, अग्नि बचाव क्षेत्र और भवनों के सामान्य प्रवेश और बहिर्गमन द्वार;
 - (iii) सामान्य बेसमेन्ट, टेरेस, पार्क, क्रीड़ा क्षेत्र, खुले पार्किंग क्षेत्र और सामान्य भंडारण स्थल;
 - (iv) संपत्ति के प्रबंधन के लिए नियोजित व्यक्तियों के आवास जिसके अंतर्गत पहरा निगरानी कर्मचारिवृंद के लिए वास-सुविधा भी है या सामुदायिक सेवा कार्मिकों के आवास के लिए परिसर;
 - (v) विद्युत, गैस, जल और स्वच्छता, वातानुकूलन और भस्मन, जल संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा की प्रणाली जैसी केंद्रीय सेवाओं का संस्थापन:
 - (vi) पानी की टेंकियां, चौबच्चा, मोटरें, पंखों, संपीड़ित्रों, निलकाओं के और सामान्य उपयोग के लिए संस्थापनों के साथ जुड़े सभी साधित्र;
 - (vii) भू-संपदा परियोजना में यथा उपबंधित सभी सामुदायिक और वाणिज्यिक सुविधाएं;
 - (viii) परियोजना के सभी अन्य भाग जो उसके अनुरक्षण, सुरक्षा आदि तथा सामान्य उपयोग के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हों;
 - (ण) ''कंपनी'' से कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित और रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—
 - (i) किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम;
 - (ii) सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस निमित्त स्थापित कोई विकास प्राधिकरण या कोई लोक प्राधिकरण;
 - (त) ''सक्षम प्राधिकारी'' से समुचित सरकार द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, सृजित या स्थापित स्थानीय प्राधिकारी या कोई ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो अपनी अधिकारिता के अधीन की भूमि पर प्राधिकार का प्रयोग करता है और जिसे ऐसी स्थावर संपत्ति के विकास के लिए अनुज्ञा देने की शक्तियां प्राप्त हैं;
 - (थ) ''समापन प्रमाणपत्र'' से सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित करते हुए कि भू–संपदा परियोजना का स्थानीय विधियों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित मंजूर रेखांक, अभिन्यास रेखांक और विनिर्देशों के अनुसार, विकास किया गया है, जारी किया गया है समापन प्रमाणपत्र या ऐसा अन्य प्रमाणपत्र, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है;
 - (द) ''दिवस'' से समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित, यथास्थिति, संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में का कार्य दिवस अभिप्रेत है;

2013 का 18

- (ध) ''विकास'' से, उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, भूमि में, उस पर, उसके ऊपर या उसके नीचे स्थावर संपत्ति का विकास, इंजीनियरी या अन्य संक्रियाएं करना अथवा किसी स्थावर संपत्ति या भूमि में कोई तात्त्विक परिवर्तन करना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत पुनर्विकास भी है;
- (न) ''विकास संकर्म'' से स्थावर संपत्ति पर के बाह्य विकास संकर्म और आंतरिक विकास संकर्म अभिप्रेत हैं:
- (प) ''इंजीनियर'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या किसी विश्वविद्यालय या किसी विधि के अधीन मान्यताप्राप्त किसी संस्था द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से स्नातक या समतुल्य डिग्री धारण करता है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इंजीनियर के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;
- (फ) ''भू-संपदा परियोजना की प्राक्कलित लागत'' से भू-संपदा परियोजना का विकास करने में अंतर्विलित कुल लागत अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत भूमि की लागत, कर, उपकर, विकास और अन्य प्रभार भी हैं;
- (ब) ''बाह्य विकास संकर्म'' के अंतर्गत सड़कें और सड़क प्रणालियां, भू-दृश्य निर्माण, जल प्रदाय, मलवहन और जलनिकास प्रणालियां, विद्युत प्रदाय ट्रांसफार्मर, उपकेन्द्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और व्ययन या कोई अन्य संकर्म आते हैं, जिसका किसी, परियोजना की परिधि में या उसके बाहर उसके फायदे के लिए इस प्रकार निष्पादन किया जाना होगा जैसा स्थानीय विधियों के अधीन उपबंधित किया जाए;
- (भ) ''कुटुंब'' के अंतर्गत पति, पत्नी, अवयस्क पुत्र और अविवाहित पुत्री, जो व्यक्ति पर पूर्णतः आश्रित हो;
- (म) ''गैराज'' से परियोजना के भीतर का कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसमें किसी यान की पार्किंग के लिए छत और तीन ओर दीवारें हों किंतु इसके अंतर्गत अपरिवेष्टित अथवा अनावेष्टित पार्किंग स्थल जैसे कि खुले पार्किंग क्षेत्र नहीं आते हैं;
- (य) ''स्थावर संपत्ति'' के अंतर्गत भूमि, भवन, मार्गाधिकार, बित्तयां या भूमि और भूबद्ध चीजों से या भूबद्ध ऐसी किसी चीज से, जो स्थायी रूप से जकड़ी हुई है, उद्भूत कोई अन्य फायदा आता है, किंतु इसके अंतर्गत खड़ा काष्ठ, खड़ी फसलें या घास नहीं आती है;
 - (यक) ''ब्याज'' से, यथास्थिति, संप्रवर्तक या आबंटिती द्वारा संदेय ब्याज की दरें अभिप्रेत हैं; स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए,—
 - (i) व्यतिक्रम की दशा में, संप्रवर्तक द्वारा आबंटिती से प्रभार्य ब्याज की दर ब्याज की उस दर के बराबर होगी, जिसे संप्रवर्तक, व्यतिक्रम की दशा में, आबंटिती को संदत्त करने का दायी होगा;
 - (ii) संप्रवर्तक द्वारा आबंटिती को ब्याज उस तारीख से, जिसको संप्रवर्तक रकम या उसका कोई भाग प्राप्त करता है उस तारीख तक, जब तक रकम या उसके भाग का तथा उस पर के ब्याज का प्रतिदाय नहीं किया जाता है, संदेय होगा और आबंटिती द्वारा संप्रवर्तक को ब्याज उस तारीख से, जब आबंटिती संप्रवर्तक को संदाय करने में व्यतिक्रम करता है, उस तारीख तक, जब तक उसका संदाय नहीं कर दिया जाता है, संदेय होगा;
- (यख) ''आंतरिक विकास संकर्म'' से सड़कें, पैदल मार्ग, जल प्रदाय, मलनाली, नाले, पार्क, वृक्षारोपण, पथ प्रकाश, सामुदायिक भवनों के लिए और मल तथा मैले जल के उपचार और व्ययन का उपबंध, ठोस अपिशष्ट प्रबंधन और व्ययन, जल संरक्षण, ऊर्जा प्रबंधन, अग्नि संरक्षण और अग्नि सुरक्षा अपेक्षाएं, सामाजिक अवसंरचना जैसे कि शैक्षणिक, स्वास्थ्य और अन्य जन सुविधाएं अथवा परियोजना में का, उसके फायदे के लिए, कोई अन्य संकर्म, मंजूर रेखांकों के अनुसार, अभिप्रेत है;

- (यग) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से नगर निगम या नगरपालिका या पंचायत या कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत हैं जो उसकी अधिकारिता के अधीन क्षेत्रों के संबंध में, यथास्थिति, नगरपालिक सेवाओं या मूलभूत सेवाओं का उपबंध करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किया गया है;
- (यघ) ''सदस्य'' से धारा 21 के अधीन नियुक्त भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है;
- (यङ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित''पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (यच) "अधिभोग-प्रमाणपत्र" से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अधिभोग-प्रमाणपत्र या ऐसा अन्य प्रमाणपत्र, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जिसमें किसी भवन के, जिसमें नागरिक अवसंरचना के जैसे कि जल, स्वच्छता और विद्युत का उपबंध हो, अधिभोग को स्थानीय विधियों के अधीन उपबंधित रूप में अनुज्ञात किया गया हो;
 - (यछ) ''व्यक्ति'' के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं.—
 - (i) कोई व्यष्टि;
 - (ii) कोई हिन्दू अविभक्त क्टूंब;
 - (iii) कोई कंपनी;
 - (iv) यथास्थिति, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन कोई फर्म;
 - (v) कोई सक्षम प्राधिकारी;
 - (vi) कोई व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं;
 - (vii) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रिजस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी;
 - (viii) कोई अन्य ऐसी इकाई, जिसे समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे:
- (यज) ''योजना क्षेत्र'' से कोई योजना क्षेत्र या विकास क्षेत्र या स्थानीय योजना क्षेत्र या प्रादेशिक विकास योजना क्षेत्र, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो या कोई ऐसा अन्य क्षेत्र अभिप्रेत है, जो समुचित सरकार या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए और इसके अंतर्गत ऐसा कोई क्षेत्र भी है जिसे समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा नगर और ग्राम योजना से संबंधित तत्समय प्रवृत्त और समय-समय पर यथा पुनरीक्षित विधि के अधीन भावी योजनाबद्ध विकास के लिए किसी योजना क्षेत्र के रूप में अभिहित किया गया है;
 - (यझ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
 - (यञ) ''परियोजना'' से खंड (यढ) में यथापरिभाषित भू-संपदा परियोजना अभिप्रेत है;
 - (यट) ''संप्रवर्तक'' से अभिप्रेत है,—
 - (i) ऐसा व्यक्ति, जो किसी स्वतंत्र भवन या अपार्टमेंटों वाले किसी भवन का, सभी अपार्टमेंटों का या उनमें से कुछ का अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने के प्रयोजन के लिए सिन्नर्माण करता है या सिन्नर्माण कराता है अथवा किसी विद्यमान भवन या उसके किसी भाग को अपार्टमेंटों में संपरिवर्तित करता है और इसके अंतर्गत उसके समनुदेशिती भी हैं; या
 - (ii) ऐसा व्यक्ति, जो किसी परियोजना में, भूमि का, चाहे वह किसी भी भू-खंड पर अवसंरचनाओं का निर्माण करता है अथवा नहीं, उक्त परियोजना, चाहे उन पर संरचना है या नहीं, में सभी या कुछ भू-खंडों का अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने के प्रयोजन के लिए विकास करता है; या

1932 का 9 2009 का 6

- (iii) (क) यथास्थिति, विकास प्राधिकरण या लोक निकाय द्वारा उसके स्वामित्वाधीन या सरकार द्वारा उनके व्ययन पर रखी भूमि पर सन्निर्मित भवनों या अपार्टमेंटों; या
- (ख) ऐसे प्राधिकरण या निकाय के स्वामित्वाधीन या सरकार द्वारा उनके व्ययन पर रखे भू-खंडों,

के आबंटिती के संबंध में सभी या कुछ अपार्टमेंटों या भू-खंडों का विक्रय करने के प्रयोजन के लिए ऐसा कोई प्राधिकरण या अन्य निकाय; या

- (iv) कोई ऐसी उच्चतर राज्य स्तरीय सहकारी आवास वित्त सोसाइटी और प्राथमिक सहकारी आवास सोसाइटी, जो अपने सदस्यों के लिए या ऐसे अपार्टमेंटों या भवनों के आबंटितियों के संबंध में अपार्टमेंटों या भवनों का सिन्नर्माण करती है; या
- (v) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो स्वयं एक निर्माणकर्ता, कालोनी निर्माता, ठेकेदार, विकासकर्ता, संपदा विकासकर्ता के रूप में या किसी अन्य नाम से कार्य करता है अथवा उस भूमि के, जिस पर विक्रय के लिए भवन या अपार्टमेंट का सिन्नर्माण किया जाता है या भू-खंड का विकास किया जाता है, स्वामी से प्राप्त मुख्तारनामे के धारक के रूप में कार्य करने का दावा करता है; या
- (vi) ऐसा अन्य व्यक्ति, जो जनसाधारण को विक्रय के लिए किसी भवन या अपार्टमेंट का सिन्नर्माण करता है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, जहां ऐसा व्यक्ति, जो विक्रय के लिए किसी भवन का निर्माण करता है या उसको अपार्टमेंटों में संपरिवर्तित करता है या किसी भू-खंड का विकास करता है और वे व्यक्ति, जो अपार्टमेंटों या भू-खंडों का विक्रय करते हैं, भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं तो उन दोनों को संप्रवर्तक समझा जाएगा और वे अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट कृत्यों और उत्तरदायित्वों के लिए उस रूप में संयुक्त रूप से दायी होंगे;

- (यठ) ''प्रास्पेक्ट्स'' से प्रास्पेक्ट्स के रूप में वर्णित या जारी किया गया कोई दस्तावेज या कोई सूचना, परिपत्र या ऐसा अन्य दस्तावेज अभिप्रेत है, जिनके द्वारा किसी भू–संपदा परियोजना का विक्रय करने की प्रस्थापना की जाती है या किसी व्यक्ति को ऐसे प्रयोजनों के लिए अग्रिम देने या निक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया जाता है;
- (यड) ''भू-संपदा अभिकर्ता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो एक व्यक्ति की ओर से किसी भू-संपदा परियोजना में, यथास्थिति, उसके भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन का विक्रय के रूप में अंतरण अथवा किसी अन्य व्यक्ति के, यथास्थिति, भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन का उसको अंतरण करने के संव्यवहार में दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करता है या उसकी ओर से कार्य करता है और अपनी सेवाओं के लिए कमीशन के रूप में या अन्यथा पारिश्रमिक या फीस या कोई अन्य प्रभार प्राप्त करता है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो किसी माध्यम के माध्यम से भावी क्रेताओं और विक्रेताओं को, यथास्थिति, भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन का विक्रय या क्रय करने संबंधी बातचीत करने के लिए एक-दूसरे को परिचय करवाता है और इसके अंतर्गत संपत्ति व्यवहारी, दलाल, बिचौलिए, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, भी हैं;
- (यढ) ''भू-संपदा परियोजना'' से, यथास्थिति, किसी भवन अथवा अपार्टमेंटों वाले किसी भवन का विकास या किसी विद्यमान भवन अथवा उसके किसी भाग का अपार्टमेंटों में संपरिवर्तन या, यथास्थिति, भू-खंडों अथवा अपार्टमेंटों में, भूमि का, यथास्थिति, उक्त सभी या कुछ अपार्टमेंटों या भू-खंडों या भवनों के प्रयोजनार्थ विकास अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सामान्य क्षेत्र, विकास संकर्म, उस पर के सभी सुधारकार्य और संरचनाएं और सभी सुखाचार अधिकार और उससे संबद्ध अनुलग्नक भी हैं;
 - (यण) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

- (यत) ''नियम'' से समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं:
- (यथ) ''मंजूर रेखांक'' से स्थल रेखांक, भवन रेखांक, सेवा रेखांक, पार्किंग और परिचालन रेखांक, दृश्य भूमि रेखांक, अभिन्यास रेखांक, जोन रेखांक और ऐसा अन्य रेखांक अभिप्रेत हैं और इनके अंतर्गत, संरचनात्मक डिजाइन, यदि लागू हों, अनुज्ञाएं, जैसे कि पर्यावरण अनुज्ञा और ऐसी अन्य अनुज्ञाएं भी हैं, जो किसी भू–संपदा परियोजना को आरंभ करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हों:
- (यद) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नगरपालिका विधियों या समुचित सरकार की ऐसी अन्य सुसंगत विधियों में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उन विधियों में क्रमश: उनके हैं।

अध्याय 2

भू-संपदा परियोजना का रजिस्ट्रीकरण और भू-संपदा अभिकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण

3.(1) कोई भी संप्रवर्तक भू-संपदा परियोजना को इस अधिनियम के अधीन स्थापित भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के पास रजिस्टर कराए बिना किसी योजना क्षेत्र में, यथास्थिति, किसी भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन या उसके किसी भाग को किसी भी रीति में विज्ञापित, विपणित, बुक, उसका विक्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना अथवा क्रय के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं करेगा:

भू-संपदा परियोजना का भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के पास पूर्व रजिस्ट्रीकरण।

परंतु उन परियोजनाओं के लिए, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को चल रही हैं और जिनके लिए कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, संप्रवर्तक उक्त परियोजना का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन मास की अविध के भीतर प्राधिकारी को आवेदन करेगा:

परन्तु यह और कि यदि प्राधिकारी, आबंटितियों के हित में, उन परियोजनाओं के लिए, जो योजना क्षेत्र से परे किंतु स्थानीय प्राधिकारी की अपेक्षित अनुज्ञा से विकसित की जाती हैं, आवश्यक समझता है तो वह, आदेश द्वारा, संप्रवर्तक को उस परियोजना को प्राधिकारी के पास रजिस्टर कराने का निदेश दे सकेगा और इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबन्ध उन परियोजनाओं को रजिस्ट्रीकरण के प्रक्रम से लागू होंगे।

- (2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भू–संपदा परियोजना का कोई रजिस्ट्रीकरण उस दशा में अपेक्षित नहीं होगा—
 - (क) जब विकसित किया जाने वाला प्रस्तावित भू-क्षेत्र पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक नहीं है या विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित अपार्टमेंटों की संख्या आठ से अधिक नहीं है, इसमें ऐसे सभी अवस्थान-क्रम की संख्या भी है:

परन्तु यदि समुचित सरकार इसे आवश्यक समझती है, तो वह इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण से छूट के लिए अवसीमा, यथास्थिति, पांच सौ वर्ग मीटर या आठ अपार्टमेंटों से नीचे तक, सभी अवस्थान– क्रमों सहित, कम कर सकेगी;

- (ख) जहां संप्रवर्तक को इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व भू-संपदा परियोजना का कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया हो;
- (ग) ऐसे नवीकरण या मरम्मत या पुनर्विकास के प्रयोजन के लिए जिसमें इस भू–संपदा परियोजना के अधीन, यथास्थिति, किसी अपार्टमेंट, भू–खंड या भवन के विपणन, विज्ञापन, विक्रय या नया आबंटन अंतर्विलत नहीं है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, जहां भू-संपदा परियोजना को अवस्थान-क्रम में विकसित किया जाना है, वहां प्रत्येक ऐसे अवस्थान-क्रम को एकल भू-संपदा परियोजना माना जाएगा और संप्रवर्तक, इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रत्येक अवस्थान-क्रम के लिए पृथक् रूप से रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करेगा।

भू–संपदा परियोजनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

- 4. (1) प्रत्येक संप्रवर्तक भू–संपदा परियोजना के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में, ऐसे समय के भीतर आवेदन करेगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
 - (2) संप्रवर्तक उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करेगा, अर्थात्:—
 - (क) उसके उद्यम का संक्षिप्त ब्यौरा, जिसके अंतर्गत उसका नाम, रजिस्ट्रीकृत पता, उद्यम का प्रकार (स्वत्वधारी, सोसाइटी, भागीदारी, कंपनी, सक्षम प्राधिकारी), और रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां, तथा संप्रवर्तक का नाम और फोटोचित्र:
 - (ख) उसके द्वारा, गत पांच वर्षों में, आरंभ की गई परियोजनाओं का, चाहे वे, यथास्थिति, पहले पूरी हो चुकी हों या विकसित की जा रही हैं, संक्षिप्त ब्यौरा, जिसके अंतर्गत उक्त परियोजनाओं की वर्तमान प्रास्थिति, उसके पूरा होने में कोई विलंब, लंबित मामलों का ब्यौरा, भूमि की किस्म का ब्यौरा और लंबित संदाय भी हैं;
 - (ग) सक्षम प्राधिकारी से उन विधियों के अनुसार, जो आवेदन में वर्णित भू-संपदा परियोजना को लागू हों, अभिप्राप्त किए गए अनुमोदनों और कार्य प्रारंभ करने संबंधी प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति और जहां परियोजना को अवस्थान-क्रम में विकसित किया जाना प्रस्तावित हो, वहां सक्षम प्राधिकारी से ऐसे प्रत्येक अवस्थान-क्रम के लिए प्राप्त अनुमोदनों और कार्य आरंभ करने संबंधी प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति;
 - (घ) प्रस्तावित परियोजना या उसके अवस्थान का मंजूर रेखांक, अभिन्यास रेखांक और विनिर्देश और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर की गई संपूर्ण परियोजना;
 - (ङ) प्रस्तावित परियोजना में निष्पादित किए जाने वाले विकास कार्यों की योजना और उसके संबंध में उपलब्ध कराए जाने वाले प्रस्तावित सुविधाएं, जिनके अंतर्गत अग्निशमन सुविधाएं, पेयजल सुविधाएं, आपात उत्खनन सेवाएं, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग भी हैं;
 - (च) परियोजना के, परियोजना के लिए उसकी सीमाओं के साथ सौंपी गई भूमि के स्पष्ट सीमांकन के साथ अवस्थिति संबंधी ब्यौरे, जिनके अंतर्गत परियोजना के अंत बिंदुओं का अक्षांश और रेखांश भी है;
 - (छ) आबंटितियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले प्रस्तावित आबंटन पत्र, विक्रय संबंधी करार और विक्रय विलेख का प्रोफार्मा;
 - (ज) परियोजना में विक्रयार्थ अपार्टमेंटों की संख्या, प्रकार और अपार्टमेंट से अनुलग्न अनन्य बालकोनी या बरामदे के क्षेत्रों तथा अनन्य खुले टेरेस क्षेत्रों, यदि कोई हों, सिहत फर्श क्षेत्र;
 - (झ) परियोजना में विक्रयार्थ गैरेज संख्या और क्षेत्र:
 - (ञ) प्रस्तावित परियोजना के लिए उसके भू-संपदा अभिकर्ताओं के, यदि कोई हों, नाम और पते;
 - (ट) प्रस्तावित परियोजना के विकास से संबंधित ठेकेदारों, वास्तुविद्, अवसरंचना इंजीनियर, यदि कोई हों और अन्य व्यक्तियों के नाम और पते:
 - (ठ) शपथ-पत्र द्वारा समर्थित एक घोषणा, जिस पर संप्रवर्तक या संप्रवर्तक द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसमें,—
 - (अ) यह कथन होगा कि उसका उस भूमि पर, जिस पर विकास कार्य प्रस्तावित है, विधिक हक है और यदि वह भूमि किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्वाधीन है तो ऐसे हक के अधिप्रमाणन सहित, विधिक रूप से वैध दस्तावेज होंगे;
 - (आ) यह कथन होगा कि, यथास्थिति, वह भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त है या ऐसी भूमि पर ऐसे विल्लंगमों के, जिनके अंतर्गत कोई अधिकार, हक, हित या ऐसी भूमि में या पर, उसके ब्यौरों सहित, किसी पक्षकार का नाम भी है, ब्यौरे;

- (इ) उस समयावधि का उल्लेख होगा जिसके भीतर वह, यथास्थिति, परियोजना या उसके अवस्थान-क्रम को पूरा करने का वचनबंध करता है;
- (ई) यह कथन होगा कि आबंटितियों से भू-संपदा परियोजना के लिए समय-समय पर वसूल की गई रकमों का स्तर प्रतिशत निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिए किसी अनुसूचित बैंक में रखे जाने वाले एक पृथक् खाते में जमा किया जाएगा और उसका केवल उस प्रयोजन के लिए ही उपयोग किया जाएगा:

परन्तु संप्रवर्तक भू–संपदा परियोजना की परियोजना लागत को पूरा करने के लिए परियोजना के पूरा होने की प्रतिशतता के अनुपात में, पृथक् खाते से रकमें निकालेगा:

परन्तु यह और कि संप्रवर्तक द्वारा पृथक् खाते से रकमें किसी इंजीनियर, वास्तुविद् और व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा यह प्रमाणित कर दिए जाने के पश्चात् निकाली जाएंगी कि रकम को परियोजना के पूरा होने की प्रतिशतता के अनुपात में निकाला गया है:

परन्तु यह भी कि संप्रवर्तक अपने खातों की, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् छह मास के भीतर, व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंट से लेखा परीक्षा कराएगा तथा ऐसे चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित तथा हस्ताक्षरित लेखाओं का एक विवरण प्रस्तुत करेगा तथा उसका लेखा परीक्षा के दौरान यह सत्यापन किया जाएगा कि किसी विशिष्ट परियोजना के लिए संगृहीत रकमों का उस परियोजना के लिए उपयोग किया जा चुका है और निकाली गई रकमें परियोजना के पूरा होने की प्रतिशतता के अनुपात के अनुपालन में हैं।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए ''अनुसूचित बैंक'' पद से ऐसा कोई बैंक अभिप्रेत है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सिम्मिलित है;

- (उ) यह कथन होगा कि वह सक्षम प्राधिकारियों से सभी लंबित अनुमोदन, समय पर, लेगा;
- (ऊ) यह कथन होगा कि उसने ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा विहित किए जाएं; और
- (ड) ऐसी अन्य जानकारी और दस्तावेज, जो विहित किए जाएं।
- (3) प्राधिकारी परियोजनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु वेब आधारित आनलाइन पद्धति को उसकी स्थापना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर परिचालित कराएगा।
- 5. (1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर, प्राधिकरण तीस दिन की अविध र्राजस्ट्रीकरण का के भीतर.—

अनुदत्त किया जाना।

- (क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करेगा और आवेदक को प्राधिकरण की वेबसाइट तक पहुंच बनाने तथा अपना वेब पेज सुजित करने और उसमें प्रस्तावित परियोजना के ब्यौरे भरने के लिए एक रजिस्ट्रीकरण संख्यांक, लॉगिन आई॰डी॰ और पासवर्ड प्रदान करेगा; या
- (ख) यदि ऐसा आवेदन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो, उस आवेदन को, लिखित में कारण लेखबद्ध करके नामंजूर करेगा:

परंतु कोई भी आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(2) यदि प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन यथा उपबंधित, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण को अनुदत्त करने या आवेदन को नामंजूर करने में असफल रहता है तो परियोजना को रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया समझा जाएगा और प्राधिकरण उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति की सात दिन की अवधि के

1934 का 2

भीतर संप्रवर्तक को प्राधिकरण की वेबसाइट तक पहुंच बनाने तथा अपना वेब पेज सृजित करने और उसमें प्रस्तावित परियोजना के ब्यौरे भरने के लिए एक रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और एक लॉगिन आई॰डी॰ और पासवर्ड प्रदान करेगा।

(3) इस धारा के अधीन अनुदत्त रिजस्ट्रीकरण, संप्रवर्तक द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ठ) के उपखंड (इ) के अधीन, यथास्थिति, परियोजना या उसके अवस्थान–क्रम को पूरा करने के लिए घोषित अविध के लिए विधिमान्य रहेगा।

रजिस्ट्रीकरण का विस्तारण। 6. धारा 5 के अधीन अनुदत्त रिजस्ट्रीकरण को, संप्रवर्तक द्वारा आवेदन किए जाने पर, प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य बाध्यता के कारण ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, विस्तारित किया जा सकेगा:

परन्तु प्राधिकरण संप्रवर्तक की ओर से व्यतिक्रम किए बिना, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर आधारित युक्तियुक्त परिस्थितियों और कारणों, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, से किसी परियोजना को अनुदत्त रिजस्ट्रीकरण ऐसे समय तक के लिए, जो वह आवश्यक समझे और जो कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक अविध का नहीं होगा, बढ़ा सकेगा:

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के विस्तारण संबंधी आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को उस मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, ''अनिवार्य बाध्यता'' पद से, कोई युद्ध, बाढ़, सूखा, अग्नि, तूफान, भूंकप या प्रकृति द्वारा कारित कोई अन्य आपदा अभिप्रेत है, जो किसी भू–संपदा परियोजना के नियमित विकास को प्रभावित करती हो।

रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण।

- 7. (1) प्राधिकरण, इस निमित्त कोई शिकायत प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से या सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश पर, अपना यह समाधान होने पर कि—
 - (क) संप्रवर्तक इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा या उनके अधीन अपेक्षित किसी बात को करने में व्यतिक्रम करता है:
 - (ख) संप्रवर्तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुमोदन के किन्हीं निबंधनों या शर्तों का अतिक्रमण करता है:
- (ग) संप्रवर्तक किसी प्रकार की अऋजु पद्धित या अनियमितताओं में संलिप्त है, धारा 5 के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण को प्रतिसंहत कर सकेगा।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए ''अऋजु पद्धित'' पद से ऐसी कोई पद्धित, जो संप्रवर्तक किसी भू–संपदा परियोजना के विक्रय की अभिवृद्धि या विकास के प्रयोजन के लिए अपनाता है या अऋजु ढंग या अऋजु या प्रवंचक पद्धित अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित पद्धितयां भी हैं, अर्थात्:—

- (अ) लिखित रूप में या दृश्यरूपण द्वारा ऐसा कोई कथन करने की पद्धति,—
- (i) जिससे मिथ्या रूप से यह व्यपदिष्ट होता है कि सेवाएं एक विशिष्ट मानक या श्रेणी की हैं:
- (ii) जिससे यह व्यपदिष्ट होता है कि संप्रवर्तक के पास ऐसा अनुमोदन या संबंधन है जो कि उस संप्रवर्तक के पास नहीं है;
 - (iii) जिसके द्वारा सेवाओं के संबंध में मिथ्या या भ्रामक व्यपदेशन किया जाता है;
- (आ) संप्रवर्तक ऐसी सेवाओं के संबंध में, जिनकी प्रस्थापना किया जाना आशयित नहीं है, किसी विज्ञापन या प्रास्पेक्टस को किसी समाचारपत्र में या अन्यथा प्रकाशित किए जाने की अनुज्ञा देता है।
 - (घ) संप्रवर्तक किन्हीं कपटपूर्ण पद्धतियों में लिप्त होता है।
- (2) संप्रवर्तक को धारा 5 के अधीन अनुदत्त रिजस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा संप्रवर्तक को लिखित में तीस दिन से अन्यून की सूचना, उसमें उन आधारों का कथन करते हुए, जिनके आधार पर रिजस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण किया जाना प्रस्तावित है, न दे दी गई हो और संप्रवर्तक

द्वारा उस सूचना की अविध के भीतर प्रस्तावित प्रतिसंहरण के विरुद्ध दर्शित किए गए किसी कारण पर उसके द्वारा विचार न कर लिया गया हो।

- (3) प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन रिजस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण करने के बजाय, उसके ऐसे अतिरिक्त निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह आबंटितियों के हित में अधिरोपित करना ठीक समझे, उसके प्रवृत्त रहने को अनुज्ञात कर सकेगा और इस प्रकार अधिरोपित ऐसे कोई निबंधन और शर्तें संप्रवर्तक पर आबद्धकर होंगी।
 - (4) प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण पर,—
 - (क) संप्रवर्तक को उस परियोजना के संबंध में उसकी वेबसाइट तक पहुंच बनाने से विवर्जित करेगा और अपनी वेबसाइट पर उसका नाम व्यतिक्रम करने वाले व्यक्तियों की सूची में विनिर्दिष्ट करेगा और उसका फोटोचित्र संप्रदर्शित करेगा तथा अन्य राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में के अन्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरणों को ऐसे रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के बारे में सूचित भी करेगा;
 - (ख) धारा ८ के उपबंधों के अनुसार किए जाने वाले शेष विकास संकर्म को सुकर बनाएगा;
 - (ग) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ठ) के उपखंड (ई) के अधीन विनिर्दिष्ट परियोजना बैंक खाते को धारण करने वाले बैंक को खाते को अक्रियाशील बनाने तथा धारा 8 के उपबंधों के अनुसार शेष विकास संकर्म को सुकर बनाने के प्रति ऐसी और आवश्यक कार्रवाइयां, जिनके अंतर्गत उक्त खाते का परिणामी क्रियाशीलन भी है, करने का निदेश देगा;
 - (घ) आबंटितियों के हितों की संरक्षा के लिए अथवा लोक हित में ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।
- 8. इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण के व्यपगत हो जाने या रिजस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण हो जाने पर, प्राधिकरण ऐसी कार्रवाई करने के लिए, जो वह ठीक समझे, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा या आबंटितियों के संगम द्वारा या ऐसी किसी अन्य रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जाए, शेष विकास संकर्मों को करना भी है, समुचित सरकार से परामर्श कर सकेगा:

रजिस्ट्रीकरण के व्यपगत होने या उसके प्रतिसंहरण के परिणामस्वरूप प्राधिकरण की बाध्यता।

परन्तु इस धारा के अधीन प्राधिकरण का ऐसा कोई निदेश, विनिश्चय या आदेश इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपबंधित अपील की अविध की समाप्ति तक प्रभावी नहीं होगा:

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के अधीन परियोजना के रिजस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण की दशा में, आबंटितियों के संगम का शेष विकास कार्यों को करने के लिए इंकार करने का प्रथम अधिकार होगा।

9. (1) कोई भी भू-संपदा अभिकर्ता इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किए बिना ऐसी किसी भू-संपदा परियोजना में, यथास्थिति, किसी भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन के या उसके किसी भाग के, जो धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत भू-संपदा परियोजना का भाग हो और जिसका संप्रवर्तक द्वारा किसी योजना क्षेत्र में विक्रय किया जा रहा है, विक्रय या क्रय को सुकर नहीं बनाएगा अथवा उसके विक्रय या क्रय को सुकर बनाने के लिए किसी व्यक्ति की ओर से कार्य नहीं करेगा।

भू–संपदा अभिकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण।

- (2) प्रत्येक भू-संपदा अभिकर्ता प्राधिकरण को रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर आवेदन करेगा और उसके साथ ऐसी फीस और दस्तावेज संलग्न होंगे जो विहित किए जाएं।
- (3) प्राधिकरण, ऐसी अवधि के भीतर, ऐसी रीति में और उन शर्तों के, जो विहित की जाएं, पूरा होने के प्रति अपना समाधान हो जाने पर,—
 - (क) भू-संपदा अभिकर्ता को, यथास्थिति, संपूर्ण राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए एकल राजस्ट्रीकरण अनुदत्त करेगा;
 - (ख) यदि ऐसा आवेदन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाने वाले आवेदन को नामंजूर करेगा:

परंतु ऐसा कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा, जब तक आवेदक को इस मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

- (4) जहां उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अविध के पूरा होने पर, यदि आवेदक को उसके आवेदन में की किमयों के बारे में अथवा उसके आवेदन को नामंजूर किए जाने के बारे में कोई संसूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसे रिजस्टर कर दिया गया समझा जाएगा।
- (5) ऐसे प्रत्येक भू-संपदा अभिकर्ता को, जिसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार रजिस्टर किया गया है, प्राधिकरण द्वारा एक रजिस्ट्रीकरण संख्यांक अनुदत्त किया जाएगा जिसे भू-संपदा अभिकर्ता द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा सुकर बनाए गए प्रत्येक विक्रय में कोट किया जाएगा।
- (6) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, विधिमान्य होगा और ऐसी अवधि के लिए ऐसी रीति में और ऐसी फीस का संदाय करने पर नवीकरणीय होगा जो विहित की जाए।
- (7) जहां कोई ऐसा भू-संपदा अभिकर्ता, जिसे इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है, उसकी किन्हीं शर्तों का या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य निबंधनों और शर्तों का भंग करता है या जहां प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा रिजस्ट्रीकरण भू-संपदा अभिकर्ता द्वारा दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा प्राप्त किया गया है वहां प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस रिजस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा या उसे ऐसी अविध के लिए निलंबित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे:

परंतु प्राधिकरण द्वारा ऐसा प्रतिसंहरण या निलंबन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि भू–संपदा अभिकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

10. धारा ९ के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक भू–संपदा अभिकर्ता,—

- (क) किसी भू-संपदा परियोजना में, यथास्थिति, किसी भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन या उसके भाग का, जिसका ऐसे संप्रवर्तक द्वारा किसी योजना क्षेत्र में, जो प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं है, विक्रय किया जा रहा है, विक्रय या क्रय सुकर नहीं बनाएगा;
- (ख) अपनी ऐसी लेखा बहियां, अभिलेख और दस्तावेज बनाए रखेगा और परिरक्षित रखेगा, जो विहित किए जाएं;
 - (ग) स्वयं को ऐसी किन्हीं अऋजु व्यापार पद्धतियों में, अर्थात्:—
 - (i) ऐसा कोई कथन करने की, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप से या दृश्यरूपण द्वारा ऐसी पद्धित में,—
 - (अ) जिससे मिथ्या रूप से यह व्यपदिष्ट होता है कि सेवाएं किसी विशिष्ट मानक या श्रेणी की हैं:
 - (आ) जिससे यह व्यपिदष्ट होता है कि संप्रवर्तक को या उसको ऐसा अनुमोदन या संबंधन प्राप्त है जो कि संप्रवर्तक के या उसके पास नहीं है;
 - (इ) जिससे संबंधित सेवाओं के बारे में मिथ्या या भ्रामक व्यपदेशन होता है:
 - (ii) किसी समाचारपत्र में या अन्यथा उन सेवाओं के बारे में, जिनकी प्रस्थापना किया जाना आशयित नहीं है, किसी विज्ञापन के प्रकाशन को अनुज्ञात करने की दृष्टि से,

अलिप्त नहीं करेगा।

- (घ) यथास्थिति, किसी भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन की बुकिंग के समय ऐसी सभी सूचना और दस्तावेजों के, जिनका आबंटिती हकदार हो, कब्जे को सुकर बनाएगा;
 - (ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का निवर्हन करेगा, जो विहित किए जाएं।

भू–संपदा अभिकर्ताओं के कृत्य।

अध्याय 3

संप्रवर्तक के कृत्य और कर्तव्य

11. (1) संप्रवर्तक, यथास्थिति, धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) या उपधारा (2) के अधीन संप्रवर्तक के कृत्य लॉगिन आई॰डी॰ और पासवर्ड प्राप्त होने पर प्राधिकरण की वेबसाइट पर लोक अवलोकन के लिए अपना वेब पेज सुजित करेगा और धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित प्रस्तावित परियोजना के सभी ब्यौरे निम्नलिखित सहित, यथा उपबंधित सभी क्षेत्रों में, प्रविष्ट करेगा,—

- (क) प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे;
- (ख) बुक किए गए, यथास्थिति, अपार्टमेंटों या भू-खंडों की संख्या और उनके प्रकार की तिमाही अद्यतन सूची;
 - (ग) बुक किए गए गैराजों की तिमाही अद्यतन संख्या सूची;
- (घ) लिए गए अनुमोदनों और उन अनुमोदनों की, जो कार्य प्रारंभ होने संबंधी प्रमाणपत्र के पश्चात् लंबित हैं, तिमाही अद्यतन सूची;
 - (ङ) परियोजना की तिमाही अद्यतन प्रास्थिति; और
- (च) ऐसी अन्य जानकारी और दस्तावेज, जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (2) संप्रवर्तक द्वारा जारी किए गए या प्रकाशित विज्ञापन या प्रास्पेक्टस में प्राधिकरण के वेबसाइट पते का सुस्पष्टत: उल्लेख किया जाएगा, जिसमें रजिस्टीकृत परियोजना के सभी ब्यौरे प्रविष्ट किए हुए हों और प्राधिकरण से प्राप्त रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और ऐसे अन्य विषयों को, जो उसके आनुषंगिक हैं, सिम्मिलित किया जाएगा।
- (3) संप्रवर्तक बुकिंग किए जाने और आबंटन पत्र के जारी किए जाने के समय आबंटिती को निम्नलिखित जानकारी, अर्थात्:—
 - (क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मंजूर रेखांक, अभिन्यास रेखांक, विनिर्देशों सहित, उस स्थल अथवा ऐसे अन्य स्थान पर, जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संप्रदर्शित करके:
 - (ख) परियोजना के, जिसके अंतर्गत नागरिक अवसंरचना जैसे जल, स्वच्छता और विद्युत आदि संबंधी उपबंध भी हैं, पूरा होने की प्रक्रमवार समय-अनुसूची,

उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) संप्रवर्तक —

(क) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन ऐसी सभी बाध्यताओं, उत्तरदायित्वों और कृत्यों के लिए अथवा आबंटितियों को, यथास्थिति, सभी अपार्टमेंटों, भू-खंडों या भवनों का अथवा आबंटितियों के संगम या सक्षम प्राधिकारी को सामान्य क्षेत्रों का हस्तांतरण किए जाने तक विक्रय करार के अनुसार, यथास्थिति, आबंटिती के प्रति या आबंटितियों के संगम के प्रति उत्तरदायी होगा:

परंतु अवसंरचनात्मक त्रुटि या किसी अन्य त्रुटि के संबंध में संप्रवर्तक का उत्तरदायित्व ऐसी अवधि के लिए, जो धारा 14 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट है, आबंटितियों को, यथास्थिति, सभी अपार्टमेंटों, भ-खंडों या भवनों की हस्तांतरण विलेख को निष्पादित कर दिए जाने के पश्चात भी, बना रहेगा;

(ख) तत्समय प्रवृत्त स्थानीय विधियों या अन्य विधियों के अनुसार समापन प्रमाणपत्र अथवा अधिभोग-प्रमाणपत्र या दोनों, जैसे वे लागू हों, सुसंगत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्राप्त करने तथा उसे, यथास्थिति, व्यष्टिक रूप से, आबंटितियों को या आबंटितियों के संगम को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा;

- (ग) जहां भू-संपदा परियोजना को पट्टाधृत भूमि पर विकसित किया जाता है, वहां पट्टा प्रमाणपत्र उसमें पट्टे की अविध को विनिर्दिष्ट करते हुए तथा यह प्रमाणित करते हुए कि पट्टाधृत भूमि के बारे में सभी शोध्यों और प्रभारों का संदाय कर दिया गया है, अभिप्राप्त करने के लिए तथा आबंटितियों के संगम को पट्टा प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (घ) आबंटितियों के संगम द्वारा परियोजना के अनुरक्षण का कार्यभार ग्रहण करने तक युक्तियुक्त प्रभारों पर अनिवार्य सेवाएं उपलब्ध कराने और उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा:
- (ङ) लागू विधियों के अधीन आबंटितियों का एक संगम या उनकी एक सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी या उनका एक परिसंघ बनाने को समर्थ बनाएगा:

परंतु स्थानीय विधियों के अभाव में, परियोजना में बहुसंख्यक आबंटितियों द्वारा, यथास्थिति, अपना भू—खंड या अपार्टमेंट या भवन बुक करने के तीन मास की अविध के भीतर आबंटितियों का संगम, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, बनाया जाएगा;

- (च) आबंटिती के पक्ष में, यथास्थिति, अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन की, इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन यथा उपबंधित आबंटितियों के संगम या सक्षम प्राधिकारी को सामान्य क्षेत्रों में के अविभाजित आनुपातिक हक सहित, एक रजिस्ट्रीकृत हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा;
- (छ) जब तक वह भू-संपदा परियोजना का वास्तिवक कब्जा, यथास्थिति, आबंटिती या आबंटितियों के संगम को अंतरित नहीं कर देता है, उन सभी निर्गमों का, जो उसने आबंटितियों से निर्गमों का संदाय करने के लिए (जिनके अंतर्गत भूमि की लागत, भूमि का किराया, जल या विद्युत के लिए नगरपालिक और अन्य स्थानीय कर, प्रभार, अनुरक्षण प्रभार, जिनके अंतर्गत बंधक ऋण और बंधकों या अन्य विल्लंगमों पर ब्याज तथा सक्षम प्राधिकारियों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को संदेय ऐसे अन्य दायित्व भी है; जो परियोजना से संबंधित हैं) संगृहीत की हैं, संदाय करेगा:

परंतु जहां कोई संप्रवर्तक अपने द्वारा आबंटितियों से संगृहीत सभी या किन्हीं निर्गमों का या किसी दायित्व, बंधक ऋण और उस पर ब्याज का, यथास्थिति, आबंटितियों या आबंटितियों के संगम को भू–संपदा परियोजना का अंतरण करने के पूर्व संदाय करने में असफल रहता है, वहां संप्रवर्तक, संपत्ति के अंतरण के पश्चात् भी ऐसे निर्गमों तथा शास्तिक प्रभारों का, यदि कोई हों, प्राधिकारी या उस व्यक्ति को, जिन्हें वे संदेय हैं, संदाय करने के लिए दायी बना रहेगा और ऐसी किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के खर्च के लिए, जो उनके संबंध में ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा लिया जाए, दायी होगा;

- (ज) उसके द्वारा, यथास्थिति, किसी अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन के विक्रय करार को निष्पादित किए जाने के पश्चात्, वह, यथास्थिति, ऐसे अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन पर बंधक या भार सृजित नहीं करेगा और यदि ऐसा कोई बंधक या भार बनाया या सृजित किया जाता है तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वह आबंटिती के, जिसने, यथास्थिति, ऐसा अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन लिया है या लेने का करार किया है, अधिकार और हितों को प्रभावित नहीं करेगा।
 - (5) संप्रवर्तक आबंटन को केवल विक्रय करार के निबंधनों के अनुसार रद्द कर सकेगा:

परंतु यदि आबंटिती ऐसे रद्दकरण से व्यथित है और ऐसा रद्दकरण, विक्रय करार के निबंधनों के अनुसार नहीं है, एकपक्षीय है और बिना किसी पर्याप्त कारण के है तो वह प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा।

- (6) संप्रवर्तक ऐसे सभी अन्य ब्यौरे तैयार करेगा और उन्हें बनाए रखेगा जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- 12. जहां कोई व्यक्ति सूचना, विज्ञापन या प्रास्पेक्टस में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर या, यथास्थिति, किसी माडल अपार्टमेन्ट, भूखंड या भवन के आधार पर कोई अग्रिम देता है या जमा करता है और उसे उसमें सिम्मिलित किसी गलत, मिथ्या कथन के कारण कोई हानि या नुकसान उठाना पड़ता है, तो उसकी संप्रवर्तक द्वारा इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित रीति में प्रतिपूर्ति की जाएगी:

विज्ञापन या प्रास्पेक्टस की सत्यता के बारे में संप्रवर्तक की बाध्यताएं। परंतु यदि सूचना विज्ञापन अथवा प्रास्पेक्ट्स में या, यथास्थिति, माडल अपार्टमेन्ट, भूखंड या भवन अंतर्विष्ट ऐसे गलत, मिथ्या कथन द्वारा व्यथित व्यक्ति प्रस्तावित परियोजना से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उसे उसका समस्त विनिधान राशि, ब्याज सिहत, ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, लौटाया जाएगा, और इस अधिनियम के अधीन उपबंधित रीति में उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

- 13. (1) संप्रवर्तक, यथास्थिति, अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन की लागत के दस प्रतिशत से अधिक राशि अग्रिम संदाय अथवा आवेदन फीस के रूप में किसी व्यक्ति से, उस व्यक्ति के साथ सर्वप्रथम लिखित करार किए बिना, स्वीकार नहीं करेगा और उक्त विक्रय करार को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्टर करेगा।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विक्रय करार ऐसे प्ररूप में होगा जो विहित किया जाए और उसमें पिरयोजना के विकास की, जिसके अंतर्गत भवन और अपार्टमेंट का सिन्नर्माण भी है, विनिर्देशों और आंतिरक विकास संकर्मों तथा बाह्य विकास संकर्मों की विशिष्टियां, वे तारीखें जिन तक और वह रीति, जिसमें, यथास्थिति, अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन की लागत के मद्दे आबंटितियों द्वारा संदाय किए जाने हैं, और वह तारीख, जिसको अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन का कब्जा सौंपा जाना है संप्रवर्तक द्वारा व्यतिक्रम की दशा में आबंटिती को और आबंटिती द्वारा संप्रवर्तक को संदेय ब्याज की दरें और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट की जाएंगी।
- 14. (1) संप्रवर्तक द्वारा प्रस्तावित परियोजना का सक्षम प्राधिकारियों द्वारा यथा अनुमोदित, मंजूर रेखांकों, अभिन्यास रेखांकों तथा विनिर्देशों के अनुसार विकास किया जाएगा और उसे पूरा किया जाएगा।
- (2) किसी विधि, संविदा या करार में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित, यथास्थिति, अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन के मंजूर रेखांक, अभिन्यास रेखांक और विनिर्देशों तथा फिक्सचरों, फिटिंगों, सुख-सुविधाओं और सामान्य क्षेत्रों को उस व्यक्ति को, जिसने, यथास्थिति, उक्त एक या अधिक अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन को लेने का करार किया है, प्रकट करने या प्रस्तुत करने के पश्चात्, संप्रवर्तक
 - (i) यथास्थिति, अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन के संबंध में ऐसे मंजूर रेखांकों, अभिन्यास रेखांकों और विनिर्देशों और उनमें वर्णित फिक्सचरों, फिटिंगों और सुख-सुविधाओं में, जिनको किए जाने का करार किया गया है, उस व्यक्ति की पूर्व सहमति के बिना परिवर्धन और फेरफार नहीं करेगा:

परंतु संप्रवर्तक ऐसे गौण परिवर्धन या फेरफार, जिनकी आबंटिती द्वारा अपेक्षा की जाए, या ऐसे गौण परिवर्तन या फेरफार, जो किसी प्राधिकृत वास्तुविद् या इंजीनियर द्वारा सिफारिश किए गए और सत्यापित स्थापत्य और अवसंरचनात्मक कारणों से आवश्यक हों, आबंटिती समुचित घोषणा और आबंटिती को संसूचना देने के पश्चात् कर सकेगा:

स्मष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजन के लिए, ''गौण परिवर्धन या फेरफार'' में क्षेत्र का जोड़ा जाना या ऊंचाई में परिवर्तन या किसी भवन के भाग का हटाया जाना या संरचना में कोई परिवर्तन, किसी दीवार या दीवार के किसी भाग का, विभाजन, कालम, बीम, कड़ी, फर्श, जिसके अंतर्गत मेजानीन फर्श भी है, या अन्य अवलंब या प्रवेश या बाहर जाने वाले किन्हीं अपेक्षित मार्गों में कोई परिवर्तन या उन्हें बंद करना या फिक्सचरों या उपस्करों आदि में कोई परिवर्तन सहित अवसंरचनात्मक परिवर्तन को अपवर्जित किया गया है:

(ii) भवनों के मंजूर रेखांकों, अभिन्यास रेखांकों और विनिर्देशों या परियोजना के भीतर सामान्य क्षेत्रों में, संप्रवर्तक से भिन्न, कम से कम दो-तिहाई उन आबंटितियों की, जिन्होंने ऐसे भवन में अपार्टमेंट लेने का करार किया है, पूर्व लिखित सहमित के बिना कोई अन्य फेरफार या परिवर्धन नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजन के लिए, आबंटिती को, उसके द्वारा बुक किए गए या उसके कुटुंब के नाम से बुक किए गए या कंपनियों या फर्मों या किसी व्यष्टि संगम, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जैसे अन्य व्यक्ति की दशा में, उसके नाम से बुक किए गए या उसकी सहबद्ध इकाइयों से संबंधित उद्यमों के नाम से बुक किए गए, यथास्थिति, अपार्टमेंट या भू-खंडों की संख्या को विचार में लाए बिना, केवल एक आबंटिती के रूप में माना जाएगा।

(3) यदि कब्जा सौंपे जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर आबंटिती द्वारा, ऐसे विकास से संबंधित किसी संरचनात्मक त्रुटि या सेवाओं के कर्मकौशल, क्वालिटी या उपबंध या संप्रवर्तक की किन्हीं अन्य बाध्यताओं की ओर संप्रवर्तक का ध्यान दिलाया जाता है तो संप्रवर्तक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी त्रुटियों को बिना किन्हीं अतिरिक्त प्रभारों के तीस दिन के भीतर दूर कराए और संप्रवर्तक द्वारा ऐसी त्रुटियों को ऐसे समय के भीतर दूर करने में असफल रहने की दशा में व्यथित आबंटिती उस रीति में वह समुचित प्रतिकर पाने का हकदार होगा, जो इस अधिनियम के अधीन उपबंधित हो।

संप्रवर्तक द्वारा सर्वप्रथम विक्रय करार किए बिना कोई निक्षेप या अग्रिम न लिया जाना।

संप्रवर्तक द्वारा मंजूर रेखांकों और परियोजना विनिर्देशों का पालन किया जाना। भू-संपदा परियोजना का अन्य पक्षकार को अंतरण की दशा में संप्रवर्तक की बाध्यताएं। 15. (1) संप्रवर्तक, दो-तिहाई आबंटितियों से पूर्व लिखित सहमति अभिप्राप्त किए बिना और प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना, संप्रवर्तक के सिवाय किसी अन्य पक्षकार को किसी संपदा परियोजना के संबंध में अपने बहुमत अधिकार और दायित्व अंतरित या समनुदेशित नहीं करेगा:

परंतु ऐसा अंतरण या समनुदेशन तत्कालीन संप्रवर्तक द्वारा बनाई गई भू–संपदा परियोजना में, यथास्थिति, अपार्टमेंट, भू–खंडों या भवनों के आबंटन या विक्रय को प्रभावी नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, आबंटिती को, उसके द्वारा बुक किए गए या उसके कुटुंब के नाम से बुक किए गए या कंपनियों या फर्मों या किसी व्यष्टि-संगम, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो जैसे अन्य व्यक्ति की दशा में, उसके नाम से बुक किए गए या उसकी सहबद्ध इकाइयों से संबंधित उद्यमों के नाम से बुक किए गए, यथास्थिति, अपार्टमेंट या भू-खंडों को विचार में लाए बिना, केवल एक आबंटिती के रूप में माना जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आबंटितियों और प्राधिकरण द्वारा अंतरण या समनुदेशन अनुज्ञात किए जाने पर आशियत संप्रवर्तक से, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन सभी लंबित बाध्यताओं और तत्कालीन संप्रवर्तक द्वारा आबंटितियों के साथ किए गए विक्रय करार के अनुसार लंबित बाध्यताओं का स्वतंत्र रूप से पालन किए जाने की अपेक्षा की जाएगी:

परंतु इस धारा के उपबंधों के अधीन अनुज्ञात किसी अंतरण या समनुदेशन के परिणामस्वरूप आशयित संप्रवर्तक को भू-संपदा परियोजना को पूरा करने के लिए समय का विस्तार नहीं किया जाएगा और उससे तत्कालीन संप्रवर्तक की सभी लंबित बाध्यताओं का पालन करने की अपेक्षा की जाएगी और व्यतिक्रम की दशा में ऐसा आशयित संप्रवर्तक, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यथा-उपबंधित, यथास्थिति, भंग या विलंब के परिणामों का दायी होगा।

भू-संपदा परियोजना के बीमे के संबंध में संप्रवर्तक की बाध्यता।

- 16. (1) संप्रवर्तक ऐसे सभी बीमा अभिप्राप्त करेगा, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, इसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में बीमा भी हैं, किंतु ये निम्नलिखित के संबंध में बीमा तक सीमित नहीं है,—
 - (i) भू-संपदा परियोजना के भागरूप भू-खंड और भवन का हक; और
 - (ii) भू-संपदा परियोजना का सन्निर्माण।
- (2) संप्रवर्तक, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट बीमा के संबंध में प्रीमियम और प्रभार संदाय करने का दायी होगा और वह आबंटितियों के संगम को बीमा अंतरण करने से पूर्व उसका संदाय करेगा।
- (3) संप्रवर्तक के आबंटिती के साथ विक्रय करार करने के समय, उपधारा (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट बीमा, यथास्थिति, आबंटिती या आबंटितियों के संगम के फायदे के लिए अंतरित हो जाएगा।
- (4) आबंटितियों का संगम के बनाए जाने पर उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट बीमे से संबंधित सभी दस्तावेज आबंटितियों के संगम को सौंप दिए जाएंगे।

हक का अंतरण।

17. (1) संप्रवर्तक, यथास्थिति, आबंटितियों के संगम या सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में एक रिजस्ट्रीकृत हस्तांतरण विलेख सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित आनुपातिक हक सिहत निष्पादित करेगा और स्थानीय विधियों के अधीन यथा उपबंधित मंजूर रेखांकों के अनुसार विनिंदिष्ट अविध के भीतर किसी भू–संपदा पिरयोजना में आबंटितियों को, यथास्थिति, भू–संपदा, अपार्टमेंट या भवन का, यथास्थिति, आबंटितियों के संगम या सक्षम प्राधिकारी को सामान्य क्षेत्रों का भौतिक कब्जा और उससे तात्पर्यित अन्य हक दस्तावेज सौंपेगा:

पंरतु किसी स्थानीय विधि के न होने पर, संप्रवर्तक द्वारा अधिभोग प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर इस धारा के अधीन, यथास्थिति, आबंटिती या आबंटितियों के संगम या सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया जाएगा।

(2) अधिभोग संबंधी प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने और उपधारा (1) के निबंधनानुसार आबंटितियों को भौतिक कब्जा सौंपे जाने के पश्चात् संप्रवर्तक का यह दायित्व होगा कि वह स्थानीय विधि के अनुसार, सामान्य क्षेत्रों सहित आवश्यक दस्तावेज और रेखांक, यथास्थिति, आबंटितियों के संगम या सक्षम प्राधिकारी को सौंप दे:

परंतु किसी स्थानीय विधि के न होने पर संप्रवर्तक, अधिभोग प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् तीस दिन के भीतर, यथास्थिति, आबंटितियों के संगम या सक्षम प्राधिकारी को सामान्य क्षेत्रों सहित आवश्यक दस्तावेज और रेखांक सौंपेगा।

18. (1) यदि संप्रवर्तक,—

रकम का लौटाया जाना और प्रतिपूर्ति।

- (क) विक्रय करार के निबंधनों के अनुसार उसमें विनिर्दिष्ट तारीख तक सम्यक् रूप से पूरा करने में; या
- (ख) इस अधिनियम के अधीन अथवा किसी अन्य कारण से रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या प्रतिसंहरण के कारण विकासकर्ता के रूप में उसका कारबार बंद होने के कारण,

यथास्थिति, किसी अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन को पूरा करने में असफल रहता है या उसका कब्जा देने में असमर्थ रहता है तो वह उपलब्ध किसी अन्य उपचार पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना आबंटिती की मांग पर, यदि आंबटिती परियोजना से प्रत्याहृत होना चाहृता है तो यथास्थिति, उस अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त रकम को. ऐसी दर पर ब्याज सहित. जो इस निमित्त विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित रीति में प्रतिकर लौटाने का दायी होगा:

परंतु जहां किसी आबंटिती का परियोजना से प्रत्याहरण का आशय नहीं है, वहां संप्रवर्तक द्वारा उसे कब्जा सौंपे जाने तक विलम्ब के प्रत्येक मास के लिए उस दर पर जो विहित की जाए ब्याज का संदाय किया जाएगा।

- (2) संप्रवर्तक ऐसी भूमि के, जिस पर इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित रीति से परियोजना विकसित की जा रही है या विकसित की गई है, दोषपूर्ण हक के कारण हुई किसी हानि की दशा में आबंटितियों की प्रतिपूर्ति करेगा और इस उपधारा के अधीन प्रतिकर का दावा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंधित परिसीमा से वर्जित नहीं होगा।
- (3) यदि संप्रवर्तक इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या विक्रय करार के अधीन उस पर अधिरोपित किन्हीं अन्य बाध्यताओं का निर्वहन करने में असफल रहता है तो वह आबंटितियों को प्रतिकर का इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित रीति में संदाय करने के लिए दायी होगा।

अध्याय 4

आबंटितियों के अधिकार और कर्तव्य

19. (1) आबंटिती सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों सहित मंजूर रेखांक अभिन्यास रेखांकों से आवंटितियों के संबंधित सूचना तथा इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों या संप्रवर्तक द्वारा ^{अधिकार और} हस्ताक्षरित विक्रय करार में यथा उपबंधित ऐसी अन्य सूचना अभिप्राप्त करने का हकदार होगा।

कर्तव्य।

- (2) आबंटिती परियोजना के, जिसके अंतर्गत जल, स्वच्छता, विद्युत और अन्य सुविधाओं तथा अन्य सेवाओं का, जो विक्रय करार के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार संप्रवर्तन और आंबटिती के बीच करार पाई जाएं, का उपबंध भी है, प्रक्रमवार पूरा होने के समय अनुसूची के बारे में जानने का हकदार होगा।
- (3) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ठ) के उपखंड (इ) के अधीन संप्रवर्तक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, आबंटिती, यथास्थिति, अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन के कब्जे का और आबंटितियों का संगम सामान्य क्षेत्रों के कब्जे का दावा करने का हकदार होगा।
- (4) यदि संप्रवर्तक विक्रय करार के निबंधनों के अनुसार या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन उसके रिजस्ट्रीकरण का निलंबन या प्रतिसंहरण हो जाने के कारण, विकासकर्ता के रूप में उसका कारबार बंद हो जाने के कारण या विक्रय करार के निबंधनानुसार अनुपालन करने में असफल रहता है या, यथास्थिति, अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन का कब्जा देने में असमर्थ रहता है तो आबंटिती संप्रवर्तक से संदत्त रकम के प्रतिदाय का ऐसी दर पर जो विहित की जाए, ब्याज तथा अधिनियम के अधीन उपबंधित रीति में प्रतिकर सहित दावा करने का हकदार होगा।
- (5) संप्रवर्तक द्वारा यथास्थिति, अपार्टमेंट, या भू-खंड या भवन का भौतिक कब्जा सौंपे जाने के पश्चात् आबंटिती आवश्यक दस्तावेज और रेखांक, जिनके अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों के दस्तावेज और रेखांक भी हैं, लेने का हकदार होगा।
- (6) प्रत्येक आबंटिती, जिसने धारा 13 के अधीन, यथास्थिति, कोई अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन लेने के लिए विक्रय करार किया है, आवश्यक संदाय, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो उक्त विक्रय

करार में विनिर्दिष्ट की जाएं, करने का उत्तरदायी होगा और समुचित समय और स्थान पर, उक्त विक्रय करार के रजिस्ट्रीकरण संबंधी प्रभारों, नगरपालिका करों, जल और विद्युत प्रभारों, अनुरक्षण प्रभारों, भूमि संबंधी किराए और अन्य प्रभारों, यदि कोई हों, का संदाय करेगा।

- (7) आबंटिती, उपधारा (6) के अधीन संदत्त की जाने वाली किसी रकम या प्रभारों के मद्दे संदाय करने में किसी विलंब के लिए ब्याज का, ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, संदाय करने के लिए दायी होगा।
- (8) आबंटिती की उपधारा (6) के अधीन आबंटिती की बाध्यताओं और उपधारा (7) के अधीन ब्याज के मद्दे उसके दायित्व को संप्रवर्तक और ऐसे आबंटिती के बीच परस्पर सहमित होने पर कम किया जा सकेगा।
- (9) प्रत्येक आबंटिती, यथास्थिति, अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन का कब्जा लेने के पश्चात् आबंटितियों का एक संगम या सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी या उनका एक परिसंघ बनाए जाने के प्रति सहभागी होगा।
- (10) प्रत्येक आबंटिती, यथास्थिति, अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र जारी किए जाने के दो मास की अविध के भीतर, यथास्थिति, उक्त अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन का भौतिक कब्जा लेगा।
- (11) प्रत्येक आबंटिती, इस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन यथा उपबंधित, यथास्थिति, अपार्टमेंट, भू-खंड या भवन हस्तांतरण विलेख का रजिस्ट्रीकरण करने संबंधी कार्रवाई में भाग लेगा।

अध्याय 5

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना और निगमन। 20. (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिसूचना द्वारा भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण की इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करने तथा उसको समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए स्थापना करेगी:

परंतु दो या अधिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों की समुचित सरकार, यदि वह ठीक समझे, एक एकल प्राधिकरण की स्थापना कर सकेगी:

परंतु यह और कि समुचित सरकार, यदि वह ठीक समझे, यथास्थिति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक से अधिक प्राधिकरण स्थापित कर सकेगी:

परंतु यह भी कि समुचित सरकार, आदेश द्वारा इस धारा के अधीन विनियामक प्राधिकरण की स्थापना किए जाने तक किसी विनियामक प्राधिकारी या ऐसे किसी अधिकारी, अधिमानत: आवासन से संबद्ध विभाग के सचिव को, इस अधिनियम के अधीन प्रयोजनों के लिए विनियामक प्राधिकारी के रूप में अभिहित करेगी:

परंतु यह भी कि विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के पश्चात् पदाभिहित विनियामक प्राधिकारी के पास लंबित सभी आवेदन, परिवाद या मामले इस प्रकार स्थापित विनियामक प्राधिकरण को अंतरित हो जाएंगे और उनकी सुनवाई उसी प्रक्रम से की जाएगी जिस पर ऐसे आवेदन, परिवाद या मामले अंतरित हुए हैं।

- (2) प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम का शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शिक्त होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगा या उस पर वाद लाया जाएगा।
- 21. प्राधिकरण एक अध्यक्ष और दो से अन्यून पूर्णकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनकी नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा की जाएगी।
- प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की

अर्हताएं।

प्राधिकरण की

संरचना ।

22. प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके नामनिर्देशिती, आवासन विभाग के सचिव और विधि सचिव से मिलकर बनी एक चयन सिमित की सिफारिशों पर ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्तियों, सुसंगत क्षेत्रों से तकनीकी विशेषज्ञों में से की जाएगी जिनके पास शहरी विकास, आवासन, भू–संपदा विकास, अवसंरचना, अर्थव्यवस्था, योजना, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, प्रबंधन, समाज सेवा, लोक कार्यों और प्रशासन में अध्यक्ष की दशा में कम से कम बीस वर्ष और सदस्यों की दशा में कम से कम पंद्रह वर्ष का पर्याप्त ज्ञान और वृत्तिक अनुभव हो:

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति की, जो राज्य सरकार की सेवा में है या रहा है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति तब तक नहीं की जाएगी जब तक ऐसे व्यक्ति ने केन्द्रीय सरकार में अपर सचिव का पद अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में उसके समतुल्य कोई पद धारण न किया हो:

परंतु यह और कि ऐसे किसी व्यक्ति की, जो राज्य सरकार की सेवा में है या रहा है, सदस्य के रूप में नियुक्ति तब तक नहीं की जाएगी जब तक ऐसे व्यक्ति ने राज्य सरकार में सचिव का पद अथवा राज्य सरकार में या केन्द्रीय सरकार में उसके समतुल्य कोई पद धारण न किया हुआ हो।

23. (1) अध्यक्ष और सदस्य उस तारीख से, जिसको वे अपना पद ग्रहण करते हैं, पांच वर्ष से अनिधक अध्यक्ष और सदस्यों अविध के लिए या उनके द्वारा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और

भत्ते।

- (2) समुचित सरकार, किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करने के पूर्व, अपना यह समाधान करेगी कि उस व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे ऐसे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
- 24. (1) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं और उनमें उनकी पदावधि के दौरान ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो उनके लिए अलाभकर हो।

(2) धारा 23 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य—

- (क) समुचित सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा:
 - (ख) इस अधिनियम की धारा 26 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकेगा।
- (3) यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद में हुई रिक्ति को उस तारीख से, जिसको ऐसी रिक्ति होती है , तीन मास की अवधि के भीतर भरा जाएगा।
- 25. अध्यक्ष को प्राधिकरण के कार्यकलापों को करने में साधारण अधीक्षण और निदेशन की शक्तियां होंगी तथा वह प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त प्राधिकरण की ऐसी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएं।

प्रशासनिक शक्तियां।

26. (1) समुचित सरकार अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को पद से हटा सकेगी, यदि यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य-

कतिपय परिस्थितियों में अध्यक्ष और सदस्यों का पद से हटाया जाना।

- (क) दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है; या
- (ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या
- (ग) शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या
- (घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
- (ङ) उसने अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिकुल प्रभाव पड सकता है।
- (2) अध्यक्ष या सदस्य को, उसके पद से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के, जिसमें ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो, पश्चात् ही समुचित सरकार द्वारा उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट आधार पर हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं।
 - 27. (1) अध्यक्ष या कोई सदस्य उस रूप में पद पर न रहने पर-
 - (क) उस तारीख से, जिसको वह उस पद पर नहीं रहता है, ऐसे किसी व्यक्ति या संगठन के, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य से सहयुक्त रहा है, प्रबंधन या प्रशासन में या उससे संबंधित कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा:

अध्यक्ष या सदस्यों के पद पर न रहने के पश्चात नियोजन

परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी कानूनी प्राधिकरण या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) के अधीन यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संप्रवर्तक नहीं है, अधीन के किसी नियोजन को लागू नहीं होगी:

2013 का 18

- (ख) ऐसी किसी विनिर्दिष्ट कार्यवाही या संव्यवहार या परक्रामण किसी व्यक्ति या संगठन के लिए या उसकी ओर से या ऐसे किसी मामले के संबंध में जिसमें प्राधिकरण एक पक्षकार है और जिसके संबंध में अध्यक्ष या ऐसे सदस्य ने, पद पर न रहने के पूर्व, प्राधिकरण के लिए कार्य किया था या उसे सलाह दी थीं, कार्य नहीं करेगा;
- (ग) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो ऐसी सूचना का, जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी हैसियत में अभिप्राप्त किया गया था, प्रयोग कर रहा है और जो जनसाधारण को उपलब्ध नहीं है अथवा जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने के योग्य नहीं है, सलाह नहीं देगा;
- (घ) ऐसे किसी अस्तित्व के साथ, जिसके साथ उसने उस रूप में अपनी पदावधि के दौरान प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण शासकीय कार्य किए थे, सेवा–संविदा नहीं करेगा या उसके निदेशक बोर्ड में कोई नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा या उसके साथ नियोजन की किसी प्रस्थापना को स्वीकार नहीं करेगा।
- (2) अध्यक्ष और सदस्य किसी व्यक्ति को ऐसे किसी विषय की, जो उसके द्वारा उस रूप में कार्य करते समय उसके विचाराधीन लाया गया था या उसे ज्ञात था, संसूचना नहीं देगा या उसको प्रकट नहीं करेगा।

प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी।

- 28. (1) समुचित सरकार, प्राधिकरण के परामर्श से, उतने अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी, जितने वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, जो अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।
- (2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

प्राधिकरण की बैठकें।

- 29. (1) प्राधिकरण ऐसे समयों और स्थानों पर बैठकों करेगा और अपनी बैठकों के कार्य संचालन के बारे में (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) ऐसे प्रक्रिया-नियमों का पालन करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (2) यदि अध्यक्ष, किसी कारणवश प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई अन्य सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (3) ऐसे सभी प्रश्नों का, जो प्राधिकरण की किसी बैठक के समक्ष उठाए जाएं, विनिश्चय, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का अथवा उसकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का मत निर्णायक होगा।
- (4) उन प्रश्नों पर, जो प्राधिकरण के समक्ष आते हैं, यथासंभव शीघ्रता के साथ, विचार किया जाएगा और प्राधिकरण उनका निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर करेगा:

परंतु जहां ऐसे किसी प्रश्न का निपटारा साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है, वहां प्राधिकरण आवेदन का निपटारा उस अवधि के भीतर न किए जाने के कारण लेखबद्ध करेगा।

रिक्तियों आदि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

- 30. प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि
 - (क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या
 - (ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या
- (ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जिससे मामले के गुणागुण पर कोई प्रभाव नहीं पडता है।
- 31. (1) कोई व्यथित व्यक्ति, यथास्थिति, किसी संप्रवर्तक, आबंटिती या भू–संपदा अभिकर्ता के विरुद्ध अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के किसी अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास परिवाद फाइल कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''व्यक्ति'' के अंतर्गत आबंटियों का संगम, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम भी है।

प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी को परिवाद का फाइल किया जाना।

- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई परिवाद फाइल करने का प्रारूप, रीति और फीस वह होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- 32. प्राधिकरण , स्वास्थ्य, पारदर्शी, दक्ष और प्रतिस्पर्धी भू-संपदा सेक्टर के विकास और संवर्धन को सुकर प्राधिकरण के बनाने के लिए, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करेगा,—

भू-संपदा सेक्टर के संवर्धन संबंधी कृत्य।

- (क) आबंटितियों संप्रवर्तक और भू-सम्पदा अभिकर्ता के हित संरक्षण;
- (ख) परियोजना को समय से पूरा करने के लिए समयबद्ध परियोजना अनुमोदनों और अनापत्तियों को सुनिश्चित करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली का सृजन;
- (ग) सक्षम प्राधिकारियों और उनके पदधारियों के कार्य लोप या किए जाने के विरुद्ध पारदर्शक और शक्तिशाली शिकायत प्रतितोष तंत्र का सूजन;
- (घ) भू-सम्पदा सेक्टर में विनिधान को प्रोत्साहन देने के उपाय, जिसके अंतर्गत सस्ते आवास क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता की वृद्धि के उपाय भी हैं;
- (ङ) पर्यावरणीय रूप से संधार्य तथा सस्ते आवास के सन्निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए मानकीकरण के संवर्धन के लिए और समुचित सन्निर्माण सामग्रियों, फिक्सचरों, फिटिंगों और सन्निर्माण तकनीकों के उपयोग के उपाय:
- (च) विकास के विभिन्न पैरामीटरों के आधार पर परियोजनाओं के श्रेणीकरण, जिसके अन्तर्गत संप्रवर्तकों का श्रेणीकरण भी है, को प्रोत्साहित करना;
- (छ) उपभोक्ता या संप्रवर्तक संगमों द्वारा गठित विवाद प्रतितोष पीठों के माध्यम से संप्रवर्तकों और आबंटितियों के मध्य विवादों के सौहार्दपूर्ण सुलह को सुकर बनाने के लिए उपाय;
- (ज) डिजिटीकरण भू-अभिलेखों और हक प्रतिभृति के साथ अंतिम सम्पत्ति हक की प्रणाली को सुकर बनाने के उपाय;
 - (झ) भू-संपदा सेक्टर के विकास से संबंधित विषयों में समुचित सरकार को सलाह देना;
 - (ञ) कोई अन्य मुद्दा जो प्राधिकरण भू-संपदा सेक्टर के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे।
- 33. (1) समुचित सरकार, भू-सम्पदा सेक्टर या किसी अन्य विषय पर नीति बनाते समय (जिसके पक्षसमर्थन और अन्तर्गत भू-सेक्टर से सम्बंधित विधियों का पुनर्विलोकन भी है) प्राधिकरण को, भू-सम्पदा सेक्टर पर ऐसी नीति या विधि के सम्भाव्य प्रभाव पर उसकी राय के लिए निर्देश कर सकेगी और प्राधिकरण, ऐसे किसी निर्देश के प्राप्त होने पर, ऐसे निर्देश के किए जाने की साठ दिन की अवधि के भीतर समृचित सरकार को अपनी राय देगी जिस पर वह तत्पश्चात् ऐसी और कार्रवाई कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

जागरूकता उपाय।

- (2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा दी गई राय, समुचित सरकार पर ऐसी नीति या विधि बनाने के सम्बंध में आबद्धकर नहीं होगी।
- (3) प्राधिकरण, पक्ष समर्थन के संवर्धन, जागरूकता का सृजन करने के लिए और भू–सम्पदा सेक्टर से संबंधित विधियों और नीतियों के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए समुचित उपाय करेगा।
 - 34. प्राधिकरण के कृत्यों में, निम्नलिखित सिम्मिलित होंगे—

प्राधिकरण के कृत्य।

- (क) भू–सम्पदा परियोजनाओं को और इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत भू–संपदा अभिकर्ताओं को रजिस्टर करना और विनियमित करना:
- (ख) उन सभी भू-संपदा परियोजनाओं का जन साधारण के अवलोकन के लिए, जिनके लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, अभिलेखों की, ऐसे ब्यौरों सहित, जो विहित किए जाएं, जिसमें उस आवेदन में उपलब्ध कराई गई सूचना भी है जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है, प्रकाशित करना और वेबसाइट बनाए रखना;

- (ग) अपनी वेबसाइट पर जनसाधारण के अवलोकन के लिए, साधारण जनता की पहुंच के लिए एक डाटा बेस बनाए रखना और उसमें ऐसे संप्रवर्तकों के नाम और फोटो व्यतिक्रमी के रूप में प्रविष्ट करना, जिसके अंतर्गत उन परियोजनाओं के, जिनके लिए अधिनियम के अधीन उनके रिजस्ट्रीकरण को प्रतिसंहृत किया गया है या उन्हें दंडित किया गया है और ऐसा करने के कारणों के ब्यौरे भी हैं;
- (घ) अपनी वेबसाइट पर, जनसाधारण के अवलोकन के लिए, एक डाटाबेस बनाए रखना और ऐसे भू-संपदा अभिकर्ताओं के नाम और फोटो को, जिन्होंने आवेदन किया है और जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है, ऐसे ब्यौरों सहित, जो विहित किए जाएं, जिसके अंतर्गत वे अभिकर्ता भी हैं, जिनका रजिस्ट्रीकरण अस्वीकार या प्रतिसंहृत कर दिया गया है, उसमें प्रविष्ट करना;
- (ङ) अपनी अधिकारिता के अधीन प्रत्येक क्षेत्र के लिए विनियमों के माध्यम से, यथास्थिति, आबंटितियों या संप्रवर्तकों या भू-सम्पदा अभिकर्ता पर उद्गृहीत की जाने वाली मानक फीस नियत करना;
- (च) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन संप्रवर्तकों, आबंटितियों और भू-संपदा अभिकर्ताओं पर अधिरोपित बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- (छ) इस अधिनियम के अधीन अपनी शिक्तयों के प्रयोग में अपने विनियमों या आदेशों या निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- (ज) ऐसे अन्य कृत्य करना जो, समुचित सरकार द्वारा प्राधिकरण को सौंपे जाएं और जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

सूचना मंगाने, अन्वेषण करने की प्राधिकरण की शक्तियां।

- 35. (1) जहां प्राधिकरण अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों से संबंधित किसी परिवाद पर या स्वप्रेरणा से ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह लिखित आदेश और उसके संबंध में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, यथास्थित, किसी संप्रवर्तक या आबंटिती या भू–संपदा अभिकर्ता से किसी भी समय लिखित में ऐसी सूचना या अपने कार्यों से संबंधित स्पष्टीकरण,जैसी प्राधिकरण अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगा, और यथास्थिति, संप्रवर्तक या आबंटिती या भू–संपदा अभिकर्ता के कार्यों के संबंध में जांच करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा।
- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण को, उपधारा (1) के अधीन शिक्तयों का प्रयोग करते समय वहीं शिक्तयां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निम्निलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात:—

1908 का 5

- (i) लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का ऐसे स्थान और ऐसे समय पर, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रकटीकरण और पेश किया जाना;
 - (ii) व्यक्तियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना;
 - (iii) साक्षियों की परीक्षा या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन निकालना;
 - (iv) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

अतंरिम आदेश जारी करने की शक्ति। 36. जहां जांच के दौरान प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि जहां कोई कार्य इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में किया गया है और किया जाना जारी है या यह कि ऐसा कार्य किया ही जाने वाला है, वहां प्राधिकरण आदेश द्वारा, किसी संप्रवर्तक, आबंटिती या भू-संपदा अभिकर्ता को ऐसी जांच के समाप्त होने तक अथवा अगले आदेशों तक, ऐसे पक्षकार को सूचना दिए बिना, जहां प्राधिकरण ऐसा आवश्यक समझे, अवरुद्ध कर सकेगा।

निदेश जारी करने की प्राधिकरण की शक्तियां। 37. प्राधिकरण, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए समय-समय पर, यथास्थिति, संप्रवर्तकों या आबंटितियों या भू-संपदा अभिकर्ताओं को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे और ऐसे निदेश सभी संबंधित व्यक्तियों पर आबद्धकर होंगे।

38. (1) प्राधिकरण को, संप्रवर्तकों, आबंटितियों और भू–संपदा अभिकर्ताओं पर डाली गई बाध्यताओं के किसी उल्लंघन के संबंध में, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन शास्ति या ब्याज अधिरोपित करने की शक्ति होगी।

प्राधिकरण की शक्तियां।

- (2) प्राधिकरण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शिक्तियां होंगी।
 - (3) जहां ऐसे करार, कार्रवाई, लोप, पद्धित या प्रक्रिया के संबंध में कोई विवाद्यक उठाया जाता है,—
 - (क) जिसमें भू–संपदा परियोजना के विकास के संबंध में प्रतिस्पर्धा के पर्याप्त निवारण निर्बंधन या विरूपण है, या
 - (ख) जिसमें एकाधिकारिक स्थिति की बाजार शिक्त का आबंटितियों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए दुरुपयोग किए जाने का प्रभाव है,

वहां प्राधिकरण स्वप्रेरणा से ऐसे विवाद्यक के संबंध में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को निर्देश कर सकेगा।

39. प्राधिकरण, अभिलेख से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, इस अधिनियम के अधीन किए आदेशों का सुधार। गए आदेश की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर किसी समय, उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लाई जाती है तो ऐसा संशोधन करेगा:

परंतु ऐसा कोई संशोधन ऐसे किसी आदेश के संबंध में, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत की गई है, नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का सुधार करते समय, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित उसके आदेश के सारवान् भाग का संशोधन नहीं करेगा।

40. (1) यदि, यथास्थिति, संप्रवर्तक या आबंटिती या भू-संपदा अभिकर्ता इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक अधिकारी या विनियामक प्राधिकरण या अपील अधिकरण द्वारा उसे अधिरोपित किसी ब्याज या शास्ति या प्रतिकर का संदाय करने में असफल रहता है, तो वह, जिसके अन्तर्गत भू-राजस्व का बकाया भी है, उस संप्रवर्तक या आबंटिती या भू-संपदा अभिकर्ता से ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वसूलनीय होगा।

ब्याज या शास्ति या प्रतिकर की वसूली और आदेश, आदि का प्रवर्तन।

(2) यदि, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक अधिकारी या विनियामक प्राधिकरण या अपील अधिकरण किसी व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य करने या कोई कार्य करने से प्रविरत रहने का, जिसके करने के लिए वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सशक्त है, कोई आदेश या निदेश जारी करता है तो ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश, निदेश का पालन करने में असफल रहने की दशा में, वह ऐसी रीति में प्रवर्तित किया जाएगा, जो विहित की जाए।

अध्याय 6

केन्द्रीय सलाहकार परिषद्

41. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, केन्द्रीय सलाहकार परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् की स्थापना करेगी।

केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की स्थापना।

- (2) भारत सरकार का आवासन से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय का प्रभारी मंत्री केन्द्रीय सलाहकार परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।
- (3) केन्द्रीय सलाहकार परिषद् वित्त मंत्रालय, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, नीति आयोग, राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास और शहरी विकास निगम के प्रतिनिधियों, राज्य सरकार के चक्रानुक्रम से चयनित किए जाने वाले पांच प्रतिनिधियों, भू-संपद्म विनियामक प्राधिकारियों के चक्रानुक्रम से चयनित किए जाने वाले पांच प्रतिनिधियों और यथा अधिसूचित केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से मिलकर बनेगी।

(4) केन्द्रीय सलाहकार परिषद् में भू-सम्पदा उद्योग, उपभोक्ताओं, भू-सम्पदा अभिकर्ता, सिन्नर्माण करने वाले श्रिमकों, गैर-सरकारी संगठनों और भू-सम्पदा सेक्टर में शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दस से अनिधक सदस्य भी होंगे।

केन्द्रीय सलाहकार परिषद् के कृत्य।

- 42. (1) केन्द्रीय सलाहकार परिषद् के कृत्य केन्द्रीय सरकार को-
 - (क) इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी विषयों पर:
 - (ख) नीति विषयक मुख्य प्रश्नों पर;
 - (ग) उपभोक्ता हित के संरक्षण के सम्बध में;
 - (घ) भू-सम्पदा सेक्टर के वर्धन और विकास के संवर्धन के संबंध में;
 - (ङ) किसी अन्य विषय पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपा जाए,

सलाह देने और सिफारिश करने के होंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन यथा उपबंधित विषयों पर केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए नियम विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

अध्याय 7

भू-सम्पदा अपील अधिकरण

भू-सम्पदा अपील अधिकरण की स्थापना।

- 43. (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, अधिसूचना द्वारा, (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) भू-सम्पदा अपील अधिकरण के नाम से ज्ञात एक अपील अधिकरण की स्थापना करेगी।
- (2) समुचित सरकार, यदि आवश्यक समझे, यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में की विभिन्न अधिकारिताओं के लिए अपील अधिकरण की एक या अधिक न्यायपीठों की स्थापना कर सकेगी।
- (3) अपील अधिकरण की प्रत्येक न्यायपीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक या तकनीकी सदस्य होगा।
- (4) दो या अधिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों की समुचित सरकार, जो वह ठीक समझे, एक एकल अपील अधिकरण स्थापित कर सकेगी:

परंतु समुचित सरकार, आदेश द्वारा, इस धारा के अधीन अपील अधिकरण की स्थापना किए जाने तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कृत्यशील अपील अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपील अधिकरण पदािभहित करेगी:

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अपील अधिकरण की स्थापना के पश्चात् इस धारा के चौथे परंतुक के अधीन उस रूप में अभिहित अपील अधिकरण के पास लंबित सभी मामले इस प्रकार स्थापित अपील अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे और उनकी सुनवाई उस प्रक्रम से की जाएगी जिस पर वह अपील अन्तरित हुई है।

(5) प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस अपील अधिकरण के समक्ष, जिसकी उस मामले के संबंध में अधिकारिता है, अपील फाइल कर सकेगा:

परंतु जहां कोई संप्रवर्तक, अपील अधिकरण में कोई अपील फाइल करता है वहां संप्रवर्तक द्वारा सर्वप्रथम अपील अधिकरण के पास, यथास्थिति, शास्ति का कम से कम तीस प्रतिशत या ऐसे उच्चतर प्रतिशत का, जो अपील अधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए, अन्यथा आबंटिती को संदत्त की जाने वाली कुल रकम, जिसके अंतर्गत ब्याज और उस पर अधिरोपित प्रतिकर, यदि कोई हो, भी है, या दोनों उक्त अपील की सुनवाई के पूर्व, जमा किए बिना ग्रहण नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए ''व्यक्ति'' के अंतर्गत आबंटितियों का संगम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम भी है।

44. (1) समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी या कोई व्यक्ति, जो प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी निदेश या आदेश या विनिश्चय से व्यथित हो, अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।

विवादों और अपीलों के निपटारे के लिए अपील अधिकरण को आवेदन। (2) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील, प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए निदेश या किए गए आदेश या विनिश्चय की प्रति समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी या व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने की तारीख से साठ दिन की अविध के भीतर की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप और ऐसी फीस के साथ होगी, जो विहित की जाए:

परंतु यदि अपील अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील न करने के पर्याप्त कारण थे तो वह साठ दिन की अवधि के पश्चात् भी कोई अपील ग्रहण कर सकेगा।

- (3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर अपील अधिकरण पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश जिसके अन्तर्गत अन्तरिम आदेश भी है, कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।
- (4) अपील प्राधिकरण, उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति, पक्षकारों और यथास्थिति, प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी को भेजेगा।
- (5) उपधारा (1) के अधीन की गई अपील का वह यथासंभवशीघ्र निपटारा करेगा और उसके द्वारा अपील प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उसका निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा:

परंतु जहां ऐसी किसी अपील का निपटारा उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है, वहां अपील अधिकरण उस अवधि के भीतर अपील का निपटारा न किए जाने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

- (6) अपील अधिकरण, प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश या विनिश्चय की वैधता या औचित्य या उसके सही होने की जांच करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या अन्यथा ऐसी अपील का निपटारा करने के लिए सुसंगत अभिलेखों को मंगा सकेगा और ऐसे आदेश कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।
- 45. अपील अधिकरण, अध्यक्ष और कम से कम दो पूर्णकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनमें से एक न्यायिक सदस्य होगा और दूसरा तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य होगा, जिनकी नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा की जाएगी।

अपील अधिकरण

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

- (i) ''न्यायिक सदस्य'' से अपील अधिकरण का ऐसा कोई सदस्य अभिप्रेत है, जो धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन उस रूप में नियुक्त किया जाए;
- (ii) ''तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य'' से अपील अधिकरण का ऐसा कोई सदस्य अभिप्रेत है, जो धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन उस रूप में नियुक्त किया जाए।
- **46**. (1) कोई व्यक्ति अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए उस दशा में पात्र होगा, जब,—
 - (क) अध्यक्ष की दशा में, वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; और
 - (ख) न्यायिक सदस्य की दशा में, उसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हुआ हो या वह भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा हो तथा उस सेवा में अपर सचिव या समतुल्य पद धारण किया हुआ हो या वह भू–संपदा के मामलों के अनुभव सहित कम से कम बीस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो; और
 - (ग) तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य की दशा में, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो शहरी विकास, आवास, भू-संपदा विकास, अवसंरचना, अर्थशास्त्र, योजना, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, प्रबंध, लोक मामले या प्रशासन के क्षेत्र में निपुण है और उस क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव रखता है या उसने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में भारत सरकार के अपर सचिव के समतुल्य पद या केन्द्रीय सरकार में कोई समतुल्य पद या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद धारण किया हुआ है।
- (2) अपील अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके नामनिर्देशिती के परामर्श से की जाएगी।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं। (3) अपील अधिकरण के न्यायिक सदस्यों और तकनीकी या प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके नामनिर्देशिती, आवासन से संबद्ध विभाग के सचिव और विधि सचिव से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिशों पर और ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। 47. (1) अपील अधिकरण का अध्यक्ष और अपील अधिकरण का कोई सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, उस रूप में पांच वर्ष से अनिधक अविध तक पद धारण करेगा किंतु वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा:

परंतु यह और कि कोई भी न्यायिक सदस्य अथवा तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(2) समुचित सरकार, किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करने के पूर्व अपना यह समाधान करेगी कि उस व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे ऐसे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते।

- 48. (1) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं और उनमें उनकी पदाविध के दौरान उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- (2) धारा 47 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य:—
 - (क) समुचित सरकार को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा;
 - (ख) धारा 49 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकेगा।
- (3) यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के पद में हुई किसी रिक्ति को, ऐसी रिक्ति होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर भरा जाएगा।

अध्यक्ष और सदस्य को कतिपय परिस्थितियों में पद से हटाया जाना।

- **49**. (1) समुचित सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, अपील अधिकरण के अध्यक्ष या किसी न्यायिक सदस्य या तकनीकी अथवा प्रशासनिक सदस्य को पद से हटा सकेगी,—
 - (क) जिसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है; या
 - (ख) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें समुचित सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्विलत है; या
 - (ग) जो शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है; या
 - (घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है: या
 - (ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया है।
- (2) अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी अथवा प्रशासिनक सदस्य को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा कराई गई ऐसी जांच के पश्चात्, जिसमें ऐसे अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी अथवा प्रशासिनक सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया हो, समुचित सरकार द्वारा किए गए आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं।

- (3) समुचित सरकार ऐसे अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी अथवा प्रशासनिक सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कोई जांच कराने का निर्देश किया गया है, तब तक के लिए पद से निलंबित कर सकेगी जब तक कि समुचित सरकार द्वारा उस निर्देश पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा कराई गई जांच की रिपोर्ट की प्राप्ति पर कोई आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है।
 - (4) समुचित सरकार, नियमों द्वारा, उपधारा (2) में निर्दिष्ट जांच की प्रक्रिया को विनियमित कर सकेगी।
- 50. (1) अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी अथवा प्रशासनिक सदस्य उस रूप में पद पर न रहने पर-

(क) उस तारीख से, जिसको वह उस पद पर नहीं रहता है, ऐसे किसी व्यक्ति या संगठन के, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य से सहयोजित रहा है, प्रबंधन या प्रशासन में या उससे संबंधित कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा:

अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी अथवा प्रशासनिक सदस्य के पद पर न रहने के पश्चात् नियो जन निर्बंधन।

परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कानूनी प्राधिकरण या किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) के अधीन यथापरिभाषित ऐसी किसी सरकारी कंपनी जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संप्रवर्तक नहीं है, के अधीन के किसी नियोजन को लागू नहीं होगी;

- (ख) किसी व्यक्ति या संगठन के लिए या उसकी ओर से ऐसी किसी विनिर्दिष्ट कार्यवाही या संव्यवहार या परक्रामण या ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिसमें प्राधिकरण एक पक्षकार है और जिसके संबंध में अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी अथवा प्रशासनिक सदस्य ने, पद पर न रहने के पूर्व, प्राधिकरण के लिए कार्य किया था या उसे सलाह दी थी, कार्य नहीं करेगा;
- (ग) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो ऐसी सूचना का, जो अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी अथवा प्रशासनिक सदस्य के रूप में उसकी हैसियत में अभिप्राप्त की गई थी, प्रयोग कर रहा है और जो जनसाधारण को उपलब्ध नहीं है अथवा जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने के योग्य नहीं है, सलाह नहीं देगाः
- (घ) ऐसी किसी इकाई के साथ, जिसके साथ उसने उस रूप में अपनी पदाविध के दौरान प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण शासकीय कार्य किए थे, सेवा-संविदा नहीं करेगा या उसके निदेशक बोर्ड में कोई नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा या उसके साथ नियोजन की किसी प्रस्थापना को स्वीकार नहीं करेगा।
- (2) अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी अथवा प्रशासनिक सदस्य किसी व्यक्ति को ऐसे किसी विषय की, जो उसके द्वारा उस रूप में कार्य करते समय उसके विचारार्थ लाया गया है या जो उसे ज्ञात था, संसूचना नहीं देगा या उसको प्रकट नहीं करेगा।
- 51. (1) समुचित सरकार अपील अधिकरण को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी जितने वह ठीक समझे।

अपील अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद।

- (2) अपील अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अपने कृत्यों का निर्वहन उसके अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन करेंगे।
- (3) अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी, जो विहित किए जाएं।
- 52. यदि अपील अधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न कारण से रिक्तियां। रिक्त होता है तो समुचित सरकार उस रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करेगी और अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उसी प्रक्रम से, जिससे रिक्ति भरी जानी है, जारी रखी जा सकेंगी।

शक्तियां।

53. (1) अपील अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा अधिकथित प्रक्रिया से आबद्धकर नहीं अधिकरण की होगा, किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा।

1908 का 5

2013 का 18

- (2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपील अधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।
- (3) अपील अधिकरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में अंतर्विष्ट साक्ष्य के नियमों द्वारा भी आबद्धकर 1872 का 1 नहीं होगा।
- (4) अपील अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वही शिक्तयां प्राप्त होंगी जो निम्निलखित विषयों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी 1908 का 5 सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थानु:—
 - (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
 - (ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;
 - (ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;
 - (घ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;
 - (ङ) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना;
 - (च) व्यतिक्रम के कारण किसी आवेदन को खारिज करना या उसे एकपक्षीय रूप से निर्दिष्ट करना; और
 - (छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।
- (5) अपील अधिकरण के समक्ष की सभी कार्यवाहियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए धारा 193, धारा 219 और धारा 228 के अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और अपील अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

1860 का 45

1974 का 2

अपील अधिकरण के अध्यक्ष की प्रशासनिक शिक्तयों। रिक्तियों आदि के कारण अपील अधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

- 54. अध्यक्ष को अपील अधिकरण के कार्य संचालन में साधारण अधीक्षण और निदेशन की शिक्तयां होंगी और वह अपील अधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त अपील अधिकरण की ऐसी प्रशासिनक शिक्तयों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएं।
 - 55. अपील अधिकरण का कोई कार्य या इसकी कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि,—
 - (क) अपील अधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या
 - (ख) अपील अधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या
 - (ग) अपील अधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।''

विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार। 56. आवेदक या अपीलार्थी, यथास्थिति, अपील अधिकरण या विनियामक प्राधिकरण या न्यायिनर्णायक अधिकारी के समक्ष अपने या इसके मामले को प्रस्तुत करने के लिए स्वयं हाजिर हो सकेगा या एक या अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्रों या कंपनी सिचवों या लागत लेखपालों या विधि व्यवसायियों या अपने किन्हीं अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) ''चार्टर्ड अकाउंटेंट'' से चार्टर्ड, अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है और जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय करने का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है;
- (ख) ''कंपनी सिचव'' से कंपनी सिचव अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में यथा परिभाषित कंपनी सिचव अभिप्रेत है और जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय करने का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है;

1949 का 38

1980 का 56

1959 का 23

- (ग) "लागत लेखापाल" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में यथा परिभाषित लागत लेखापाल अभिप्रेत है और जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय करने का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है:
- (घ) ''विधि व्यवसायी'' से कोई अधिवक्ता, वकील या किसी उच्च न्यायालय का अर्टर्नी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत व्यवसाय करने वाला प्लीडर भी है।
- **57**. (1) इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश अपील अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादनीय होगा और इस प्रयोजन के लिए अपील अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

अपील अधिकरण के आदेशों का डिक्री के रूप में निष्पादनीय होना।

- (2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण अपने द्वारा किए गए किसी आदेश को स्थानीय अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को पारेषित कर सकेगा और ऐसा सिविल न्यायालय उस आदेश को इस प्रकार निष्पादित करेगा मानो कि वह उस न्यायालय द्वारा की गई कोई डिक्री हो।
- 58. (1) अपील अधिकरण के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अपील अधिकरण के विनिश्चय या आदेश की उसे संसूचना दिए जाने की तारीख से साठ दिन की अविध के भीतर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक आधारों पर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा:

उच्च न्यायालय को अपील।

1908 का 5

परंतु यदि उस न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील करने में पर्याप्त कारणों से निवारित रहा था तो वह साठ दिन की उक्त अविध के अवसान के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—''उच्च न्यायालय''पद से ऐसे किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जहां भू–संपदा स्थित है।

(2) अपील अधिकरण द्वारा पक्षकारों की सहमति से किए गए किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

अध्याय 8

अपराध, शास्तियां और न्यायनिर्णयन

59. (1) यदि कोई संप्रवर्तक धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी किसी शास्ति के लिए जो प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित भू–संपदा परियोजना की अनुमानित लागत के दस प्रतिशत तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा 3 के अधीन रिजस्ट्रीकरण न किए जाने के लिए दंदा

- (2) यदि संप्रवर्तक उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों, विनिश्चयों या निदेशों का अनुपालन नहीं करता है या धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन जारी रखता है, तो वह कारावास से, जिसकी अविध तीन वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से, जो भू-संपदा परियोजना की अनुमानित लागत के दस प्रतिशत तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।
- 60. यदि कोई संप्रवर्तक मिथ्या सूचना देता है या धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह शास्ति के लिए, जो प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित भू-संपदा परियोजना की अनुमानित लागत के पांच प्रतिशत तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा 4 के उल्लंघन के लिए शास्ति।

61. यदि कोई संप्रवर्तक इस अधिनयम या उससे भिन्न जो धारा 3 या धारा 4 के अधीन उपबंधित है, या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसीं अन्य उपबंध का, उल्लंघन करता है तो वह ऐसी शास्ति के लिए जो प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित भू-संपदा परियोजना की अनुमानित लागत के पांच प्रतिशत तक की हो सकेगी, दायी होगा।

इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के लिए शास्ति।

62. यदि कोई भू–संपदा अभिकर्ता जानबूझकर धारा 9 या धारा 10 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, दस हजार रुपए की शास्ति के लिए, जो संचयी रूप से भू–संपदा परियोजना के, यथास्थिति, भू–खंड,

धारा 9 और धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण न किए जाने के लिए या उनके उल्लंघन के लिए शास्ति। अपार्टमेंट या भवन की जिसके लिए विक्रय या क्रय सुकर बनाया गया है, प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित लागत के पांच प्रतिशत तक की हो सकेगी, का दायी होगा।

संप्रवर्तक द्वारा प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति। संप्रवर्तक द्वारा अपील प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति।

भू–संपदा अभिकर्ता द्वारा प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने के

लिए शास्ति।

भू-संपदा अभिकर्ता द्वारा अपील प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति।

आबंटिती द्वारा अधिकरण के आदेशों

का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति। आबंटिती द्वारा अपील अधिकरण के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति।

कंपनियों द्वारा अपराध। 63. यदि कोई संप्रवर्तक, जो प्राधिकरण के किन्हीं आदेशों या निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, ऐसी शास्ति के लिए, जो संचयी रूप से, प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित भू–संपदा परियोजना की अनुमानित लागत के पांच प्रतिशत तक की हो सकेगी, दायी होगा।

- 64. यदि कोई संप्रवर्तक, जो अपील अधिकरण के किन्हीं आदेशों, विनिश्चयों या निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है, या तो वह ऐसी अविध के कारावास जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यितक्रम जारी रहता है, या जुर्माने से जो संचयी रूप से अपील अधिकरण द्वारा यथा अवधारित भू-संपदा परियोजना की अनुमानित लागत के दस प्रतिशत तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।
- 65. यदि कोई भू-संपदा अभिकर्ता, जो प्राधिकरण के किन्हीं आदेशों या निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है, या तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, ऐसी शास्ति के लिए, जो संचयी रूप से प्राधिकरण द्वारा भू-संपदा परियोजना के, यथास्थिति, भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन, जिसके लिए विक्रय या क्रय प्राधिकरण द्वारा सुकर बनाया गया है और यथा अवधारित अनुमानित लागत के पांच प्रतिशत तक की हो सकेगी, दायी होगा।
- 66. यदि कोई भू-संपदा अभिकर्ता, जो अपील अधिकरण के किन्हीं आदेशों, विनिश्चयों या निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास की अविध से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, जुर्माने से, संचयी रूप से भू-संपदा परियोजना, यथास्थिति, भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन लागत, जिसके लिए विक्रय या क्रय सुकर बनाया गया है, की अनुमानित लागत के दस प्रतिशत तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।
- 67. यदि कोई आबंटिती, जो प्राधिकरण के किन्हीं आदेशों या निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है, तो वह, उस अविध के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यितक्रम जारी रहता है, ऐसी शास्ति के लिए, जो संचयी रूप से प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित, यथास्थिति, भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन की लागत के पांच प्रतिशत तक की हो सकेगी, दायी होगा।
- 68. यदि कोई आबंटिती, जो अपील अधिकरण के किन्हीं आदेशों या निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है, तो वह, उस अविध के लिए ऐसे कारावास से जिसकी अविध एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, जुर्माने से जो संचयी रूप से, यथास्थिति, भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन की लागत के दस प्रतिशत तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।
- 69. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक या उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमित या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य, अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या अन्य व्यष्टि-संगम भी है: और

(ख) फर्म के संबंध में, ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

1974 का 2

70. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी व्यक्ति को इस अपराधों का शमन। अधिनियम की धारा के अधीन कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है, तो वह ऐसे दंड का, अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, न्यायालय द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर तथा ऐसी राशि का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, शमन किया जा सकेगा:

परंतु विहित राशि, किसी भी दशा में जुर्माने की उस अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी, जो अपराध के इस प्रकार शमन किए जाने के लिए अधिरोपित की जाए।

71. (1) प्राधिकरण, धारा 12, धारा 14 और धारा 18 और धारा 19 के अधीन प्रतिकर न्यायनिर्णीत करने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार के परामर्श से ऐसे एक या अधिक न्यायिक अधिकारी जैसा आवश्यक समझे जो जिला न्यायाधीश है या रहा है, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा, जो कि किसी संबद्ध व्यक्ति को, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात्, विहित रीति में जांच करेगा:

न्यायनिर्णयन करने की शक्ति।

1986 का 68

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका धारा 12, धारा 14, धारा 18 और धारा 19 के अधीन आने वाले मामलों की बाबत परिवाद इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पूर्व, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 9 के अधीन स्थापित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच या उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष लंबित है, यथास्थिति, उस पीठ या आयोग की अनुज्ञा से उसके समक्ष लंबित परिवाद को वापस ले सकेगा और इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर का न्यायनिर्णयन किए जाने संबंधी आवेदन पर न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा यथासंभव शीघ्रता के साथ कार्यवाही की जाएगी और उसके आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा किया जाएगा:

पंरतु जहां ऐसे किसी आवेदन का निपटारा उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है, वहां न्यायनिर्णायक अधिकारी उक्त अविध के भीतर आवेदन का निपयरा न किए जाने के अपने कारण लेखबद्ध करेगा।

- (3) न्यायनिर्णायक अधिकारी को जांच करते समय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए अथवा ऐसे किसी दस्तावेज को, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है, प्रस्तुत करने के लिए समन करने तथा हाजिर कराने की शक्ति होगी और ऐसी जांच पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उन धाराओं में से किसी भी धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह उन धाराओं में से किसी भी धारा के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, ऐसे प्रतिकर या ब्याज का संदाय करने का निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- 72. न्यायनिर्णायक अधिकारी, धारा 7 के अधीन, यथास्थिति, प्रतिकर या ब्याज की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय निम्नलिखित कारकों पर सम्यक् रूप से विचार करेगा, अर्थात्:—

न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा विचार में लिए

- (क) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप अननुपातिक लाभ या अनुचित फायदे की, जहां कहीं अनुमान्य जाने वाले कारक। हो, रकम;
 - (ख) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप हुई हानि की रकम;
 - (ग) व्यतिक्रम की आवृतिमूलक प्रकृति;
- (घ) ऐसे अन्य कारक, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी न्याय के अग्रसरण के मामले में आवश्यक समझे।

अध्याय 9

वित्त, लेखा, संपरीक्षा और रिपोर्ट

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और ऋण।

73. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात्, प्राधिकरण को ऐसी धनराशि का अनुदान और ऋण दे सकेगी जितना वह सरकार आवश्यक समझे।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान और ऋण।

74. राज्य सरकार, राज्य विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, इस निमित्त सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात्, प्राधिकरण को ऐसी धनराशि का अनुदान और ऋण दे सकेगी, जितना राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए उचित समझे।

निधि का गठन।

- 75. (1) समुचित सरकार ''भू-संपदा विनियामक निधि'' नामक एक निधि का गठन करेगी और उसमें.—
 - (क) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदानों को;
 - (ख) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त फीसों को;
 - (ग) खंड (क) से खंड (ख) में निर्दिष्ट रकमों पर प्रोद्भूत ब्याज को,

जमा किया जाएगा।

- (2) निधि का उपयोग निम्नलिखित को चुकाने के लिए किया जाएगा—
- (क) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, न्यायिनणीयक अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा प्रशासिनक व्यय, जिसके अंतर्गत प्राधिकरण और अपील अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते भी हैं;
- (ख) प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के संबंध में उसके और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अन्य व्यय।
- (3) निधि का प्रशासन प्राधिकरण के ऐसे सदस्यों की सिमिति द्वारा किया जाएगा जो कि अध्यक्ष द्वारा अवधारित की जाए।
- (4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त समिति निधि में से उस धनराशि का, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यय करेगी जिनके लिए निधि का गठन किया गया है।

शास्तियों के रूप में वसूल की गई धनराशियों का भारत की संचित निधि या राज्य के खाते में जमा किया जाना।

- **76**. (1) अपील अधिकरण या प्राधिकरण द्वारा संघ राज्यक्षेत्रों में अधिरोपित शास्तियों के रूप में वसूल की गई सभी धनराशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी।
- (2) अपील अधिकरण या प्राधिकरण द्वारा किसी राज्य में अधिरोपित शास्तियों के रूप में वसूल की गई सभी धनराशियां राज्य सरकार के ऐसे खाते में जमा की जाएंगी, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।

बजट, लेखे और संपरीक्षा।

- 77. (1) प्राधिकरण बजट तैयार करेगा, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित करे।
- (2) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।
- (3) भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति के, उस संपरीक्षा के संबंध में, वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के होते हैं और विशिष्टतय्या उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज तथा कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और प्रस्तुत करने तथा प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

- (4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्राधिकरण के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष प्राधिकरण द्वारा समुचित सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और समुचित सरकार संपरीक्षा रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष या राज्य विधान-मंडल या संघ राज्यक्षेत्र विधान-मंडल के, जहां उसके दो सदन हैं, प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी।
- 78. (1) प्राधिकरण प्रतिवर्ष एक बार ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो समुचित सरकार द्वारा विहित विषिक रिपोर्ट। किया जाए,—
 - (क) पूर्ववर्ष के प्राधिकरण के समस्त क्रियाकलापों का एक विवरण;
 - (ख) पूर्ववर्ष के वार्षिक लेखे; और
 - (ग) आगामी वर्ष का कार्यक्रम,

तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की प्रति उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष या राज्य विधान–मंडल या संघ राज्यक्षेत्र विधान–मंडल के, जहां उसके दो सदन हैं, प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां विधान–मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखी जाएगी।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

79. किसी भी सिविल न्यायालय को, ऐसे किसी विषय की बाबत, जिसका अवधारण करने के लिए प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी या अपील अधिकरण इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त है, कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी और किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शिक्त के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा।

अधिकारिता का

80. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान अधिकरण द्वारा या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा लिखित शिकायत करने के सिवाय नहीं लेगा।

अपराधों का संज्ञान।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

81. प्राधिकरण साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विहित की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियां और कृत्य (धारा 85 के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय), जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

प्रत्यायोजन ।

- 82. (1) यदि किसी समय समुचित सरकार की यह राय है कि—
- (क) प्राधिकरण के नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण, वह इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित कृत्यों का निर्वहन करने या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है; या

समुचित सरकार की प्राधिकरण को अधिक्रांत करने की शक्ति।

- (ख) प्राधिकरण ने इस अधिनियम के अधीन समुचित सरकार द्वारा दिए गए किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित कृत्यों का निर्वहन करने या कर्तव्यों के पालन करने में लगातार व्यतिक्रम किया है और ऐसे व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति या प्राधिकरण के प्रशासन को हानि पहुंची है; या
 - (ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो गया है,

तो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण को छह मास से अनिधक की ऐसी अविध के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक्रांत कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन शिक्तयों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन के लिए किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को जैसे, यथास्थिति, राष्ट्रपित या राज्यपाल निदेश दे, नियुक्त कर सकेगी:

परंतु ऐसी कोई अधिसूचना जारी किए जाने से पूर्व, समुचित सरकार, प्राधिकरण को प्रस्तावित अधिक्रमण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी और प्राधिकरण के अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी।

- (2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को अधिक्रांत किए जाने संबंधी अधिसूचना के प्रकाशन पर—
 - (क) अध्यक्ष और अन्य सदस्य अधिक्रमण की तारीख से ही उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे;
- (ख) ऐसी सभी शिक्तयों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन किया जा सकता है, प्राधिकरण का उपधारा (3) के अधीन पुनर्गठन किए जाने तक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जा सकेगा;
- (ग) प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी संपत्तियां, उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन किए जाने तक, समुचित सरकार में निहित होंगी।
- (3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अविध के अवसान पर या उसके पूर्व, समुचित सरकार प्राधिकरण का, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नए सिरे से नियुक्ति करके, पुनर्गठन करेगी और उस दशा में, ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपना पद रिक्त किया था, पुनर्नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जाएगा।
- (4) समुचित सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई करने की परिस्थितियों की एक पूरी रिपोर्ट यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष या राज्य विधान-मंडल या संघ राज्यक्षेत्र विधान-मंडल के, जहां उसके दो सदन हैं, प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी।

समुचित सरकार की प्राधिकरण को निदेश देने और रिपोर्ट तथा विवरणियां अभिप्राप्त करने की शक्तियां।

83. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के पालन में नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्धकर होगा, जो समुचित सरकार समय-समय पर लिखित में उसे दे:

परंतु प्राधिकरण को जहां तक साध्य हो इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पहले अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

- (2) यदि समुचित सरकार और प्राधिकरण के मध्य इस बात का कोई विवाद उद्भूत होता है कि वह प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं तो समुचित सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।
- (3) प्राधिकरण समुचित सरकार को अपने क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी विवरणियां या अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जिसकी समुचित सरकार, समय-समय पर अपेक्षा करे।

नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति।

- 84. (1) समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम के प्रारंभ के छह मास की अवधि के भीतर, अधिसूचना द्वारा, नियम बनाएगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शिक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्निलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध किया जा सकेगा अर्थात्:—
 - (क) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को आवेदन करने के लिए सूचना और दस्तावेज;

- (ख) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे आवेदन करने का प्ररूप और रीति तथा ऐसे आवेदन के साथ संलग्न की जाने वाली फीस और दस्तावेज;
- (ग) वह अवधि, रीति और वे शर्तें जिनके अधीन धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया जाना है;
- (घ) धारा 9 की उपधारा (6) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की अविध की वैधता और नवीकरण की रीति और फीस:
- (ङ) धारा 10 के खंड (ख) के अधीन लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का बनाए रखा जाना और उनका परिरक्षण;
 - (च) धारा 10 के खंड (ङ) के अधीन भू-संपदा अभिकर्ता द्वारा अन्य कृत्यों का निर्वहन;
 - (छ) धारा 12 के अधीन संदेय ब्याज की दर;
 - (ज) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन विक्रय के लिए करार का प्ररूप और विशिष्टियां;
 - (झ) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन संदेय ब्याज की दर;
 - (अ) धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन संदेय ब्याज की दर;
 - (ट) धारा 19 की उपधारा (7) के अधीन संदेय ब्याज की दर;
 - (ठ) धारा 22 के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की रीति;
- (ड) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तै:
 - (ढ) धारा 25 के अधीन अध्यक्ष की प्रशासनिक शक्तियां;
- (ण) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें।
- (त) धारा 34 के खंड (ख) के अधीन और खंड (घ) के अधीन वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने वाले ब्यौरे:
- (थ) ऐसे अन्य अतिरिक्त कृत्य जिनका धारा 35 की उपधारा (2)के खंड (iv) के अधीन प्राधिकरण द्वारा पालन किया जा सकेगा;
- (द) धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा ब्याज, शास्ति और प्रतिकर की वसूली की रीति:
- (ध) धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी, प्राधिकरण या अपील अधिकरण के आदेश, निदेश या विनिश्चय का क्रियान्वयन करने की रीति;
 - (न) धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सलाहकार परिषद् से प्राप्त सिफारिशें;
- (प) धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन अपील फाइल किए जाने का प्ररूप और रीति तथा फीस;
 - (फ) धारा 46 की उपधारा (3) के अधीन अधिकरण के सदस्यों के चयन की रीति ;
- (ब) धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;
- (भ) धारा 49 की उपधारा (4) के अधीन अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए प्रक्रिया:

- (म) धारा 51 की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;
 - (य) धारा 53 की उपधारा (4) के खंड (ज) के अधीन अधिकरण की कोई अन्य शक्तियां;
 - (यक) धारा 54 के अधीन अपील अधिकरण के अध्यक्ष की शिक्तयां;
 - (यख) धारा 70 के अधीन अपराधों के शमन के लिए निबंधन और शर्तें तथा ऐसी राशि का संदाय;
 - (यग) धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन जांच की रीति;
- (यघ) धारा 77 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाने वाला वह प्ररूप जिसमें प्राधिकरण बजट तैयार करेगा, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा;
- (यङ) धारा 78 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप और समय जिसमें प्राधिकरण वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा;
- (यच) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

विनियम बनाने की शक्ति।

- **85**. (1) प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम समुचित सरकार द्वारा उनका अनुमोदन किए जाने के पश्चात् अपनी स्थापना के तीन मास की अविध के भीतर, अधिसूचना द्वारा बनाएगा।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—
 - (क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने का प्ररूप और रीति तथा उसके साथ संदेय फीस:
 - (ख) धारा 6 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का प्ररूप और विस्तार के लिए फीस;
 - (ग) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन अपेक्षित ऐसी अन्य जानकारी और दस्तावेज;
 - (घ) धारा 11 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन प्रदर्शन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्वीकृत रेखांक, विनिर्देशों सहित, अभिन्यास रेखांकों का प्रदर्शन;
 - (ङ) धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन अन्य ब्यौरे तैयार करना और उनका अनुरक्षण;
 - (च) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के अधिवेशनों का समय, स्थान और कार्य-संचालन के संबंध में प्रक्रिया;
 - (छ) धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए प्ररूप, रीति और फीस;
 - (ज) धारा 34 के खंड (ङ) के अधीन संप्रवर्तक पर आबंटितियों या भू-संपदा अभिकर्ता पर उद्गृहीत की जाने वाली मानक फीस;
 - (झ) कोई अन्य विषय जिसे विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या जो विनिर्दिष्ट किया जाए या जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना होगा।

नियमों का रखा जाना। 86. (1) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र और विधान-मंडल रहित संघ राज्यक्षेत्र के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना उसके बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अविध के लिए रखा जाएगा/रखी जाएगी। यह अविध एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के

ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए या वह अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा/जाएगी किन्तु, यथास्थिति, उस नियम या विनियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- (2) इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, यथास्थिति, राज्य सरकार या पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र सरकार के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम और यथास्थिति, राज्य सरकार या पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना उसके बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।
- 87. प्राधिकरण, अपील अधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य अधिकारी और कर्मचारी और न्यायनिर्णायक अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

सदस्यों आदि का लोक सेवक होना।

88. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।

अन्य विधियों का लागू होना, वर्जित न होना।

89. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

90. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशियत किसी बात के लिए समुचित सरकार या प्राधिकरण या समुचित सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

91. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन नहीं किया जाएगा।

- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।
 - 92. महाराष्ट्र आवासन (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2012 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन।

2014 का महाराष्ट्र अधिनियम संख्यांक 2

1860 का 45

विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 22)

[6 मई, 2016]

विनियोग अधिनियमों [विनियोग (रेल) अधिनियमों सहित] का निरसन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2016 है।

संक्षिप्त नाम।

2. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को इसके द्वारा उसके चौथे स्तंभ में वर्णित सीमा तक निरसित किया जाता है।

विनियोग अधिनियमों [विनियोग (रेल) अधिनियमों सहित] का निरसन।

3. किसी अधिनियमिति का इस अधिनियम द्वारा निरसन किया जाना, किसी अन्य ऐसी अधिनियमिति को व्यावृत्ति। प्रभावित नहीं करेगा जिसमें ऐसे निरसित की गई अधिनियमिति को लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया है;

और इस अधिनियम का प्रभाव पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसके विषय में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग से कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले से अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर नहीं पड़ेगा;

और इस अधिनियम का प्रभाव विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धित या प्रक्रिया या विद्यमान विशेषाधिकार, निर्वंधन, छूट पद या नियुक्ति पर नहीं पड़ेगा, भले ही वह, यथास्थिति, इस अधिनियम द्वारा निरिसत किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे किसी भी रीति से पुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न क्यों न हो;

और इस अधिनियम द्वारा, किसी अधिनियमिति निरसन से, ऐसी कोई अधिकारिता, पद, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्वंधन, छूट, पद्धति, प्रक्रिया या कोई अन्य विषय या बात, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनरुज्जीवित या प्रत्यावर्तित नहीं होगी;

और इस अधिनियम द्वारा अधिनियमितियों के निरसन से, किसी प्राधिकारी द्वारा उसके संबंध में की गई या की जाने वाली लेखापरीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अन्वेषण, जांच या किसी अन्य कार्रवाई पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसी लेखापरीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अन्वेषण, जांच या कार्रवाई उसी प्रकार की जा सकेगी और या चालू रखी जा सकेगी मानो उक्त अधिनियमितियां इस अधिनियम द्वारा निरसित नहीं की गई हैं।

अनुसूची (धारा 2 **देखिए**)

 वर्ष	संख्यांक	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
1	2	3	4
1950	23	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1950	संपूर्ण
1950	24	विनियोग अधिनियम, 1950	संपूर्ण
1950	39	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1950	संपूर्ण
1950	60	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1950	संपूर्ण
1950	77	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1950	संपूर्ण
1950	79	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1950	संपूर्ण
1951	6	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1951	संपूर्ण
1951	7	विनियोग अधिनियम, 1951	संपूर्ण
1951	8	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1951	संपूर्ण
1951	12	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1951	संपूर्ण
1951	14	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1951	संपूर्ण
1951	15	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1951	संपूर्ण
1951	57	पंजाब विनियोग अधिनियम, 1951	संपूर्ण
1951	58	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1951	संपूर्ण
1951	60	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1951	संपूर्ण
1952	13	विनियोग अधिनियम, 1952	संपूर्ण
1952	14	पंजाब विनियोग अधिनियम, 1952	संपूर्ण
1952	15	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1952	संपूर्ण
1952	21	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 1952	संपूर्ण
1952	28	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1952	संपूर्ण
1952	43	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1952	संपूर्ण
1952	44	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1952	संपूर्ण
1952	80	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1952	संपूर्ण
1953	1	विनियोग अधिनियम, 1953	संपूर्ण

1	2	3	4
1953	4	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1953	संपूर्ण
1953	5	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1953	संपूर्ण
1953	6	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1953	संपूर्ण
1953	7	पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ विनियोग अधिनियम, 1953	संपूर्ण
1953	8	पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1953	संपूर्ण
1953	9	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1953	संपूर्ण
1953	13	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1953	संपूर्ण
1953	17	पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1953	संपूर्ण
1953	33	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1953	संपूर्ण
1953	50	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1953	संपूर्ण
1953	51	पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम 1953	संपूर्ण
1954	5	विनियोग अधिनियम, 1954	संपूर्ण
1954	6	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1954	संपूर्ण
1954	8	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1954	संपूर्ण
1954	11	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1954	संपूर्ण
1954	16	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1954	संपूर्ण
1954	40	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1954	संपूर्ण
1954	47	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1954	संपूर्ण
1954	56	आन्ध्र विनियोग अधिनियम, 1954	संपूर्ण
1955	3	आन्ध्र विनियोग अधिनियम, 1955	संपूर्ण
1955	4	आन्ध्र विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1955	संपूर्ण
1955	5	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1955	संपूर्ण
1955	6	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1955	संपूर्ण
1955	7	विनियोग अधिनियम, 1955	संपूर्ण
1955	8	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1955	संपूर्ण
1955	14	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1955	संपूर्ण
1955	38	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम 1955	संपूर्ण
1955	46	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1955	संपूर्ण
1955	47	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1955	संपूर्ण
1956	5	विनियोग अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1956	11	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1956	12	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1956	13	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1956	14	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1956	15	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1956	संपूर्ण

1	2	3	4
1956	16	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1956	19	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1956	20	त्रावणकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1956	23	त्रावणकोर-कोचीन विनियोग अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1956	43	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1956	44	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1956	46	त्रावणकोर-कोचीन विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1956	83	विनियोग (रेल) संख्यांक 6 अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1956	84	विनियोग (रेल) संख्यांक 7 अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1956	85	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1957	1	विनियोग अधिनियम, 1957	संपूर्ण
1957	2	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1957	संपूर्ण
1957	3	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1957	संपूर्ण
1957	4	केरल विनियोग अधिनियम, 1957	संपूर्ण
1957	6	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1957	संपूर्ण
1957	8	केरल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1957	संपूर्ण
1957	9	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 1957	संपूर्ण
1957	15	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1957	संपूर्ण
1957	22	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1957	संपूर्ण
1957	24	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1957	संपूर्ण
1957	56	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1957	संपूर्ण
1958	4	विनियोग अधिनियम, 1958	संपूर्ण
1958	6	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1958	संपूर्ण
1958	8	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1958	संपूर्ण
1958	10	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1958	संपूर्ण
1958	12	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1958	संपूर्ण
1958	14	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1958	संपूर्ण
1958	23	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1958	संपूर्ण
1958	40	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1958	संपूर्ण
1958	49	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1958	संपूर्ण
1958	50	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम, 1958	संपूर्ण
1958	51	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1958	संपूर्ण
1959	2	विनियोग अधिनियम, 1959	संपूर्ण
1959	5	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1959	संपूर्ण
1959	6	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1959	संपूर्ण

1	2	3	4
1959	7	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1959	संपूर्ण
1959	11	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1959	संपूर्ण
1959	18	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1959	संपूर्ण
1959	19	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1959	संपूर्ण
1959	34	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1959	संपूर्ण
1959	35	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1959	संपूर्ण
1959	36	विनियोग (संख्यांक 6) अधिनियम, 1959	संपूर्ण
1959	39	केरल विनियोग अधिनियम, 1959	संपूर्ण
1959	40	विनियोग (संख्यांक 7) अधिनियम, 1959	संपूर्ण
1959	53	केरल विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1959	संपूर्ण
1959	55	विनियोग (संख्यांक 8) अधिनियम, 1959	संपूर्ण
1960	3	विनियोग अधिनियम, 1960	संपूर्ण
1960	7	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1960	संपूर्ण
1960	8	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1960	संपूर्ण
1960	9	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1960	संपूर्ण
1960	12	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1960	संपूर्ण
1960	15	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1960	संपूर्ण
1960	29	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1960	संपूर्ण
1960	30	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1960	संपूर्ण
1960	36	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1960	संपूर्ण
1960	49	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम, 1960	संपूर्ण
1960	50	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1960	संपूर्ण
1961	2	विनियोग अधिनियम, 1961	संपूर्ण
1961	3	उड़ीसा विनियोग अधिनियम, 1961	संपूर्ण
1961	5	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1961	संपूर्ण
1961	6	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1961	संपूर्ण
1961	9	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1961	संपूर्ण
1961	10	उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1961	संपूर्ण
1961	12	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1961	संपूर्ण
1961	18	उड़ीसा विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1961	संपूर्ण
1961	20	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1961	संपूर्ण
1961	22	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1961	संपूर्ण
1961	37	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1961	संपूर्ण
1961	54	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1961	संपूर्ण
1961	57	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1961	संपूर्ण

1	2	3	4
1962	2	विनियोग अधिनियम, 1962	संपूर्ण
1962	4	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1962	संपूर्ण
1962	5	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1962	संपूर्ण
1962	12	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 1962	संपूर्ण
1962	18	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1962	संपूर्ण
1962	19	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1962	संपूर्ण
1962	22	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1962	संपूर्ण
1962	23	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1962	संपूर्ण
1962	28	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1962	संपूर्ण
1962	29	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1962	संपूर्ण
1962	40	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम, 1962	संपूर्ण
1962	41	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1962	संपूर्ण
1963	5	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1963	संपूर्ण
1963	6	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1963	संपूर्ण
1963	7	विनियोग अधिनियम, 1963	संपूर्ण
1963	9	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1963	संपूर्ण
1963	12	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1963	संपूर्ण
1963	16	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, 1963	संपूर्ण
1963	17	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1963	संपूर्ण
1963	18	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1963	संपूर्ण
1963	25	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1963	संपूर्ण
1963	31	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम, 1963	संपूर्ण
1963	44	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1963	संपूर्ण
1963	46	विनियोग (रेल) संख्यांक 6 अधिनियम, 1963	संपूर्ण
1964	1	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1964	संपूर्ण
1964	2	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1964	संपूर्ण
1964	3	विनियोग अधिनियम, 1964	संपूर्ण
1964	4	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1964	संपूर्ण
1964	6	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1964	संपूर्ण
1964	8	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1964	संपूर्ण
1964	22	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1964	संपूर्ण
1964	29	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1964	संपूर्ण
1964	39	विनियोग (संख्यांक 6) अधिनियम, 1964	संपूर्ण
1964	42	केरल विनियोग अधिनियम, 1964	संपूर्ण
1964	50	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, 1964	संपूर्ण
1965	2	विनियोग अधिनियम, 1965	संपूर्ण

1	2	3	4
1965	3	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1965	संपूर्ण
1965	4	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1965	संपूर्ण
1965	5	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1965	संपूर्ण
1965	7	केरल विनियोग अधिनियम, 1965	संपूर्ण
1965	8	केरल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1965	संपूर्ण
1965	11	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1965	संपूर्ण
1965	13	केरल विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1965	संपूर्ण
1965	24	केरल विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1965	संपूर्ण
1965	25	केरल विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1965	संपूर्ण
1965	26	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1965	संपूर्ण
1965	27	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1965	संपूर्ण
1965	28	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, १९६५	संपूर्ण
1965	29	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1965	संपूर्ण
1965	37	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1965	संपूर्ण
1965	43	केरल विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1965	संपूर्ण
1966	5	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1966	संपूर्ण
1966	6	विनियोग अधिनियम, 1966	संपूर्ण
1966	7	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1966	संपूर्ण
1966	8	विनियोग (रेल)संख्यांक २ अधिनियम, 1966	संपूर्ण
1966	10	केरल विनियोग अधिनियम, 1966	संपूर्ण
1966	11	केरल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1966	संपूर्ण
1966	12	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1966	संपूर्ण
1966	14	केरल विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1966	संपूर्ण
1966	27	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1966	संपूर्ण
1966	39	केरल विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1966	संपूर्ण
1966	40	केरल विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1966	संपूर्ण
1966	41	केरल विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1966	संपूर्ण
1966	42	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1966	संपूर्ण
1966	43	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1966	संपूर्ण
1966	45	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1966	संपूर्ण
1966	46	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1966	संपूर्ण
1967	1	विनियोग अधिनियम, 1967	संपूर्ण
1967	2	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1967	संपूर्ण
1967	3	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1967	संपूर्ण

1	2	3	4
1967	4	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 1967	संपूर्ण
1967	5	गोवा, दमन और दीव विनियोग अधिनियम, 1967	संपूर्ण
1967	6	गोवा, दमन और दीव विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1967	संपूर्ण
1967	7	राजस्थान विनियोग अधिनियम, 1967	संपूर्ण
1967	8	राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1967	संपूर्ण
1967	18	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1967	संपूर्ण
1967	19	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1967	संपूर्ण
1967	23	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1967	संपूर्ण
1967	32	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1967	संपूर्ण
1967	33	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1967	संपूर्ण
1967	34	मणिपुर विनियोग अधिनियम, 1967	संपूर्ण
1967	35	हरियाणा विनियोग अधिनियम, 1967	संपूर्ण
1968	4	विनियोग अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	5	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	8	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	9	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	11	हरियाणा विनियोग अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	12	हरियाणा विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	13	पश्चिमी बंगाल विनियोग अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	14	पश्चिमी बंगाल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	15	उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	16	उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	18	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	20	उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	21	पश्चिमी बंगाल विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	37	विनियोग (रेल)संख्यांक 3 अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	38	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	40	बिहार विनियोग अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	41	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	42	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	43	उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	54	विनियोग (रेल)संख्यांक 5 अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	55	विनियोग (रेल) संख्यांक 6 अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	64	पंजाब विनियोग अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	65	पांडिचेरी विनियोग अधिनियम, 1968	संपूर्ण

1	2	3	4
1968	66	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1968	67	बिहार विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1969	2	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1969	संपूर्ण
1969	4	विनियोग अधिनियम, 1969	संपूर्ण
1969	5	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1969	संपूर्ण
1969	6	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1969	संपूर्ण
1969	7	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1969	संपूर्ण
1969	13	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1969	संपूर्ण
1969	29	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1969	संपूर्ण
1969	30	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1969	संपूर्ण
1969	31	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1969	संपूर्ण
1969	48	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम, 1969	संपूर्ण
1969	49	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1969	संपूर्ण
1969	50	विनियोग (संख्यांक 6) अधिनियम, 1969	संपूर्ण
1969	51	मणिपुर विनियोग अधिनियम, 1969	संपूर्ण
1969	52	बिहार विनियोग अधिनियम, 1969	संपूर्ण
1970	4	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1970	संपूर्ण
1970	7	विनियोग अधिनियम, 1970	संपूर्ण
1970	8	मणिपुर विनियोग अधिनियम, 1970	संपूर्ण
1970	9	मणिपुर विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1970	संपूर्ण
1970	10	पश्चिमी बंगाल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1970	संपूर्ण
1970	11	पश्चिमी बंगाल विनियोग अधिनियम, 1970	संपूर्ण
1970	12	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1970	संपूर्ण
1970	13	विनियोग (रेल) संख्यांक २ अधिनियम, 1970	संपूर्ण
1970	18	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1970	संपूर्ण
1970	32	पश्चिमी बंगाल विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1970	संपूर्ण
1970	36	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1970	संपूर्ण
1970	38	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1970	संपूर्ण
1970	44	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1970	संपूर्ण
1970	45	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1970	संपूर्ण
1970	46	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1970	संपूर्ण
1970	47	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम, 1970	संपूर्ण
1971	1	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	2	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	3	मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1971	संपूर्ण

1	2	3	4
1971	4	मणिपुर विनियोग अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	5	विनियोग अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	6	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	8	उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	9	उड़ीसा विनियोग अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	10	मैसूर विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	11	मैसूर विनियोग अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	12	पश्चिमी बंगाल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	13	पश्चिमी बंगाल विनियोग अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	18	मणिपुर विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	19	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	25	पंजाब विनियोग अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	27	मैसूर विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	28	पश्चिमी बंगाल विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	29	गुजरात विनियोग अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	30	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	38	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	58	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	60	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	61	पंजाब विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1972	1	विनियोग अधिनियम, 1972	संपूर्ण
1972	2	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1972	संपूर्ण
1972	3	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1972	संपूर्ण
1972	4	विनियोग (रेल) संख्यांक २ अधिनियम, 1972	संपूर्ण
1972	5	विनियोग (रेल) (लेखानुदान) अधिनियम, 1972	संपूर्ण
1972	6	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1972	संपूर्ण
1972	14	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1972	संपूर्ण
1972	17	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, 1972	संपूर्ण
1972	51	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1972	संपूर्ण
1972	63	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1972	संपूर्ण
1972	64	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम, 1972	संपूर्ण
1972	65	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1972	संपूर्ण
1972	66	विनियोग (संख्यांक 6) अधिनियम, 1972	संपूर्ण
1973	4	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	5	विनियोग अधिनियम, 1973	संपूर्ण

1	2	3	4
1973	6	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	7	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	9	आंध्र प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	10	आंध्र प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	11	उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	12	उड़ीसा विनियोग अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	16	मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	19	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	28	मणिपुर विनियोग अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	29	आंध्र प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	30	उड़ीसा विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	35	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	38	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	42	उड़ीसा विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	43	मणिपुर विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	61	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	63	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	64	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	65	उड़ीसा विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1974	7	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1974	संपूर्ण
1974	10	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1974	संपूर्ण
1974	13	गुजरात विनियोग अधिनियम, 1974	संपूर्ण
1974	14	गुजरात विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1974	संपूर्ण
1974	15	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1974	संपूर्ण
1974	16	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, १९७४	संपूर्ण
1974	17	विनियोग अधिनियम, 1974	संपूर्ण
1974	18	पांडिचेरी विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1974	संपूर्ण
1974	19	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1974	संपूर्ण
1974	24	गुजरात विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1974	संपूर्ण
1974	25	पांडिचेरी विनियोग अधिनियम, 1974	संपूर्ण
1974	43	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1974	संपूर्ण
1974	44	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1974	संपूर्ण
1974	61	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1974	संपूर्ण
1974	62	गुजरात विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1974	संपूर्ण
1974	63	गुजरात विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1974	संपूर्ण

1	2	3	4
1974	64	पांडिचेरी विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1974	संपूर्ण
1975	5	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1975	संपूर्ण
1975	6	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1975	संपूर्ण
1975	7	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1975	संपूर्ण
1975	8	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, १९७५	संपूर्ण
1975	9	पांडिचेरी विनियोग अधिनियम, 1975	संपूर्ण
1975	10	पांडिचेरी विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1975	संपूर्ण
1975	11	विनियोग अधिनियम, 1975	संपूर्ण
1975	14	गुजरात विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1975	संपूर्ण
1975	15	गुजरात विनियोग अधिनियम, 1975	संपूर्ण
1975	17	नागालैंड विनियोग अधिनियम, 1975	संपूर्ण
1975	18	नागालैंड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1975	संपूर्ण
1975	21	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1975	संपूर्ण
1975	27	नागालैंड विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1975	संपूर्ण
1975	30	पांडिचेरी विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1975	संपूर्ण
1975	36	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1975	संपूर्ण
1975	37	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1975	संपूर्ण
1976	5	विनियोग अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	6	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	7	विनियोग (रेल) संख्यांक २ अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	16	नागालैंड विनियोग अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	17	पांडिचेरी विनियोग अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	38	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	39	पांडिचेरी विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	40	नागालैंड विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	43	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	47	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	48	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	50	तमिलनाडु विनियोग अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	51	तमिलनाडु विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	52	गुजरात विनियोग अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	64	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	83	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	84	तमिलनाडु विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	85	पांडिचेरी विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1976	संपूर्ण

1	2	3	4
1976	95	विनियोग (संख्यांक 6) अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	110	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	111	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	112	विनियोग (संख्यांक 7) अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	113	गुजरात विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	114	पांडिचेरी विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1977	1	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1977	संपूर्ण
1977	2	विनियोग अधिनियम, 1977	संपूर्ण
1977	3	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 1977	संपूर्ण
1977	4	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1977	संपूर्ण
1977	18	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1977	संपूर्ण
1977	22	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1977	संपूर्ण
1977	28	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1977	संपूर्ण
1977	45	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1977	संपूर्ण
1978	3	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1978	संपूर्ण
1978	4	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1978	संपूर्ण
1978	5	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1978	संपूर्ण
1978	6	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1978	संपूर्ण
1978	7	विनियोग अधिनियम, 1978	संपूर्ण
1978	8	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1978	संपूर्ण
1978	18	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1978	संपूर्ण
1978	35	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1978	संपूर्ण
1979	1	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1978	संपूर्ण
1979	2	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम, 1978	संपूर्ण
1979	3	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1979	संपूर्ण
1979	7	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1979	संपूर्ण
1979	8	विनियोग अधिनियम, 1979	संपूर्ण
1979	9	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1979	संपूर्ण
1979	10	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1979	संपूर्ण
1979	11	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1979	संपूर्ण
1979	19	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1979	संपूर्ण
1980	2	विनियोग अधिनियम, 1980	संपूर्ण
1980	3	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1980	संपूर्ण
1980	9	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 1980	संपूर्ण
1980	10	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1980	संपूर्ण

1	2	3	4
1980	11	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1980	संपूर्ण
1980	12	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1980	संपूर्ण
1980	39	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1980	संपूर्ण
1980	43	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1980	संपूर्ण
1980	71	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1980	संपूर्ण
1981	2	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1981	संपूर्ण
1981	3	विनियोग अधिनियम, 1981	संपूर्ण
1981	4	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1981	संपूर्ण
1981	5	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1981	संपूर्ण
1981	8	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1981	संपूर्ण
1981	9	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1981	संपूर्ण
1981	10	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1981	संपूर्ण
1981	11	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1981	संपूर्ण
1981	15	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1981	संपूर्ण
1981	34	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम, 1981	संपूर्ण
1981	37	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1981	संपूर्ण
1981	54	विनियोग (रेल) संख्यांक 6 अधिनियम, 1981	संपूर्ण
1981	55	विनियोग (रेल) संख्यांक ७ अधिनियम, १९८१	संपूर्ण
1981	56	विनियोग (संख्यांक 6) अधिनियम, 1981	संपूर्ण
1981	57	विनियोग (संख्यांक 7) अधिनियम, 1981	संपूर्ण
1982	5	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1982	संपूर्ण
1982	6	विनियोग अधिनियम, 1982	संपूर्ण
1982	7	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1982	संपूर्ण
1982	8	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1982	संपूर्ण
1982	19	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1982	संपूर्ण
1982	32	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1982	संपूर्ण
1982	33	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1982	संपूर्ण
1982	60	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1982	संपूर्ण
1983	2	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1983	संपूर्ण
1983	3	विनियोग अधिनियम, 1983	संपूर्ण
1983	4	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1983	संपूर्ण
1983	5	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1983	संपूर्ण
1983	6	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1983	संपूर्ण
1983	7	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, १९८३	संपूर्ण
1983	10	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1983	संपूर्ण

1	2	3	4
1983	19	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1983	संपूर्ण
983	21	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1983	संपूर्ण
983	36	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1983	संपूर्ण
983	37	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम, 1983	संपूर्ण
984	6	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1984	संपूर्ण
984	7	विनियोग अधिनियम, 1984	संपूर्ण
984	8	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1984	संपूर्ण
984	9	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1984	संपूर्ण
984	10	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1984	संपूर्ण
984	11	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1984	संपूर्ण
984	18	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1984	संपूर्ण
984	50	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1984	संपूर्ण
985	4	विनियोग अधिनियम, 1985	संपूर्ण
985	5	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1985	संपूर्ण
985	6	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1985	संपूर्ण
985	7	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1985	संपूर्ण
985	14	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1985	संपूर्ण
985	15	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1985	संपूर्ण
985	16	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1985	संपूर्ण
985	17	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1985	संपूर्ण
985	29	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1985	संपूर्ण
985	42	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1985	संपूर्ण
985	68	विनियोग (संख्यांक 6) अधिनियम, 1985	संपूर्ण
985	71	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम, 1985	संपूर्ण
986	12	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1986	संपूर्ण
986	13	विनियोग अधिनियम, 1986	संपूर्ण
986	15	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1986	संपूर्ण
986	16	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1986	संपूर्ण
986	17	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1986	संपूर्ण
986	18	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1986	संपूर्ण
986	21	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1986	संपूर्ण
986	39	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1986	संपूर्ण
986	52	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1986	संपूर्ण
986	55	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1986	संपूर्ण
987	1	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1987	संपूर्ण

1	2	3	4
1987	2	विनियोग अधिनियम, 1987	संपूर्ण
1987	3	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1987	संपूर्ण
1987	5	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1987	संपूर्ण
1987	6	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1987	संपूर्ण
1987	7	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, 1987	संपूर्ण
1987	9	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1987	संपूर्ण
1987	33	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1987	संपूर्ण
1987	45	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1987	संपूर्ण
1988	6	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1988	संपूर्ण
1988	7	विनियोग अधिनियम, 1988	संपूर्ण
1988	15	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1988	संपूर्ण
1988	16	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1988	संपूर्ण
1988	17	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, 1988	संपूर्ण
1988	25	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1988	संपूर्ण
1988	28	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1988	संपूर्ण
1988	47	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1988	संपूर्ण
1988	48	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1988	संपूर्ण
1988	70	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1988	संपूर्ण
1989	4	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1989	संपूर्ण
1989	5	विनियोग अधिनियम, 1989	संपूर्ण
1989	6	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1989	संपूर्ण
1989	7	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1989	संपूर्ण
1989	12	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1989	संपूर्ण
1989	14	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, 1989	संपूर्ण
1989	19	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1989	संपूर्ण
1989	27	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1989	संपूर्ण
1989	34	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1989	संपूर्ण
1990	1	विनियोग (संख्यांक 6) अधिनियम, 1989	संपूर्ण
1990	5	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1990	संपूर्ण
1990	6	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1990	संपूर्ण
1990	7	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1990	संपूर्ण
1990	8	विनियोग अधिनियम, 1990	संपूर्ण
1990	11	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1990	संपूर्ण
1990	22	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1990	संपूर्ण
1990	24	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1990	संपूर्ण

1	2	3	4
1991	3	विनियोग अधिनियम, 1991	संपूर्ण
1991	12	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 1991	संपूर्ण
1991	13	विनियोग (रेल)अधिनियम, 1991	संपूर्ण
1991	14	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1991	संपूर्ण
1991	15	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1991	संपूर्ण
1991	16	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1991	संपूर्ण
1991	17	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1991	संपूर्ण
1991	29	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, 1991	संपूर्ण
1991	30	विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 अधिनियम, 1991	संपूर्ण
1991	37	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1991	संपूर्ण
1991	61	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1991	संपूर्ण
1992	3	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1992	संपूर्ण
1992	4	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1992	संपूर्ण
1992	5	विनियोग अधिनियम, 1992	संपूर्ण
1992	6	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1992	संपूर्ण
1992	17	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1992	संपूर्ण
1992	29	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, 1992	संपूर्ण
1992	30	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1992	संपूर्ण
1992	32	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1992	संपूर्ण
1992	33	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1992	संपूर्ण
1993	2	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1993	संपूर्ण
1993	6	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1993	संपूर्ण
1993	7	विनियोग अधिनियम, 1993	संपूर्ण
1993	21	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1993	संपूर्ण
1993	22	विनियोग (रेल) संख्यांक २ अधिनियम, 1993	संपूर्ण
1993	39	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1993	संपूर्ण
1993	60	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1993	संपूर्ण
1993	61	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1993	संपूर्ण
1993	62	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, 1993	संपूर्ण
1993	63	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1993	संपूर्ण
1994	5	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1994	संपूर्ण
1994	14	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 1994	संपूर्ण
1994	15	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1994	संपूर्ण
1994	21	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1994	संपूर्ण
1994	22	विनियोग अधिनियम, 1994	संपूर्ण

1	2	3	4
1994	29	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1994	संपूर्ण
1994	30	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1994	संपूर्ण
1994	31	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1994	संपूर्ण
1994	48	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1994	संपूर्ण
1994	49	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1994	संपूर्ण
1994	50	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1994	संपूर्ण
1994	52	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1994	संपूर्ण
1994	53	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम, 1994	संपूर्ण
1995	2	विनियोग (संख्यांक 6) अधिनियम, 1994	संपूर्ण
1995	3	विनियोग (रेल) संख्यांक 6 अधिनियम, 1994	संपूर्ण
1995	10	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 1995	संपूर्ण
1995	11	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1995	संपूर्ण
1995	12	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1995	संपूर्ण
1995	13	विनियोग अधिनियम, 1995	संपूर्ण
1995	20	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1995	संपूर्ण
1995	21	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, 1995	संपूर्ण
1995	23	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1995	संपूर्ण
1995	36	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1995	संपूर्ण
1995	37	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1995	संपूर्ण
1996	3	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1995	संपूर्ण
1996	4	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1995	संपूर्ण
1996	6	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 1996	संपूर्ण
1996	7	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1996	संपूर्ण
1996	8	विनियोग (रेल) संख्यांक २ अधिनियम, 1996	संपूर्ण
1996	9	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1996	संपूर्ण
1996	10	विनियोग अधिनियम, 1996	संपूर्ण
1996	17	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996	संपूर्ण
1996	18	विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 अधिनियम, 1996	संपूर्ण
1996	19	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1996	संपूर्ण
1996	31	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1996	संपूर्ण
1996	37	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1996	संपूर्ण
1996	39	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1996	संपूर्ण
1997	9	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 1997	संपूर्ण
1997	10	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1997	संपूर्ण
1997	11	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1997	संपूर्ण

1	2	3	4
1997	19	विनियोग अधिनियम, 1997	संपूर्ण
1997	20	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1997	संपूर्ण
1997	21	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1997	संपूर्ण
1997	25	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1997	संपूर्ण
1997	27	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1997	संपूर्ण
1997	33	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1997	संपूर्ण
1997	34	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1997	संपूर्ण
1998	2	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 1998	संपूर्ण
1998	3	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1998	संपूर्ण
1998	5	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1998	संपूर्ण
1998	6	विनियोग अधिनियम, 1998	संपूर्ण
1998	8	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1998	संपूर्ण
1998	15	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998	संपूर्ण
1998	19	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1998	संपूर्ण
1998	20	विनियोग (संख्यांक 3) लेखानुदान अधिनियम, 1998	संपूर्ण
999	9	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1998	संपूर्ण
999	10	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1998	संपूर्ण
999	18	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 1999	संपूर्ण
999	19	विनियोग (रेल) अधिनियम, 1999	संपूर्ण
999	20	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 1999	संपूर्ण
1999	22	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1999	संपूर्ण
999	23	विनियोग अधिनियम, 1999	संपूर्ण
999	24	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1999	संपूर्ण
999	25	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, 1999	संपूर्ण
999	26	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1999	संपूर्ण
999	37	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1999	संपूर्ण
999	43	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 1999	संपूर्ण
2000	3	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	4	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	5	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	6	विनियोग अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	9	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	11	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	40	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	41	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2000	संपूर्ण

1	2	3	4
2000	42	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	43	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, २०००	संपूर्ण
2001	2	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2001	संपूर्ण
2001	3	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम,2001	संपूर्ण
2001	5	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2001	संपूर्ण
2001	7	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2001	संपूर्ण
2001	8	विनियोग अधिनियम, 2001	संपूर्ण
2001	13	विनियोग (रेल) संख्यांक २ अधिनियम, २००१	संपूर्ण
2001	15	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2001	संपूर्ण
2001	42	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2001	संपूर्ण
2002	2	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, २००१	संपूर्ण
2002	3	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, २००१	संपूर्ण
2002	4	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2001	संपूर्ण
2002	6	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	7	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	8	विनियोग अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	9	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	10	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम 2002	संपूर्ण
2002	18	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	19	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	46	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	49	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, २००२	संपूर्ण
2002	67	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	71	विनियोग (संख्यांक 6) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2003	21	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003	22	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003	23	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003	26	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003	27	विनियोग अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003	28	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003	30	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, २००३	संपूर्ण
2003	33	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003	41	विनियोग (संख्यांक 4)अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003	42	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003	55	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2003	संपूर्ण

1	2	3	4
2004	10	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2004	संपूर्ण
2004	11	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2004	संपूर्ण
2004	12	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2004	संपूर्ण
2004	14	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2004	संपूर्ण
2004	15	विनियोग अधिनियम, 2004	संपूर्ण
2004	18	विनियोग (रेल) लेखानुदान संख्यांक 2 अधिनियम, 2004	संपूर्ण
2004	19	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004	संपूर्ण
2004	20	विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 अधिनियम, 2004	संपूर्ण
2004	21	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 2004	संपूर्ण
2004	22	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2004	संपूर्ण
2004	27	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, २००४	संपूर्ण
2005	3	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2004	संपूर्ण
2005	6	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2005	7	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2005	8	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2005	9	विनियोग अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2005	16	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2005	17	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2005	34	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2005	35	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2005	36	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2005	37	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, २००५	संपूर्ण
2005	52	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2005	56	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2006	11	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	12	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	13	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	14	विनियोग अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	15	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	16	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	17	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	36	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	37	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, २००६	संपूर्ण
2006	50	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	53	विनियोग (रेल) संख्यांक 6 अधिनियम, 2006	संपूर्ण

1	2	3	4
2006	55	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	56	विनियोग (संख्यांक 6) अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2007	12	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	13	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	14	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	15	विनियोग अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	20	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	21	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	33	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	34	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	46	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	47	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	48	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, २००७	संपूर्ण
2008	1	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2008	2	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2008	3	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2008	5	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2008	6	विनियोग अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2008	16	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2008	17	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2008	20	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2008	21	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, २००८	संपूर्ण
2008	31	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2008	32	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2009	13	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2009	संपूर्ण
2009	14	विनियोग (रेल) संख्यांक २ अधिनियम, २००९	संपूर्ण
2009	15	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2009	संपूर्ण
2009	16	विनियोग (लेखानुदान)अधिनियम, 2009	संपूर्ण
2009	17	विनियोग अधिनियम, 2009	संपूर्ण
2009	29	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 2009	संपूर्ण
2009	30	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009	संपूर्ण
2009	32	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2009	संपूर्ण
2009	42	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2009	संपूर्ण
2009	44	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, 2009	संपूर्ण
2010	5	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2010	संपूर्ण

1	2	3	4
2010	6	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	7	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	8	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	9	विनियोग अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	11	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	12	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	13	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	21	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	29	विनियोग (रेल) संख्यांक ४ अधिनियम, २०१०	संपूर्ण
2010	44	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	45	विनियोग (संख्यांक 6) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	46	विनियोग (रेल) संख्यांक 5 अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	47	विनियोग (रेल) संख्यांक 6 अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2011	1	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2011	2	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2011	3	विनियोग अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2011	4	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2011	9	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2011	19	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2012	7	विनियोग (रेल) संख्यांक ३ अधिनियम, २०११	संपूर्ण
2012	14	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2012	संपूर्ण
2012	15	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2012	संपूर्ण
2012	16	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2012	संपूर्ण
2012	17	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2012	संपूर्ण
2012	18	विनियोग अधिनियम, 2012	संपूर्ण
2012	19	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2012	संपूर्ण
2012	21	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 2012	संपूर्ण
2012	22	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2012	संपूर्ण
2012	40	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2012	संपूर्ण

निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 23)

[6 मई, 2016]

कितपय अधिनियमितियों का निरसन और कितपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 है।

संक्षिप्त नाम।

2. पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को इसके द्वारा उसके चौथे स्तंभ में वर्णित विस्तार तक निरसित किया जाता है।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन। कतिपय अधिनियमितियों

का संशोधन।

व्यावृत्ति।

- 3. दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनिमितियों को इसके द्वारा उसके चौथे स्तंभ में वर्णित विस्तार तक तथा रीति से संशोधित किया जाता है।
- 4. किसी अधिनियमिति का इस अधिनियम द्वारा निरसन किया जाना, किसी अन्य ऐसी अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, सम्मिलत या निर्दिष्ट किया गया है;

और इस अधिनियम का प्रभाव, पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उद्भूत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा उसके विषय में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व दावे या मांग से कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले से अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर नहीं पड़ेगा;

और न ही, इस अधिनियम का प्रभाव विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धित, या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, विशेषाधिकार, निर्वंधन, छूट, पद या नियुक्ति पर नहीं पड़ेगा भले ही वह, यथास्थिति, इसके द्वारा निरिसत किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे किसी रीति से पुष्ट, मान्य या व्युत्पन्न क्यों न हो;

और न ही, इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के, जो अब विद्यमान या प्रवत्तृ नहीं है, निरसन से कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धित, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात पुनरुज्जीवित या प्रत्यावर्तित होगी।

पहली अनुसूची (धारा 2 देखिए)

निरसन

वर्ष	संख्यांक	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
1	2	3	4
1863	16	उत्पाद-शुल्क (स्पिरिट) अधिनियम, 1863	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है
1874	4	विदेशी भर्ती अधिनियम, 1874	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है
1875	18	भारतीय निर्णय पत्रिका अधिनियम, 1875	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है
1879	6	हाथी परिरक्षण अधिनियम, 1879	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है
1890	13	उत्पाद-शुल्क (माल्ट लिकर) अधिनियम, 1890	संपूर्ण
1898	3	कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898	संपूर्ण
1902	4	भारतीय ट्राम अधिनियम, 1902	संपूर्ण
1912	8	वन्य पक्षी और जीव-जन्तु संरक्षण अधिनियम, 1912	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है
913	6	मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम, 1913	संपूर्ण
916	7	भारतीय चिकित्सा उपाधि अधिनियम, 1916	संपूर्ण
919	1	स्थानीय प्राधिकरण, पेंशन और उपदान अधिनियम, 1919	संपूर्ण
930	32	मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम, 1930	संपूर्ण
933	2	बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम, 1933	संपूर्ण
936	18	रेड क्रास सोसाइटी (संपत्ति का आबंटन) अधिनियम, 1936	संपूर्ण
936	22	भारतीय कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1936	संपूर्ण
938	24	नियोजक-दायित्व अधिनियम, 1938	संपूर्ण
940	12	आय-कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1940	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है
941	22	भारतीय वणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1941	संपूर्ण
941	23	भारतीय आय-कर (संशोधन) अधिनियम, 1941	संपूर्ण
941	24	आधिक्य लाभ कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1941	संपूर्ण
941	25	रेल (स्थानीय प्राधिकारी कर) अधिनियम, 1941	संपूर्ण
947	44	आय-कर और कारबार लाभ कर (संशोधन) अधिनियम, 1947	संपूर्ण
947	45	भारतीय व्यापार संघ (संशोधन) अधिनियम, 1947	संपूर्ण
948	38	विधिक कार्यवाहियों का चालू रह जाना अधिनियम, 1948	संपूर्ण
948	48	आय-कर और कारबार लाभ कर (संशोधन) अधिनियम, 1948	संपूर्ण
948	58	बंदी आदान-प्रदान अधिनियम, 1948	संपूर्ण
948	60	विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948	संपूर्ण
949	24	दिल्ली होटल (आवासन का नियंत्रण) अधिनियम, 1949	संपूर्ण
949	53	भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1949	संपूर्ण
949	59	विलयित राज्य (विधियां) अधिनियम, 1949	संपूर्ण

1	2	3	4
1950	9	भारतीय चाय नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1950	संपूर्ण
1950	26	ओषधि (नियंत्रण) अधिनियम, 1950	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है
1950	52	अनिवार्य प्रदाय (अस्थायी शक्तियां) संशोधन अधिनियम, 1950	संपूर्ण
1950	71	भारतीय आय-कर (संशोधन) अधिनियम, 1950	संपूर्ण
1950	72	अनिवार्य प्रदाय (अस्थायी शक्तियां) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1950	संपूर्ण
1951	42	भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1951	संपूर्ण
1951	59	दिल्ली परिसर (अध्यपेक्षा और बेदखली) संशोधन अधिनियम, 1951	संपूर्ण
952	9	भारतीय स्वतंत्रता पाकिस्तान न्यायालय (लंबित कार्यवाहियां) अधिनियम, 1952	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है
952	49	भारतीय चाय नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1952	संपूर्ण
1952	54	केंद्रीय चाय बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1952	संपूर्ण
953	23	भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1953	संपूर्ण
1953	25	भारतीय आय-कर (संशोधन) अधिनियम, 1953	संपूर्ण
1953	54	भारतीय रिजर्व बेंक (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1953	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है
1954	9	पोत परिवहन नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1954	संपूर्ण
954	13	प्रेस (आक्षेपणीय सामग्री) संशोधन अधिनियम, 1954	संपूर्ण
1954	23	संघ प्रायोजनार्थ भूमियों का राजकीय अर्जन (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1954	संपूर्ण
1954	33	भारतीय आय-कर (संशोधन) अधिनियम, 1954	संपूर्ण
.954	41	कराधान विधि (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 1954	संपूर्ण
1954	53	निरहिता निवारण (संसद् और भाग ग राज्य विधान-मंडल) दूसरा संशोधन	संपूर्ण
1954	33	अधिनियम, 1954	\\ \&\\
1955	29	औद्योगिक विवाद (अपील अधिकरण) संशोधन अधिनियम, 1955	संपूर्ण
1955	52	निरर्हता निवारण (संसद् और भाग ग राज्य विधान-मंडल) दूसरा संशोधन	संपूर्ण
056	10	अधिनियम, 1955	rint
956	10	पोत परिवहन नियंत्रण (जारी रहना) अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1956	26	भारतीय आय-कर (संशोधन) अधिनियम, 1956 औद्योगिक विवाद (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1956	36		उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है
1956	45	समाचारपत्र (कीमत और पृष्ठ) अधिनियम, 1956	संपूर्ण
956	52	सरकारी परिसर (बेदखली) संशोधन अधिनियम, 1956	संपूर्ण
956	63	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1956	95	बेंककारी कंपनी (संशोधन)अधिनियम, 1956	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है
1957	17	जीवन-बीमा निगम (संशोधन) संशोधन अधिनियम, 1957	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है
1957	47	भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 1957	संपूर्ण

1	2	3	4
1957	53	भारतीय रेल (संशोधन) अधिनियम, 1957	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है
.957	64	निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1957	संपूर्ण
958	9	पोत परिवहन नियंत्रण (जारी रहना) अधिनियम, 1958	संपूर्ण
958	33	संपदा-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1958	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
958	35	मणिपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) अधिनियम, 1958	संपूर्ण
1958	54	निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1958	संपूर्ण
959	1	भारतीय आय-कर (संशोधन) अधिनियम, 1959	संपूर्ण
959	17	कोयला श्रेणीकरण बोर्ड (निरसन) अधिनियम, 1959	संपूर्ण
959	29	सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) अधिनियम, 1959	संपूर्ण
960	16	संपदा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1960	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
960	18	भारतीय बायलर (संशोधन) अधिनियम, 1960	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
960	28	कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1960	संपूर्ण
960	45	भारतीय संग्रहालय (संशोधन) अधिनियम, 1960	संपूर्ण
960	54	रेल यात्री किराया (संशोधन) अधिनियम, 1960	संपूर्ण
960	65	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1961	7	बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1961	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
961	36	समाचारपत्र (कीमत और पृष्ठ का जारी रहना) अधिनियम, 1961	संपूर्ण
961	55	चीनी (उत्पादन विनियमन) अधिनियम, 1961	संपूर्ण
962	17	वायु निगम (संशोधन) अधिनियम, 1962	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
962	43	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1962	संपूर्ण
962	56	राज्य सहयुक्त बैंक (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1962	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
962	59	वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) अधिनियम, 1962	संपूर्ण
963	21	अनिवार्य निक्षेप स्कीम अधिनियम, 1963	संपूर्ण
963	37	वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1963	संपूर्ण
963	53	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1963	संपूर्ण
964	32	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1964	संपूर्ण
.965	23	बेंककारी विधि (सहकारी सोसाइटी को लागू होना) अधिनियम, 1965	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1965	31	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1965	संपूर्ण

1	2	3	4
1966	21	वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1966	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1966	30	विद्युत (प्रदाय) संशोधन अधिनियम, 1966	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1966	37	कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1966	संपूर्ण
1967	14	आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1967	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1967	25	बाट और माप मानक (कोहिमा और मोकाक चांग जिलों पर विस्तारण) अधिनियम, 1967	संपूर्ण
1968	60	राज्य कृषि उधार निगम अधिनियम, 1968	संपूर्ण
1969	17	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1969	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1969	22	बैंककारी कंपनी (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1969	संपूर्ण
1969	23	कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1969	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1969	28	केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1969	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1969	37	दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1969	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1969	38	वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1969	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1970	24	पेट्रोलियम (संशोधन) अधिनियम, 1970	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1970	25	वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1970	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1970	51	केन्द्रीय श्रम विधि (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 1970	संपूर्ण
1971	63	जयंती शिपिंग कंपनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1971	64	कोककारी कोयला खान (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971	संपूर्ण
1972	58	इंडियन कापर कारपोरेशन (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1972	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1972	72	रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1972	संपूर्ण
1973	15	कोयला खान (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1973	62	कोंकण यात्री पोत (अर्जन) अधिनियम, 1973	संपूर्ण
1974	4	एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1974	संपूर्ण
1974	37	अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974	संपूर्ण
1976	2	बर्मा शैल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	97	बर्न कंपनी और इंडियन स्टैण्डर्ड वैगन कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1976	98	लक्ष्मीरत्नम एंड एथरटन वेस्ट काटन मिल्स (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1976	संपूर्ण

1	2	3	4
1976	106	अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1976	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
.977	17	काल्टेक्स [काल्टेक्स आइल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों तथा काल्टेक्स (इंडिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] अधिनियम, 1977	संपूर्ण
1978	21	निक्षेप बीमा निगम (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1978	संपूर्ण
979	28	कोसन गैस कंपनी (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1979	संपूर्ण
980	64	मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980	संपूर्ण
981	18	आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981	संपूर्ण
1981	19	चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) अधिनियम, 1981	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
.981	41	बर्मा आइल कंपनी [आइल इंडिया लिमिटेड के शेयरों तथा असम आइल कंपनी लिमिटेड और बर्मा आइल कंपनी (इंडिया ट्रेडिंग) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] अधिनियम, 1981	संपूर्ण
1982	26	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1982	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1982	31	संपदा शुल्क अधिनियम, 1982	संपूर्ण
982	38	मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1982	संपूर्ण
982	50	अमृतसर आयल वर्क्स (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1982	संपूर्ण
982	58	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1982	संपूर्ण
.982	68	ओषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 1982	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1983	29	राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983	संपूर्ण
983	40	कपड़ा उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1983	संपूर्ण
1983	44	भारतीय रेल (संशोधन) अधिनियम, 1983	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
984	1	बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983	संपूर्ण
.984	16	गणेश फ्लोर मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1984	संपूर्ण
1984	26	उपदान संदाय (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1984	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
984	33	मुगल लाइन लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1984	संपूर्ण
984	34	आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1984	संपूर्ण
984	38	दिल्ली विकास (संशोधन) अधिनियम, 1984	संपूर्ण
984	45	कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1984	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
984	53	संपदा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1984	संपूर्ण

1	2	3	4
1984	54	लेवी चीनी समान कीमत निधि (संशोधन) अधिनियम, 1984	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1984	59	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1984	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1984	63	दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1984	संपूर्ण
1984	67	कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1984	संपूर्ण
1985	3	साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1985	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1985	83	फतुहा–इस्लामपुर लाइट रेल लाइन (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1985	संपूर्ण
1986	33	वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1986	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1986	66	पोत परिवहन विकास निधि समिति (उत्सादन) अधिनियम, 1986	संपूर्ण
1987	27	राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987	संपूर्ण
1987	43	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1987	संपूर्ण
1989	3	प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989	संपूर्ण
1989	29	कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1989	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1991	2	कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1991	संपूर्ण (धारा 6 के सिवाय)
1991	34	उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1991	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1991	44	वन्य जीव (संशोधन) अधिनियम, 1991	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1991	60	दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1991	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1993	49	बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1993	उतना भाग, जितना निरसित नहीं किया गया है।
1994	27	पंजाब ग्राम पंचायत, समिति और जिला परिषद् (चंडीगढ़) अधिनियम, 1994	संपूर्ण
1999	2	कपास ओटाई (निरसन) अधिनियम, 1998	संपूर्ण
1999	4	रेल दावा अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1998	संपूर्ण
999	11	आय-कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1998	संपूर्ण
999	21	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999	संपूर्ण
999	28	आय-कर (संशोधन) अधिनियम, 1999	संपूर्ण
999	38	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1999	संपूर्ण
2000	2	भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	19	सूती वस्त्र उपकर (निरसन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण

1	2	3	4
2000	24	भारतीय कंपनी (विदेशी हित) और कंपनी (लाभांशों पर अस्थायी	संपूर्ण
		निर्बंधन) निरसन अधिनियम, 2000	
2000	25	सूती कपड़ा (निरसन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	26	लौह और इस्पात कंपनी (समामेलन और प्रबंध-ग्रहण विधि) निरसन	संपूर्ण
		अधिनियम, 2000	
2000	27	मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	31	सेना और वायुसेना (प्राइवेट संपत्ति का व्ययन) संशोधन	संपूर्ण
		अधिनियम, 2000	
2000	32	भारतीय पावर ऐल्कोहल (निरसन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	33	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	36	केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) संशोधन अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	38	भारतीय पुनर्वास परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	46	कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	47	पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	51	वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	53	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2001	1	कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण (धारा 5 के सिवाय)
2001	4	कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2001	संपूर्ण (धारा ८ के सिवाय)
2001	11	बीमा विधि (कारबार का अंतरण और आपात उपबंध) निरसन	संपूर्ण
		अधिनियम, 2001	
001	17	उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) निरसन अधिनियम, 2001	संपूर्ण
2001	18	स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़	संपूर्ण
		(संशोधन) अधिनियम, 2001	
2001	20	बैंककारी कंपनी (विधि व्यवसायियों के मुविक्कलों के खाते) निरसन	संपूर्ण
		अधिनियम, 2001	
2001	21	विद्युत विनियामक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001	संपूर्ण
2001	28	पशुधन आयात (संशोधन) अधिनियम, 2001	संपूर्ण
2001	31	व्यापार संघ (संशोधन) अधिनियम, 2001	संपूर्ण
001	32	प्रसव पूर्व निदान–तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन	संपूर्ण
		अधिनियम, 2001	
2001	34	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2001	संपूर्ण
2001	35	गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) निरसन अधिनियम, 2001	संपूर्ण
001	44	मंत्रियों के संबलम और भत्ते से संबंधित (संशोधन) अधिनियम, 2001	संपूर्ण

2001 55 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 2001 56 सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2001 2001 57 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2001 2002 13 जूट विनिर्मित उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 17 पासपोर्ट (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 24 भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 25 संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 32 संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 44 तटरक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 45 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 50 पेट्रोलियम (बरार में विस्तार) निरसन अधिनियम, 2002 2002 61 संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 63 वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 64 गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 1 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 14 प्रसवपूर्व निदान–तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2003 2003 16 वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण संपूर्ण
2001 57 कंपनी (संशोधन) अधिनयम, 2001 2002 13 जूट विनिर्मित उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 17 पासपोर्ट (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 24 भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 25 संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 32 संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 44 तट्यक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 45 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 50 पेट्रोलियम (बरार में विस्तार) निरसन अधिनियम, 2002 2002 61 संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 63 वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 64 गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 1 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 14 प्रसवपूर्व निदान–तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2003 2003 16 वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2002 13 जूट विनिर्मित उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 17 पासपोर्ट (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 24 भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 25 संविधान (अनुसूचित जाितयां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 32 संविधान (अनुसूचित जाितयां) और अनुसूचित जनजाितयां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 44 तटरक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 45 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 50 पेट्रोलियम (बरार में विस्तार) निरसन अधिनियम, 2002 2002 61 संविधान (अनुसूचित जाितयां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 63 वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 1 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 1 प्रसवपूर्व निदान–तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2003 2003 16 वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2003	
2002 17 पासपोर्ट (संशोधन) अिधनियम, 2002 2002 24 भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अिधनियम, 2002 2002 25 संविधान (अनुसूचित जाितयां) आदेश (संशोधन) अिधनियम, 2002 2002 32 संविधान (अनुसूचित जाितयां) और अनुसूचित जनजाितयां) आदेश (दूसरा संशोधन) अिधनियम, 2002 2002 44 तटरक्षक (संशोधन) अिधनियम, 2002 2002 45 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) अिधनियम, 2002 2002 50 पेट्रोलियम (बरार में विस्तार) निरसन अिधनियम, 2002 2002 61 संविधान (अनुसूचित जाितयां) आदेश (दूसरा संशोधन) अिधनियम, 2002 2002 63 वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अिधनियम, 2002 2002 64 गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अिधनियम, 2002 2003 1 कंपनी (संशोधन) अिधनियम, 2002 2003 14 प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अिधनियम, 2003 2003 16 वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) अिधनियम, 2003	संपूर्ण
2002 24 भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अिधनियम, 2002 2002 25 संविधान (अनुसूचित जाितयां) आदेश (संशोधन) अिधनियम, 2002 2002 32 संविधान (अनुसूचित जाितयां और अनुसूचित जनजाितयां) आदेश (दूसरा संशोधन) अिधनियम, 2002 2002 44 तटरक्षक (संशोधन) अिधनियम, 2002 2002 45 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) अिधनियम, 2002 2002 50 पेट्रोलियम (बरार में विस्तार) निरसन अिधनियम, 2002 2002 61 संविधान (अनुसूचित जाितयां) आदेश (दूसरा संशोधन) अिधनियम, 2002 2002 63 वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अिधनियम, 2002 2002 64 गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अिधनियम, 2002 2003 1 कंपनी (संशोधन) अिधनियम, 2002 2003 14 प्रसवपूर्व निदान–तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अिधनियम, 2003 2003 16 वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) अिधनियम, 2003	संपूर्ण
2002 25 संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 32 संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 44 तटरक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 45 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 50 पेट्रोलियम (बरार में विस्तार) निरसन अधिनियम, 2002 2002 61 संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 63 वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 64 गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 1 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 14 प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2003 2003 16 वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2002 32 संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 44 तटरक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 45 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 50 पेट्रोलियम (बरार में विस्तार) निरसन अधिनियम, 2002 2002 61 संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 63 वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 64 गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 1 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 14 प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2003 2003 16 वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 44 तटरक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 45 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 50 पेट्रोलियम (बरार में विस्तार) निरसन अधिनियम, 2002 2002 61 संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 63 वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 64 गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 1 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 14 प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2003 2003 16 वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2002 44 तटरक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 45 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 50 पेट्रोलियम (बरार में विस्तार) निरसन अधिनियम, 2002 2002 61 संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 63 वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 64 गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 1 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 14 प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2003 2003 16 वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2002 45 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 50 पेट्रोलियम (बरार में विस्तार) निरसन अधिनियम, 2002 2002 61 संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 63 वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 64 गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 1 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 14 प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2003 2003 16 वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2003	
2002 50 पेट्रोलियम (बरार में विस्तार) निरसन अधिनियम, 2002 2002 61 संविधान (अनुसूचित जाितयां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 63 वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 64 गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 1 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 14 प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2003 2003 16 वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2002 61 संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 63 वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 64 गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 1 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 14 प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2003 2003 16 वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2002 63 वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2002 64 गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 1 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 14 प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2003 2003 16 वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2002 64 गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 1 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 14 प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2003 2003 16 वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003 1 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 2003 14 प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2003 2003 16 वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003 14 प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2003 2003 16 वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
अधिनियम, 2003 2003 16 वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003 16 वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2002 10	संपूर्ण
2003 19 जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003 29 बैंक सेवा आयोग (निरसन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003 38 शिशु दुग्ध अनुकल्प पोषण बोतल और शिशुखाद्य (उत्पादन, प्रदाय और	संपूर्ण
वितरण विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2003	
2003 43 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003 47 संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003 52 रेल संरक्षण बल (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003 54 कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003 56 रेल (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003 57 विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2004 5 विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2004 8 भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2004 25 सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (निरसन) अधिनियम, 2004	संपूर्ण
2005 15 पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2005 23 नौसेना संशोधन अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2005 41 मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2005	संपूर्ण

1	2	3	4
2005	47	रेल (संशोधन) अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2005	55	कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2006	7	लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	8	कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	9	चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	23	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	33	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	39	वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	42	केंद्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	48	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	57	भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2007	4	बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2007	25	केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	26	विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	31	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	36	शिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	38	सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	42	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान	संपूर्ण
		शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2007	
2007	44	वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	45	बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	49	भारतीय बायलर (संशोधन) अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2008	11	रेल (संशोधन) अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2008	12	प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2008	13	खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2008	14	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2008	15	प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2008	26	औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2009	2	संविधान (अनुसूचित जातियां) संघ राज्यक्षेत्र आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2009	3	स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2009	10	सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008	संपूर्ण

1	2	3	4
2009	28	विमान वहन (संशोधन) अधिनियम, 2009	संपूर्ण
2009	34	मेट्रो रेल (संशोधन) अधिनियम, 2009	संपूर्ण
2009	45	कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2009	संपूर्ण
2009	46	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) अधिनियम, 2009	संपूर्ण
2009	47	उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2009	संपूर्ण
2010	2	मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अधिनियम, 2009	संपूर्ण
2010	15	उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	17	बागान श्रम (संशोधन) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	18	कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	24	औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	25	विदेश व्यापार (विकास ओर विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	26	प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	28	ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	32	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	34	खान और खनिज (विकास ओर विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	35	आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2011	10	जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (संशोधन) अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2011	12	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2011	13	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2011	18	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2011	21	केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2012	1	दामोदर घाटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2012	2	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2012	संपूर्ण
2012	3	चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2012	4	कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2012	6	प्रसार भारतीय (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2012	9	पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि उपयोग के अधिकार का	संपूर्ण
		अर्जन) संशोधन अधिनियम, 2011	
2012	10	लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2012	20	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2012	संपूर्ण
2012	24	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2012	संपूर्ण
2012	25	रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) संशोधन अधिनियम, 2012	संपूर्ण
2012	30	नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012	संपूर्ण
		अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012	संपूर्ण

1	2	3	4	
2013	2	धन-शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012	संपूर्ण	
2013	3	विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2012	संपूर्ण	
2013	13	दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013	संपूर्ण	
2013	19	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013	संपूर्ण	
2013	22	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2013	संपूर्ण	
2013	24	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2013	संपूर्ण	
2013	29	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) संशोधन अधिनियम, 2013	धारा 2 और धारा 3	

दूसरी अनुसूची (धारा 3 देखिए)

संशोधन

वर्ष	संख्यांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
2013	14	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013	धारा 6, धारा 7 और धारा 24 में,— (i) ''स्थानीय परिवाद सिमिति''शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, ''स्थानीय सिमिति'' शब्द रखे जाएंगे;
			(ii) ''आंतरिक परिवाद सिमिति'' शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, ''आंतरिक सिमिति'' शब्द रखे जाएंगे।
2014	8	राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन अधिनियम, 2014	धारा 2 में,— (i) ''की धारा 2 के'' शब्दों और अंक के स्थान पर, ''की धारा 2 में,'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;
			(ii) ''(जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2'' कोष्ठकों, शब्दों और अंक के स्थान पर, ''की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 25)

[6 मई, 2016]

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन संक्षिप्त नाम। अधिनियम, 2017 है।

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल धारा ३ का अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:— संशोधन।

'(क) ''पट्यधीन क्षेत्र'' से खनन पट्य में विनिर्दिष्ट ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके भीतर खनन संक्रियाएं की जा सकती हैं और इसके अंतर्गत खंड (झ) में यथा निर्दिष्ट खान की परिभाषा के अधीन आने वाले क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित और अनुमोदित गैर-खनिज क्षेत्र भी है;

(कक) ''खिनजों'' के अंतर्गत खिनज तेलों के सिवाय सभी खिनज आते हैं;'।

धारा 12क का संशोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (6) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'परंतु जहां खनन पट्टा नीलामी से भिन्न माध्यम से अनुदत्त की गई है और जहां ऐसे खनन पट्टे से खिनजों का, आबद्ध प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, वहां ऐसे खनन पट्टों को, ऐसे निबंधनों और शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन और ऐसी रकम या अंतरण प्रभारों के संदाय पर, जो विहित किए जाएं, अंतरित किए जाने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए ''आबद्ध प्रयोजन के लिए उपयोग'' पद से पट्टेदार के स्वामित्वाधीन किसी विनिर्माण इकाई में खनन पट्टे से निकाले गए खनिज की संपूर्ण मात्रा का उपयोग अभिप्रेत है।'।

धारा 13 का संशोधन। 4. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में खंड (थथञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(थथञक) धारा 12क की उपधारा (6) के परंतुक के अधीन निबंधन और शर्तें तथा रकम या अंतरण प्रभार।''।

भारतीय न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 34)

[26 जुलाई, 2016]

भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

संक्षिप्त नाम ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 20 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

'20. जहां न्यास संपत्ति धन हो और न्यास के प्रयोजनों के लिए उसका उपयोजन तुरन्त या नजदीकी तारीख पर न किया जा सके, वहां न्यासी, न्यास की लिखत में अंतर्विष्ट किसी निदेश के अध्यधीन रहते हुए, उस धन को न्यास की लिखत द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के वर्ग में या केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में विनिहित करेगा:

न्यास-धन का विनिधान।

परंतु जहां कोई व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम हो और न्यास-संपत्ति की आय को अपने जीवनपर्यन्त या किसी वृहत्तर संपदार्थ प्राप्त करने का हकदार हो, वहां ऊपर उल्लिखित किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के वर्ग में कोई विनिधान उसकी लिखित सहमित के बिना नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''प्रतिभूति'' पद का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा (2) के खंड (ज) में है।'।

1956 का 42

धारा 20क का संशोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (1) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।

लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 37)

[29 जुलाई, 2016]

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2016 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 16 जनवरी, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2014 का 1

2. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 44 का के प्रारंभ की तारीख से ही धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी और रखी गई समझी जाएगी, संशोधन। अर्थात्:—

''44. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही प्रत्येक लोक सेवक, अपनी आस्तियों और आस्तियों की दायित्वों की ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, घोषणा करेगा।''।

धारा 59 का संशोधन। 3. मूल अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

''(ट) धारा 44 के अधीन लोक सेवकों द्वारा आस्तियों और दायित्वों की घोषणा का प्ररूप और रीति:

परंतु इस खंड के अधीन नियम, भूतलक्षी रूप से उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त हुए थे, बनाए जा सकेंगे;''।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 39)

[4 अगस्त, 2016]

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 है। संक्षिप्त नाम और

प्रारंभ।

(2) यह 24 मई, 2016 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1956 का 102

2. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा नई धारा 10घ का गया है) की धारा 10ग के पश्चात् निम्निलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— अंतःस्थापन।

''10घ. स्नातक पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर सभी आयुर्विज्ञान शैक्षिक संस्थाओं के लिए ऐसे अभिहित प्राधिकारी के माध्यम से हिन्दी, अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक समान प्रवेश परीक्षा संचालित की जाएगी तथा अभिहित प्राधिकारी पूर्वोक्त रीति में समान प्रवेश परीक्षा का संचालन सुनिश्चित करेगा:

स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर स्तर के लिए समान प्रवेश परीक्षा। परंतु किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के होते हुए भी, इस धारा के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार संचालित शैक्षणिक वर्ष 2016–17 के लिए स्नातक पूर्व स्तर पर समान प्रवेश परीक्षा के संबंध में राज्य सरकार के स्थानों की बाबत (चाहे वह सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में हो या प्राइवेट आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में), जहां ऐसे राज्य ने ऐसी परीक्षा का विकल्प नहीं दिया है, लागू नहीं होंगे।"।

धारा 33 का संशोधन। 3. मूल अधिनियम, की धारा 33 में, खंड (डक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(डख) स्नातक पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर सभी आयुर्विज्ञान शैक्षिक संस्थाओं में समान प्रवेश परीक्षा के संचालन के लिए अभिहित प्राधिकारी, अन्य भाषाएं और रीति;''।

निरसन और व्यावृत्ति। 4. (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2016 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

2016 का अध्यादेश सं॰ 4

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त 1956 का 102 अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 41)

[9 अगस्त, 2016]

प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

संक्षिप्त नाम, और प्रारंभ।

धारा 2 का

- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. प्रौद्योगिको संस्थान अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, ''और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (काशी हिंदू विश्वविद्यालय), वाराणसी'' शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर ''इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (काशी हिंदू विश्वविद्यालय), वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, तिरुपति, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, पलक्कड़, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, गोवा, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, धारवाड़, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, भिलाई, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, जम्मू और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद'' शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

धारा 3 का संशोधन।

- 3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—
- (अ) खंड (ग) के उपखंड (xiii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:—
 - "(xiv) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, तिरुपित नामक सोसाइटी के संबंध में, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, तिरुपित;
 - "(xv) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, पलक्कड़ नामक सोसाइटी के संबंध में, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, पलक्कड़;
 - ''(xvi) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, गोवा नामक सोसाइटी के संबंध में, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, गोवा;
 - "(xvii) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, धारवाड़ नामक सोसाइटी के संबंध में, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, धारवाड़;
 - ''(xviii) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, भिलाई नामक सोसाइटी के संबंध में, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, भिलाई;
 - ''(xix) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, जम्मू नामक सोसाइटी के संबंध में, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, जम्मू;
 - ''(xx) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद नामक सोसाइटी के संबंध में, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद।'':
 - (आ) खंड (छक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 - '(छख) ''इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद'' से इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद सोसाइटी अभिप्रेत है;'';
- (इ) खंड (ञ) के उपखंड (xi) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:—
 - ''(xii) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, तिरुपति;
 - (xiii) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, पलक्कड़;
 - (xiv) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, गोवा;
 - (xv) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, धारवाड;
 - (xvi) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, भिलाई;
 - (xvii) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, जम्मू;
 - (xviii) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ माइन्स, धनबाद;"।

धारा 4 का संशोधन।

- 4. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:—
 - ''(1ङ) ऐसे निगमन पर, इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद को इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद कहा जाएगा।''।

धारा 5 का संशोधन।

- 5. मूल अधिनियम की धारा 5 में, स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—
 - "स्पष्टीकरण 3—इस धारा में, इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का इंडियन इंस्टीट्यूट

आफ टेक्नालाजी, तिरुपित, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, पलक्कड़, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, गोवा, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, धारवाड़, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, फिलाई, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, जम्मू, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस तारीख के प्रति निर्देश है, जिसको प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं।''।

6. मूल अधिनियम की धारा 38 में,—

(i) खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

धारा 38 का संशोधन।

- "(त) जब तक इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, तिरुपित, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, पलक्कड़, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, गोवा, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, धारवाड़, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, भिलाई, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, जम्मू के प्रथम परिनियम और अध्यादेश इस अधिनियम के अधीन नहीं बनाए जाते हैं, जब तक प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ से ठीक पहले यथा प्रवृत्त ऐसे संस्थानों के परिनियम और अध्यादेश आवश्यक उपांतरणों और अनुकूलनों सिहत उन संस्थानों को उस विस्तार तक लागू होंगे, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत नहीं हैं;
- (थ) प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ से ठीक पहले कार्य करने वाले इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के नियमों के नियम 7 और विनियमों में निर्दिष्ट कार्यकारी बोर्ड उसी रूप में तब तक कार्य करता रहेगा, जब तक इस अधिनियम के अधीन इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद के लिए किसी नए बोर्ड का गठन नहीं कर दिया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नए बोर्ड के गठन पर इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद का कार्यकारी बोर्ड, जहां तक उसका संबंध इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद से है, कार्य नहीं करेगा;
- (द) प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ से ठीक पहले कार्य करने वाली इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के नियमों के नियम 9 और विनियमों में निर्दिष्ट विद्या पिरषद् उस रूप में तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक इस अधिनियम के अधीन इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद के लिए किसी नई सीनेट का गठन नहीं कर दिया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नई सीनेट के गठन पर इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद की विद्या पिरषद्, जहां तक उसका संबंध इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद से है, कार्य नहीं करेगी;
- (ध) जब तक इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद के संबंध में प्रथम परिनियम और अध्यादेश, इस अधिनियम के अधीन नहीं बनाए जाते हैं, तब तक ऐसे परिनियम और अध्यादेश, जो प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम 2016 के प्रारंभ से ठीक पहले इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, रुड़की को लागू होते हैं, आवश्यक उपांतरणों और अनुकूलनों सहित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद को उस विस्तार तक लागू होंगे, जहां तक वे इस अधिनियम के उपवंधों के असंगत नहीं हैं;
- (न) प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे छात्र के बारे में, जिसने शैक्षणिक सत्र 2015–2016 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद की कक्षाओं में जाना प्रारंभ कर दिया है या जिसने शैक्षणिक सत्र 2015–2016 में या उसके पश्चात् पाठ्यक्रम पूरा किया है, धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद में अध्ययन पाठ्यक्रम किया गया समझा जाएगा, परंतु यह तब जब, ऐसे छात्र को उसी अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए पहले ही डिग्री या डिप्लोमा प्रदान नहीं कर दिया गया है;
- (प) यदि प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर

सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु इस खंड के अधीन कोई आदेश प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि इस खंड के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।'';

(ii) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण 4—इस धारा के खंड (थ), खंड (द) और खंड (ध) में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस तारीख के प्रति निर्देश है, जिसको प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं।"।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 42)

[9 अगस्त, 2016]

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संक्षिप्त नाम, और (संशोधन) अधिनियम, 2016 है। प्रारंभ।
 - (2) यह 20 अगस्त, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2007 के अधिनियम सं॰ 29 की पहली अनुसूची का संशोधन। 2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 की पहली अनुसूची में, क्रम सं॰ 30 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं॰ और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

 $(1) \qquad \qquad (2)$

''31. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश।''।

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 45)

[19 अगस्त, 2016]

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

संक्षिप्त नाम।

- 2. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया धारा 2 का संशोधन। है) की धारा 2 के खंड (ठ) में, ''मिजोरम,'' शब्द के पश्चात् ''नागालेंड,'' शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा।
- 3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में, ''मिजोरम,'' शब्द के पश्चात् ''नागालैंड,'' शब्द धारा 6 का संशोधन। अंत:स्थापित किया जाएगा।

कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 47)

[8 सितम्बर, 2016]

आय-कर अधिनियम, 1961 और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह, इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, तुरंत प्रवृत्त होगा।

अध्याय 2

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

1961 का 43

2. आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 का संशोधन। धारा 2 के खंड (19कक) में, स्पष्टीकरण 4 के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2017 से निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण 5—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसी कंपनी की, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसके शेयरों का पृथक् कंपनियों में अंतरण के परिणामस्वरूप पिल्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही है, पुनर्संरचना या विभाजन को निर्विलयन समझा जाएगा, यदि ऐसी पुनर्संरचना या विभाजन शेयरों के उक्त अंतरण से संलग्न किसी शर्त को प्रभावी करने के लिए किया गया है और वह ऐसी अन्य शर्तों को भी पूरा करता है जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएं।''।

धारा 80ञञकक का संशोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 80ञ्चकक की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2017 से निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु ऐसे किसी निर्धारिती की दशा में, जो परिधान विनिर्माण के कारबार में लगा हुआ है, उपखंड (ग) के उपबंधों का वही प्रभाव होगा मानो ''दो सौ चालीस दिन'' शब्दों के स्थान पर, ''एक सौ पचास दिन'' शब्द रखे गए हों।'।

अध्याय 3

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क टैरिफ

पहली अनुसूची का संशोधन। 4. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में,

- (क) अध्याय 25 में, टैरिफ मद 2515 11 00, टैरिफ मद 2515 12 10, टैरिफ मद 2515 12 20, टैरिफ मद 2515 12 90, टैरिफ मद 2516 11 00 और टैरिफ मद 2516 12 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में, ''10%'' प्रविष्टि के स्थान पर, क्रमशः ''40%'' प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (ख) अध्याय 68 में, टैरिफ मद 6802 10 00, टैरिफ मद 6802 21 10, टैरिफ मद 6802 21 20, टैरिफ मद 6802 21 90, टैरिफ मद 6802 23 10, टैरिफ मद 6802 23 90, टैरिफ मद 6802 29 00, टैरिफ मद 6802 91 00, टैरिफ मद 6802 92 00 और टैरिफ मद 6802 93 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में, "10%" प्रविध्टि के स्थान पर, क्रमश: "40%" प्रविध्टि रखी जाएगी।

भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, खंड II, संख्यांक 3, दिनांक 9 अक्तूबर, 2013 को प्रकाशित राजपत्र का शुद्धिपत्र:—

पृष्ठ सं॰ धारा पंक्ति के स्थान पर पढ़ें

235-251 में, ''प्रवर्तित'' शब्द, जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर, ''नवीकृत'' शब्द, उसके व्याकरणिक रूपभेदों सहित, पढ़ा जाए।

डॉ॰ जी॰ नारायण राजू, सचिव, भारत सरकार।